43वीं वार्षिक रिपोर्ट
2018-2019

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली

43वीं वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019

मुद्रण एवं प्रकाशन :

सचिव

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

(वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के अध्याधीन एक स्वायत्त
अनुसंधान संस्थान)

18/2, सत्संग विहार मार्ग,
स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू)
नई दिल्ली 110067
दूरभाष: 011 26569303, 26569780, 26569784

फैक्स : 91-11-26852548

ईमेल : nipfp@nipfp.org.in

वेबसाइट: www.nipfp.org.in

सम्पादन एवं डिजाइन : रोहित दत्ता

मुद्रक : हिमांशी इंटरप्राइजेज

ईमेल: prem.adhikari@rediffmail.com

दूरभाष: 011-41034642

विषय सूची

1. **प्रस्तावना**	**1**
2. **अनुसंधान क्रियाकलाप**	**6**
3. **कार्यशालाएं, सेमिनार, बैठकें एवं सम्मेलन**	**17**
4. **प्रशिक्षण कार्यक्रम**	**18**
5. **प्रकाशन एवं संचार**	**19**
6. **पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र**	**20**
7. **संकाय क्रियाकलापों के मुख्य अंश**	**25**
अनुलग्नक	46
I. **अध्ययनों की सूची**	**47**
II. **कार्यशील पेपर श्रृंखला**	**52**
III. **आंतरिक सेमिनार श्रृंखला**	**55**
IV. **शासी निकाय सदस्य**	**56**
V. **मूल्य अंकित प्रकाशनों की सूची**	**61**
VI. **संकाय सदस्यों की प्रकाशित सामग्री**	**66**
VII. **स्टाफ सदस्यों की सूची**	**76**
VIII. **प्रायोजक, कारपोरेट, स्थाई एवं साधारण सदस्य**	**81**
IX. **वित्त एवं लेखा**	**82**

1. प्रस्तावना

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कार्यों तथा शासी निकाय एवं जनता के प्रति अपनी उत्तरदेयता की प्रस्तुति है। यहां आगे के पृष्ठों में वर्ष *2017-18* के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी द्वारा किए गए क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान तथा पूर्व वार्षिक रिपोर्टों की डिजीटल प्रति संस्थान की वेबसाइट http://www.nipfp.org.in/publications/annual-reports/.पर प्राप्त की जा सकती है।

संस्थान का परिचय

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी एक लोक अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान केन्द्र है। वर्ष 1976 में स्थापित यह संस्थान लोक अर्थशास्त्र से सम्बद्ध अनुसंधान, नीति प्रतिपालन एवं क्षमता निर्माण के कार्य कर रहा है। इस संस्थान को सौंपे गए कार्यों में एक प्रमुख कार्य विश्लेषणात्मक आधार उपलब्ध करवाकर लोक नीतियों के निर्माण एवं उनमें सुधार के कार्य में केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय प्रशासन को सहायता प्रदान करना है। इस संस्थान की स्थापना वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, अनेक राज्य सरकारों तथा विख्यात अकादमियों के संयुक्त प्रयासों से एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है।

अपनी स्थापना के 43वें वर्ष में यह संस्थान भारत के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में उभरा है तथा इसके द्वारा सरकार में सभी स्तरों पर नीति सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के क्रियात्मक कार्यों से इसकी निकट सम्बद्धता स्थापित है तथा भारत एवं विदेश में स्थित अन्य अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थानों से भी इसका जुड़ाव बना हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान प्राप्त होने के बावजूद भी अनुसंधान एवं नीति लक्ष्य के कार्यों में एक गैर-सरकारी संस्थान की इसकी छवि बनी हुई है।

शासी निकाय

संस्थान के शासी निकाय द्वारा दिनांक 19 मार्च,2016 को आयोजित अपनी बैठक में आगामी चार वर्षों अर्थात 5 अप्रैल, 2016 से 4 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया था। डा. विजय केलकर शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। श्री सुमित बोस इसके उपाध्यक्ष हैं।

वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व श्री अजय भूषण पांडे, राजस्व सचिव; श्री अतानु चक्रबर्ती, सचिव (आर्थिक कार्य); तथा श्री कृष्णामूर्ति सुब्रमणियम, मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व डा. राजीव रंजन, सलाहकार एवं कार्यालय प्रभारी, आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग द्वारा किया गया है। नीति आयोग का प्रतिनिधित्व सुश्री अन्ना राय, सदस्य द्वारा किया गया है।

प्रायोजक राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व : श्री मुद्ददा रविचन्द्रन, प्रधान वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार ; श्री आई.एस.एन. प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार; तथा श्री पी.ए. सिद्दिकी, सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है।

श्री राकेश झा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा नामित किए गए हैं, श्री बालकृष्ण गोयनका, अध्यक्ष, एसोसिएटिड चेम्बर ऑफ कार्मस एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया से; तथा श्रीर संदीप सोमानी, अध्यक्ष, फिक्की संस्थान से नामित किए गए हैं।
शासी निकाय में तीन विख्यात अर्थशास्त्री डा. शैबल गुप्ता, एशियन डेवलमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआई); डा. ईरोल डिसुजा, प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद तथा डा. सुदिप्तो मंडल शामिल हैं।
सहयोगी संस्थानों से डा. शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर; श्री एस.के. पट्टनायक, महानिदेशक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट

कॉलेज ऑफ इंडिया; तथा सुश्री यामिनी अय्यर, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी, सेंटर फार पालिसी रिसर्च का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। सी.ए. तरूण जे. घिया, परिषद सदस्य, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को शासी निकाय में सहयोजित सदस्यता प्रदान की गई है।

डा. रथिन रॉय, निदेशक पदेन सदस्य सचिव हैं; तथा डा. आर.कविता राव, प्रोफेसर, प्रतिनिधि, एनआईपीएफपी रोटेशन में प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

शासी निकाय के विशेष अतिथि श्री प्रमोद चन्द्र मोदी, अध्यक्ष, सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय तथा प्रणब कुमार दास, अध्यक्ष, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं। (विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है)

निष्पादित एवं जारी परियोजनाएं

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान हमारे अनुसंधान लक्ष्य: कराधान एवं राजस्व, लोक व्यय एवं वित्त प्रबंधन, स्थूल अर्थव्यवस्था स्वरूप सरकारों के मध्य वित्तीय संबंध तथा राज्य योजना एवं विकास के तीन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर रहे दलों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं।

वर्ष के दौरान संस्थान उप-राष्ट्रीय स्तरीय मांग आधारित अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण के प्रयासों में राज्यों को सहयोग प्रदान करने की अपनी व्यवस्तताओं को और अधिक विस्तारित किया गया है। हमने लोक हित मामलों पर विकासशील राष्ट्रों के साथ अपनी साझेदारी के आयाम को भी और विस्तारित किया है। कमीशन आन रेवन्यु एलोकेशन (सीआरए), केन्या तथा फाइनेंशियल एंड फिस्कल कमीशन, (एफएफसी), दक्षिण अफ्रीका के साथ लोक वित्त प्रबंधन, हस्तांतरण एवं सरकारों के मध्य अंतरण इत्यादि के संबंध में करार निर्धारित किए गए हैं। लोक हित एवं मानव विकास से संबंधित हमारे कार्यों से स्वास्थ्य वित्त के क्षेत्र में परिणाम प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रति वित्तीय बाध्यताओं एवं प्रभाव्यता का परीक्षण किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार तथा गुजरात जैसे कुछेक राज्यों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण अनुसंधान दल द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय की रूपरेखा के निर्धारण के लिए उप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजस्व संभाव्यताओं का विश्लेषण किया जा रहा है। हमारे द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं व्यावसायिक आचरण एवं स्वास्थ्य आपातत तथा आपदा जोखिम प्रबंधन के विनियामक फ्रेमवर्क के लिए अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। हमने भारत की तथा यू.के. के संबंध में भी सरकार से निधियन प्राप्त स्वास्थ्य बीमा की विधिक, गुणवत्ता, एवं मॉनीटरिंग के दृष्टिकोण से किया गया तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है।

हमने अपने कार्यों के माध्यम से लिंग बजटिंग एवं लिंग समानता के प्रति अपने योगदान को जारी रखा है। इसके अलावा,एनआईपीएफपीद्वारा अनेक ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों के संबंध में अनेक अध्ययन किए है जिनका समाधान खाद्य मूल्यअस्थिरता, भारत में डेटा का स्थानीकरण, डिजीटलाइजेशन के परिणाामस्वरूप उत्पन्न कर चुनौतियां, प्रवासन से संबंधित वित्तीय दबाव जैसे कड़े नीतिगत अनुसंधान से हो सकता था। हमारे प्रकाशित अध्ययन भारत में सूक्ष्म स्तरीय मूल्य निर्धारण व्यवहार, खाद्य स्फीति, ऋणों एवं न्यूनताओं के प्रति लक्ष्यबद्ध संरचित सूक्ष्म इकोमैट्रिक एप्रोच, एमटीईएफ को अंगीकार करना तथा भारतीय में बहु-परतीय बजट योजना के अनुभव जैसे विविध प्रकार के अनुसंधानों में विस्तारित किया गया है।

हमारे द्वारा राज्य वित्तीयन का कड़ा मॉनीटर करना जारी रखा गया है तथा अब हम राज्य वित्तीयन डेटा बैंक, जो एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा, को डिजीटल बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। राज्य वित्तीयन के संबंध में प्रस्तुत मुद्दों पर आयोजित हमारे वार्षिक सेमानारों में राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय एवं निजी क्षेत्र के अर्थशात्रियों सहित समग्र नीतिगत तंत्रव्यवस्था द्वारा अपनी रूचि दर्शाई गई है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान राज्य वित्तीयन से संबंधित विविध प्रकार के विषयों पर अपने अध्ययन अनुसंधान प्रकाशित किए हैं। अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से हमने अपना काफी कुछ समय पंद्रहवे वित्त आयोग के अनुरोध पर उनके लिए अनुसंधान अध्ययन करने के उद्देश्य से भी समर्पित किया है। हमें यह उल्लेख करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से आर्थिक संघवाद के सेमिनार तथा द इंस्टीट्यूट

ऑफ न्यू इकॉनिमिक थिंकिंग (आईएनईटी) के सहयोग से तीसरे विधि आर्थिक नीति सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्पूर्ण भारत तथा अन्य सेवाओं के कनिष्ठ एवं मध्यम स्तरीय अधिकारियों सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा लोक वित्तीयन के सामयिक विषयों की प्रारंभिक जानकारी दिए जाने पर ध्यान दिया जाना जारी रखा गया है। वर्ष के दौरान हमारे द्वारा विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के लिए आयोजित किए जाने वाले लोक अर्थशास्त्र के पुनश्चर्या कार्यक्रम की समीक्षा की गई है।

संस्थान द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान नीतिगत ध्यान आकर्षण की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्रों में अपना योगदान दिया जाना जारी रखा गया है: वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं सम्पन्न की गई हैं – क्या मौद्रिक नीति से भारत में वित्तीय स्थिरता उत्पन्न हो सकती है; दक्षिण एशिया में वित्तीय वैश्वीकरण एवं आर्थिक विकास: एक प्रयोगसिद्ध अध्ययन; भारतीय कारपोरेट सेक्टर में क्रेडिट दबाव का मूल्यांकन;डिजिटल आब्जेक्ट आर्किटैकचर के संबंध में नीतिगत इनपुट ; भारत में आर्थिक विकास के पूर्वानुमान : समय परिवर्तित मापदंडों पर रिग्रेशन एप्रोच; प्रधान मंत्री आवास योजना ' ग्रामीण के शासी मापदंडों का मूल्यांकन' राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की पुन:संरचना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अनुसंधान एवं परामर्शी सेवाएं;ट्राई-एनआईपीएफपीअनुसंधान का कार्यान्वयन; डेटा संरक्षण नीतियों के प्रति सहमत रूपरेखा का डिजाइन; सरकारी स्कूल व्यवस्था में सुधार: नव विश्वास का आधार।

अप्रैल, 2018 में एनआईपीएफपीतथा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अंतर्गत एनआईपीएफपीद्वारा एनआईपीएफपी-आर्थिक कार्य विभाग अनुसंधान कार्यक्रम (1अप्रैल, 2018 – 31मार्च 2020)को जारी रखा जाना है। यह अनुसंधान कार्यक्रम उन अनेक नई चुनौतियों के प्रति अनुसंधान इनपुट प्रदान करने के लिए है जिनका सामना आर्थिक कार्य विभाग एवं वित्त मंत्रालय को समय समय पर अपने क्रियाकलापों के निर्वाह के दौरान करना पड़ रहा है।

इस रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा राज्य वित्तीयन पर दिए गए विशेष ध्यान के परिणामस्वरूप ही परियोजनाओं का वृहद स्वरूप प्रसारित हुआ है जिनमें से कुछ परियोजनाएं हैं:- वर्ष 2022 तक के लिए राज्य राजस्व के अनुमान; राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों की समीक्षा; जनजातिय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई), भोपाल का संस्थानिक मूल्यांकन एवं अंतर विश्लेषण; मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा; वर्ष 2015-16 के संबंध में राज्य एफआरबीएम अधिनियम का सिक्किम सरकार द्वारा किए गए अनुपालन की समीक्षा; सिक्किम की मध्यावधि आर्थिक योजना: 2018-19 से 2020-21; आर्थिक नीति; अंत:शासकीय स्थानांतरण एवं लिंग समानता: भारतीय राज्यों का अध्ययन (दिसम्बर, 2017-दिसम्बर, 2019)। हिमाचल प्रदेश,उड़ीसा राज्यों के साथ लोक वित्त, क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान सहायता के संबंध में आवश्यकता आधारित सहयोग प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। (सभी परियोजना का विवरण ज्ञात करने के लिए अनुसंधान क्रियाकलाप देखें)

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एनआईपीएफपी द्वारा वर्ष के दौरान अपने दायित्वों से संबंधित विषयों के निर्वाह के लिए अनेक कार्यशालाओं, बैठकों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। ''आर्थिक संघवाद से क्या प्रभाव होते हैं?'' के विषय पर विश्व बैंक के सहयोग से दिनांक 1 अगस्त, 2018 को एनआईपीएफपी ऑडिटोरियम में एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य वित्तीयन के मुद्दों – राज्य बजट 2018-19 के विश्लेषण पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिनांक 10 अगस्त, 2018 को एक अर्ध दिव्सीय सेमिनार का आयोजन किया गया था।

द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू इकॉनिमिक थिंकिंग (आईएनईटी) के साथ मिलकर 26-28 नवम्बर, 2018 को इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में तीसरे विधि आर्थिक नीति सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

सेव द चिल्डर्न एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (एनएससी) के सहयोग से दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को एनआईपीएफपी के ऑडिटोरियम में ''भारत में बाल बजट: बाल अधिकारों की उपयोज्यता में उत्तम निवेश'' विषय पर अर्ध दिव्सीय राष्ट्रीय गोष्ठि आयोजित की गई थी।

बांग्लादेश के युवा एवं मध्यम स्तरीय अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल के लिए ''भारत सरकार की लोक वित्त नीति एवं संगठनात्मक क्रियाकलापों की समीक्षा'' के विषय पर संस्थान द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2019 को एक अर्ध दिव्सीय पारस्परिक चर्चा का सत्र आयोजित किया गया था।

गोवा इंटरनेशनल सेंटर, गोवा के सहयोजन से 31 जनवरी – 2 फरवरी, 2019 के दौरान ''द डिफिकल्ट डायलॉग'' विषय पर एक संगोष्ठि आयोजित की गई थी।

संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे: आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 9-20 अप्रैल 2018 के दौरान नए मुद्दे तथा लोक वित्त एवं नीति की चुनौतियां; भारतीय आर्थिक सेवा के 2017 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए जून 18 – 22, 2018 के दौरान लोक वित्त; आईए एवं एएस अधिकारियों के लिए दिसम्बर 10 – 14, 2018 के दौरान एनआईपीएफपीका उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम ;आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 10-21 दिसम्बर 2018 के दौरान नए मुद्दे तथा लोक वित्त एवं नीति की चुनौतियां; दक्षिण एशिया क्षेत्र के विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के लिए दिसम्बर 17-28, 2018 के दौरान दो सप्ताह के 12वें लोक अर्थशास्त्र पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 9-20 अप्रैल 2018 के दौरान नए मुद्दे तथा लोक वित्त एवं नीति की चुनौतियां; भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए दिसम्बर 24-28, 2018 के दौरान लोक वित्त; भारतीय ऑडिट एवं लेखांकन सेवा (आईए एवं आईएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए लोक वित्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी से 1 फरवरी, 2019; उड़ीसा सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों के लिए दो चरणों (चरण 1 जनवरी 14-18, 2019 तथा चरण 2 फरवरी11-14, 2019) के दौरान मधुसूदन दास रिजनल एकादमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भुवनेश्वर में लोक वित्त के परिणामों के लिए नवोपाय विषय पर।

विकास

डा. रीता पांडे, प्रोफेसर दिनांक 28 फरवरी, 2019 को सेवानिवृत्त हो गई हैं।

श्री अशोक कुमार खंडुरी द्वारा दिनांक 1.8.2018 से संस्थान में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया गया है।

श्री अरूणोदय कुमार, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी द्वारा त्यागपत्र दिया गया तथा उन्हें 9.7.2018 से कार्य मुक्त कर दिया गया है।

श्री भास्कर मुखर्जी, अधिशासी दिनांक 31 अगस्त, 2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

संकाय समाचार

डा.विजय केलकर,अध्यक्ष,एनआईपीएफपीद्वारा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल थिंक टैंक (आईटीटी) की दिनांक 12-13 अक्तूबर, 2018 को आयोजित दूसरी बैठक में प्रतिभागिता की गई।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के साथ दिनांक 15 अक्तूबर, 2018 को नीति आयोग द्वारा 7, लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक तेल एवं गैस नेतृत्व के संबंध में हुई परिचर्चा में प्रतिभागिता की गई।

2. अनुसंधान क्रियाकलाप

निष्पादित अध्ययन

- **भारतीय कारपोरेट सेक्टर पर क्रेडिट दबाव का अध्ययन** (**जुलाई** 2017-**जून** 2018)

प्रायोजक: कारपोरेट कार्य मंत्रालय **(**एमसीए)
दल: अजय शाह, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, अमेय सप्रे
लक्ष्य: विद्यमान क्रेडिट दबाव के अंतर को (i) निश्चित स्तरीय डेटा सेट के उपयोग से भारतीय कारपोरेट सेक्टर की संवेदनशीलता को एस्सेस करना (ii) सूचकों के उपयोग से विभिन्न सेक्टरों तथा उप-सेक्टरों में कारपोरेट सेक्टर के दबाव का विश्लेषण एवं सेक्टर वार संवेदनशीलता इंडेक्स का निर्माण करना (iii) डिस्टेंस-टू-डिफाल्ट विधि के उपयोग से क्रेडिट दबाव के परिमाण का मापन किए जाने के माध्यम से पूरा करना।

- **डिजिटल आब्जेक्ट आर्किटैक्चर के संबंध में नीतिगत इनपुट** (**आर्थिक कार्य विभाग**) (**अगस्त** 2017-**जनवरी** 2018)

प्रायोजक: दूरसंचार विभाग (डीओटी)
दल: अजय शाह, स्मृति परशीरा, विशाल त्रेहान, सुदिप्तो बैनर्जी
लक्ष्य: विभिन्न देशों में एमपीए संरचना के कार्यान्वयन का अध्ययन मॉडल

- **कारपोरेट कार्य मंत्रालय की आडिटर्स विशेषज्ञ समिति - कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं एनआईपीएफपी के मध्य समझौता ज्ञापन** (**मई** 2018-**अगस्त** 2018)

प्रायोजक: कारपोरेट कार्य मंत्रालय (**एमसीए)**
दल: अजय शाह, शुभो राय, आशिष अग्रवाल, शैफाली मल्होत्रा, सुदिप्तो बैनर्जी.
लक्ष्य: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार से बहुराष्ट्रीय ऑडिट फर्मों (एमएएफ) के प्रचालनों की देखरेख के लिए तीन सदस्य समिति का गठन करने के लिए कहा गया है। एनआईपीएफपीएस समिति का सचिवालय है।

- **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद (एनसीवीटी) की पुन: संरचना तथा सुदृढ़ीकरण के लिए अनुसंधान एवं परामर्शी सेवाएं (मई 2017 – मार्च**, 2019)

प्रायोजक: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय **(**एमएसडीई**)**
दल: अजय शाह, अनिरूद्ध बर्मन, सुयश राय, आदित्य सिंह राजपूत
लक्ष्य: मंत्रालय को एनसीवीटी की विनियामक के रूप में पुन:संरचना किए जाने के निर्णयों में सहायता प्रदान करना। इसमें एनसीवीटी से संबंधित निर्णय एवं क्रियाकलाप तथा संचलन एवं प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

- **अध्ययन - क्या मौद्रिक नीति से भारत में वित्तीय स्थिरता उत्पन्न हो सकती है** (**मई 2017-दिसम्बर**, 2018)

प्रायोजक: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)
दल: इला पटनायक**,** राधिका पांडे**,** शालिनी मित्तल
लक्ष्य: भारत में मूल्य स्थायित्व एवं वित्तीय स्थायित्व के मध्य समंजन की जांच करना।

- **जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई), भोपाल का संस्थानिक मूल्यांकन एवं अंतर विश्लेषण**

प्रायोजक: मध्य प्रदेश सरकार के अध्याधीन जनजातिय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई), भोपाल,
दल: पिनाकी चक्रबर्ती एवं श्रुति त्रिपाठी
लक्ष्य: जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मध्य प्रदेश द्वारा यूनिसेफ, भोपाल के साथ साझेदारी की गई है; इस साझेदारी का उद्देश्य जनजातिय अनुसंधान संस्थान *की क्षमताओं में संवर्धन* करना, नीतिगत अनुशंसाओं, विशेषत: जनजातिय, के प्रमाण एकत्रण के लिए अनुसंधान एवं मूल्यांकन करनाहै। साझेदारी के फ्रेमवर्क में अनुसंधान, मूल्यांकन एवं मानीटरिंग/मूल्यांकन सहित अध्ययनों की प्रक्रिया के संबंध में टीआरडीकी आंतरिक प्रतिस्पर्धी शक्तियों एवं न्यूनताओं के संबंध में बेहतर अंतदृष्टि प्राप्त करने के लिए **जनजातिय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई), भोपाल का संस्थानिक मूल्यांकन एवं अंतर विश्लेषण** करने का एक प्रमुख क्रियाकलाप भी शामिल किया गया है। एनआईपीएफपी द्वारा टीआरडीआई के साथ एक अनुबंध करके संस्थान के भावी विकास की विकास योजनाओं का निर्माण करने तथा अपने मूल्यांकन के आधार पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने के उद्देश्य से टीआरडीआई की शक्तियों, न्यूनताओं, संकटों एवं अवसरों का संज्ञान करने के उद्देश्य से संस्थानिक मूल्यांकन एवं अंतर विश्लेषण कर लिया गया है।

- **समावेशित विकास के लिए अवसंरचना निर्माण**

प्रायोजक: एशियन डेवलपमेंट बैंक
दल: अभिजित सेन गुप्ता (एडीबी), शताद्रू सिकदर एवं ऋचा जैन
लक्ष्य: संक्षेप: इस अध्ययन के अंतर्गत हमारे द्वारा भारत में जीवन यापन के मानकों में सुधार के लिए अवसंरचना विकास द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच की गई है। हमने वर्ष 2004-05 से 2015-16 की अवधि के दौरान भारत के प्रमुख 18 राज्यों में चार सेक्टरों, नामत: विद्युत, सड़क परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में आय वृद्धि एवं गरीबी कम करने के लिए अवसंरचना की उत्पति की भूमिका का अंवेषण किया है। हमारा प्रमुख्य निष्कर्ष यह रहा है कि सभी सेक्टरों, स्वास्थ्य सेक्टर के अलावा, में अवसंरचना का विकास करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। दूसरी तरफ सड़क परिवहन के अलावा सभी सेक्टरों में अवसंरचना के विकास गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले नागरिकों का उत्थान संभव हो सकता है। हमारे निष्कर्षों से ये संकेत प्राप्त हुए हैं कि भौतिक एवं गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना के स्तर महत्वपूर्ण होते हुए भी भारतीय राज्यों की श्रम उत्पादकता चैनल एवं खपत के माध्यम से विकास पर इसका प्रभाव नहीं हो पाता है।

- **भारत में आर्थिक विकास के पूर्वानुमान : समय परिवर्तित मापदंडों पर रिग्रेशन एप्रोच**

प्रायोजक: एनआईपीएफपी
दल: सुदिप्तो मंडल, परम चक्रबर्ती (अम्बेडकर विश्वविद्यालय), ऋचा जैन
लक्ष्य: मैक्रोइकॉनोमिक नीतियों का प्रभावी एवं समयानुकूल कार्यान्वयन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान लगाए जाने अनिवार्य हैं। इस पेपर में समय परिवर्तन मापदंड परावर्तन एप्रोच (टीवीपीआर) के प्रमुख घटक का उपयोग भारत की वास्तविक औसत एवं सेक्टरल विकास दर के पूर्वानुमान लगाए जाने के लिए किया गया है। हमारे द्वारा आर्थिक, मौद्रिक, व्यवसाय एवं उत्पादन साइड-विशिष्ट परावर्ती कारकों के मिश्रण के माडल का उपयोग करके अनुमान लगाए गए हैं। विभिन्न विकास ड्राइवरों के महत्व को ज्ञात करने के लिए तीन प्रकार के माडल उपयोग में लाए गए हैं। ''डिमांड साइड'' माडल के लिए इन परावर्ती कारकों में उत्पादन विशिष्ट सूचकों को अलग रखा गया है जबकि ''आपूर्ति साइड'' माडल के लिए सूचना को केवल उत्तरवर्ती सेट में से छांट लिया गया है। ''मिश्रित'' माडल में दोनों प्रकार के परावर्ती कारकों के सेट हैं। हमारा ऐसा मानना है कि टीवीपीआर माडल निरंतर पैरामीटर फैक्टर-संवर्धित परावर्तन मॉडल और डायनेमिक फैक्टर मॉडल तीनों विशिष्टताओं के लिए पूर्वानुमान प्रदर्शन के मामले में बेहतर है। टीवीपीआर मॉडल के आधार पर, हम पाते हैं कि मांग परावर्ती कारक कुल जीडीपी और औद्योगिक क्षेत्र जीडीपी के लिए त्रुटि पूर्वानुमान को कम करता है, जबकि आपूर्ति साइड परावर्ती

कारक सेवा क्षेत्र जीडीपी के लिए त्रुटि पूर्वानुमान को कम करता है। हम यह भी पाते हैं कि कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के लिए आपूर्ति साइड परावर्ती कारक और संयुक्त संस्करण दोनों का उपयोग करके पूर्वानुमान त्रुटि को कम किया जाता है।

- **दक्षिण एशिया में वित्तीय वैश्वीकरण एवं आर्थिक विकास: एक प्रयोगसिद्ध अध्ययन**

प्रायोजक: आईसीएसएसआर
दल: एन.आर.भानुमूर्ति, लोकेन्द्र कुमार (रामजस कालेज)एवंदिनेश कुमार नायक
लक्ष्य: इस अध्ययन में दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास वित्तीय वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच के प्रयास किए गए हैं। आर्थिक विकास पर समग्र प्रभाव के अलावा इसमें उन चैनल (चैनलों) का भी संज्ञान करने के प्रयास किए गए जिनमें माध्यम से वित्तीय वैश्वीकरण से विकास प्रभावित होता है। इस उद्देश्य से प्रत्यक्ष (अर्थात पूंजी का विनियोजन) तथा अप्रत्यक्ष चैनलों (अर्थात वित्तीय विकास, सरकारी नीतियों में परिवर्तन इत्यादि) के दोनों चैनलों के प्रति ध्यान दिया गया है। समग्र क्षेत्र के परिणामों से यह ज्ञात हुआ है कि विकास पर वित्तीय वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यधिक सीमित होता है जबकि इसके विपरीत दिशा में जाने के प्रमाण काफी सुदृढ़ हैं। घरेलू विकास के कारण ही वित्तीय वैश्वीकरण संभव हो पाता है। इस अध्ययन में अलग अलग देश स्तरीय विश्लेषण भी किए गए हैं। अलग अलग देश स्तरीय परिणामों में काफी भिन्नता होते हुए भी ऐसी भिन्नताएं मुख्यत: ऐसे देशों की शासन व्यवस्था के स्तर की भिन्नताओं के कारण हैं।

- **प्रधान मंत्री आवास योजना के संचलन मापदंडों का मूल्यांकन - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)**

प्रायोजक: ग्रामीण विकास मंत्रालय
दल: एन.आर.भानुमूर्ति, एच.के.अमरनाथ, भाबेश हजारिका, कृष्णा शर्मा , कणिका गुप्ता, तानवी ब्राह्मे
लक्ष्य: इस परियोजना में सरकार द्वारा ग्रामीण आवास कार्यक्रम पीएमएवाई-जी में निवेश किए जाने के परिणाम रोजगार एवं आय उत्पति जैसे कुछ सूक्ष्म मापदंडों का विश्लेषण किया गया है। इसके अंतर्गत फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन तथा निधि प्रवाह, निर्माण गति, बचत एवं सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग जैसे शासी मापदंडों का मूल्यांकन भी किया गया है। सूक्ष्म स्तर पर रोजगार एवं आय के संदर्भ में ग्रामीण आवास कार्यक्रम के परिणाम सकारात्मक पाए गए हैं। मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए गए विभिन्न प्रयासों के कारण शासी मापदंडों में भी सुधार देखने में आए हैं। पांच चयनित राज्यों से प्राप्त प्रारंभिक डेटा के विश्लेषण से पीएमएवाइ-जी के अंतगर्त आवास प्राप्त करने वालों के बेहतर स्वास्थ्य की स्थिति भी ज्ञात हुई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभग्राही आवास धारकों में आत्म गौरव, संरक्षा एवं सामाजिक समावेशन में भी सुधार आए हैं। इसी के साथ साथ विद्यालयों में बच्चों के निष्पादन एवं विद्यालय में बच्चों को दाखिल करवाने की दर में भी आकर्षक सुधार देखे गए हैं।

- **सरकारी स्कूल व्यवस्था में सुधार: नव विश्वास का आधार**

प्रायोजक: अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अनुदान, 2016.
दल: सुकन्या बोस, प्रियंता घोष, अरिवंद सरदाना (एकलव्य, मध्य प्रदेश)
लक्ष्य: इस परियोजना में ऐसे विभिन्न लोक वित्त मामलों का अध्ययन किया गया है जिनसे भारत में शिक्षा अधिकार के चिरस्थायी कार्यान्वयन एवं गारंटी पर प्रभाव पड़ते हैं। प्रत्ययात्मक फ्रेमवर्क एवं यूनिट डेटा के प्रयोगसिद्ध उपयोग से सावधानी पूर्वक किए गए इस अनुसंधान में प्रत्येक भारतीय राज्य में शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित नियामक संसाधनों के अनुमान लगाने के प्रयास किए गए हैं।

- **भारत में सरकारों के मध्य आर्थिक अंतरणों का अध्ययन**

प्रायोजक: आईडीआरसी
दल: पिनाकी चक्रबर्ती, लेखा चक्रबर्ती, मनीष गुप्ता, अमनदीप कौर, शताक्षी गर्ग, अजरूद्दीन , रजेल श्रेष्ठा

लक्ष्य: भारत में हाल ही में आर्थिक अंतरणों के संबंध में किए गए नीतिगत परिवर्तनों के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य संबंधों में परिवर्तन आया है। इस अध्ययन का उद्देश्य राज्य स्तर पर आर्थिक व्यवहार एवं लोक सेवा डिलीवरी पर ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण करना है।

- **राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों की समीक्षा (बीएमजीएफ परियोजना के अंतर्गत पंद्रहवा वित्त आयोग - लोक वित्त में नवोपाय)**

प्रायोजक: बीएमजीएफ
दल: पिनाकी चक्रबर्ती, मनीष गुप्ता
लक्ष्य: इस अध्ययन के अंतर्गत राज्यों द्वारा विभिन्न राज्यों की स्थानीय सरकारों को अंतरित किए जाने वाले संसाधनों के लिए विभिन्न राज्य वित्त आयोगों द्वारा अंगीकार की गई व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अनुरोध पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में 25 राज्य वित्त आयोगों की रपिोर्टों की जांच की गई है। इस अध्ययन विश्लेषण में राज्य वित्त आयोगों के प्रचालनों के अंतरों एवं चुनौतियों एवं राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं का प्रभाव्यता का अध्ययन/विश्लेषण किया गया है।

- **केन्द्र एवं राज्यों के मध्य संसाधन सहभाजन : सिद्धांत तथा रूझान**

प्रायोजक: पंद्रहवा वित्त आयोग
दल: पिनाकी चक्रबर्ती
लक्ष्य: संविधान में तथापि भारत की संकल्पना अर्ध-संघीय राष्ट्र के रूप में की गई है परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात के प्रथम चालीस वर्षों में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण राजनैतिक समदृश्यता देखने में आई है जिसके कारण केन्द्र में शक्ति का केन्द्रीकरण हुआ है। बाद के दशकों में, तथापि, राज्य स्तर पर अत्यधिक राजनैतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा के उदय के साथ साथ अपकेन्द्री रूझानों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। बाद की स्थिति से ही उदारीकरण की लाभकारी शक्तियों का मार्ग प्रशस्त हुआ जो अस्सी के दशक के अंत एवं नब्बे के दशक के प्रारम्भ में प्राप्त प्रभाव से अपना प्रभुत्व जमा पाई। राजस्व नीति के प्रति केन्द्र एवं राज्य सरकारों की अभिमुखमता से भी आर्थिक सुधारों पर बदलाव स्थापित हुए जिनका प्रभाव केन्द्र-राज्य अंतरणों के परिमाण एवं स्वरूप पर पड़ा। इस अध्ययन में केन्द्र से राज्यों के साथ संसाधनों के सहभाजन की प्रक्रियाओं एवं उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 15वें वित्त आयोग के अनुरोध पर किया गया है।

- **वर्ष 2022 तक के लिए राज्य राजस्व पूर्वानुमान**

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)
दल: आर. कविता राव, सच्चिदानंद मुखर्जी, सुरांजली टंडन एवं हरी नायुडु
लक्ष्य: इसमें हमने चार राज्यों के राजस्व का विश्लेषण किया है। अनुमानित कार्य कौशल, परावर्तन रूझान विश्लेषणों के उपयोग के आधार पर प्रत्येक कर एवं गैर-कर राजस्व के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। मूल्य संवर्धित कर संग्रहण, राज्य उत्पाद, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क, राज्य एवं परिवहन करों का विश्लेषण प्रसंभाव्य फ्रंटियर विश्लेषणों के उपयोग से करके वर्ष 2022 तक के राजस्व अनुमान लगाए गए हैं। गैर-कर राजस्व एवं अन्य छोटे करों को परावर्तन एवं रूझान विश्लेषणों के उपयोग से किए गए उक्त करों के विश्लेषण से अलग रखा गया है। विभिन्न कर एवं गैर-कर राजस्वों के संभावित मूल्यों के योग से कुल राज्य राजस्वों का औसत प्राप्त किया जा सका है। इसमें हमने चार स्थितियों की प्रस्तुति की है।

- **भारत के स्वास्थ्य बीमा नेटवर्क में निजी अस्पताल: आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन पर विचार**

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)
दल: मीता चौधरी, प्रीतम दत्ता

लक्ष्य: निजी अस्पतालों से सरकार द्वारा प्रायोजित भारत की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करने की प्रत्याशा की गई है। इस पेपर में देश में निजी अस्पतालों की उपलब्धता एवं प्रसार का अध्ययन सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाए जाने के दृष्टिकोण से किया गया है।

- **बीआईओएफआईएन: जैवविविधता के संरक्षण के लिए संसाधनों का एकत्रण** (**दिसम्बर** 2017 - **सितम्बर** 2018)

प्रायोजक: यूएनडीपी
दल: रीता पांडे, रेणुका साने, प्रिया यादव, सुमित अग्रवाल

जारी अध्ययन

- **ट्राई- एनआईपीएफपीअनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन** (**जून** 2016-**मई** 2019)

प्रायोजक: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)
दल: अजय शाह, इला पटनायक, स्मृति परिशरा, मयंक मिश्रा, फैजा रहमान, सुदिप्तो बैनर्जी, देवेन्द्र डामले, ऋषभ बेली, सारंग मोहारिर, अशिम कपूर, रचना शर्मा, सुदिप्तो बैनर्जी, विशाल त्रेहान , श्रृष्टि शर्मा
लक्ष्य: एनआईपीएफपीद्वारा ट्राई के साथ दूरसंचार ब्रॉडकास्टिंग सेक्टरों के विनियामक शासन एवं आर्थिक विश्लेषणों के क्षेत्रों का विश्लेषणात्मक एवं नीतिगत अनुसंधान करने के लिए तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन किया गया है।

- **उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था के निष्पादन ऑडिट में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए करार** (**मई** 2018-**जुलाई** 2019).

प्रायोजक: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)
दल: अजय शाह, इला पटनायक, शुभो राय, अमेय सप्रे, हरलीन कौर, महिमा गुप्ता, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, समीर पेठे, शैफाली मलहौत्रा, सुप्रिया कृष्णन
लक्ष्य: अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के निष्पादन ऑडिट की प्रक्रिया के लिए एनआईपीएफपीद्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में सीएजी को परामर्शी एवं ज्ञान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ऑडिट कार्यों के दौरान सीएजी के साथ एनआईपीएफपी की संलिप्तता के दौरान रणनीतिक लक्षित विकास, ऑडिट योजना का निर्माण ऑडिट निष्पादन एवं विश्लेषण संभव हो पाएगा।

- **स्वास्थ्य एवं इसके वित्तीयन के अनुसंधान एवं नीतियों में सुधार** (**दिसम्बर** 2015-**दिसम्बर** 2019)

प्रायोजक: बिल एवं मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन
दल: अजय शाह, इला पटनायक, शुभो राय, शैफाली मलहौत्रा, हरलीन कौर, रचना शर्मा, संहिता सपतनेकर, महिमा गुप्ता, मनप्रीत सिंह, समीर पेठे, सुप्रिया कृष्णन , मधुर मेहता. सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मोमिता दास
लक्ष्य: भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र का चित्रण करने वाली समस्याएं जटिल हैं। एक ओर जहांस्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे हैं, और दूसरी ओर राज्य लोक स्वास्थ्य व्यय की स्थिति के साथ साथ इसके व्यय के लेखांकन के कार्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन भी समस्याएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सूचना अंतराल अपर्याप्त या अपूर्ण डेटा से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव के कारण भी है।बिल एवं मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशनद्वारा एनआईपीएफपीको भारत में राज्यों के स्वास्थ्य की बेहतर समझ के लिए अपेक्षित उपकरण का विकास करने के लिए निधियन प्रदान करने के साथ साथ भारत में इसके लिए वित्तीयन भी किया जा रहा है। परियोजना का डिजायन लोक स्वास्थ्य वित्त के विस्तृत डेटासेट के लिए निर्माण के लिए ऊपर उल्लिखित सूचना अंतरों को भरने के उद्देश्य से तैयार

किया गया है। इसका समग्र उद्देश्य विश्वसनीय एवं विस्तृत डेटा उपलबध करवाना है जिससे स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों की डिजायनिंग एवं मानीटरिंग में सहायता प्रदान किए जाने के माध्यम से बेहतर सूचित निर्णय निर्धारण किए जा सकें।

- **भारत के विशेष क्षेत्रों की जटिल समस्याओं का अध्ययन** (**अप्रैल** 2018-**दिसम्बर** 2019)

प्रायोजक: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)
दल: इला पटनायक, अशिम कपूर, रचना शर्मा, समीर पेठे, शैफाली मलहौत्रा, चिराग आनन्द
लक्ष्य: इस परियोजना के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी(एनआईपीएफपी) द्वारा आईसीएसएसआर को *विशेष क्षेत्रों के जटिल मामलों* से संबंधित डिजीटल लाइब्रेरी के पेपर के संयोजन में सहयोग दिया जा रहा है। इस डिजीटल लाइब्रेरी का डिजायन एवं अनुरक्षण एनआईपीएफपीद्वारा किया जाएगा। इस लाइब्रेरी में घटक असेम्बली डिबेट्स, विधिक उपकरण, नीति पेपर, यूएन पेपर एवं करारों सहित प्रारम्भिक सामग्रियों को शामिल किया जाएगा।

- **एमसीए अनुसंधान कार्यक्रम** (**फरवरी** 2019-**जनवरी** 2021)

प्रायोजक: कारपोरेट कार्य मंत्रालय
दल: इला पटनायक, प्रतीक दत्ता, सुदिप्तो बैनर्जी, कार्तिक सुरेश, मेधा राजू, शुभो राय
लक्ष्य: प्रस्तावित फ्रेमवर्क का डिजायन कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा एनआईपीएफपी के मध्य तीन वर्षों के लिए औपचारिक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए निर्मित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनआईपीएफपी द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सांविधिक उत्तरदायित्वों के संबंध में आवश्यक विधिक,नीतिगत एवं अनुसंधान सहायता प्रदान की जाएगी।

- **भूमि बाज़ार को बेहतर बनाना** (**अप्रैल** 2019-**मार्च** 2021)

प्रायोजक: ओमिदयार नेटवर्क
दल: ईला पटनायक, देवेन्द्र डामले
लक्ष्य: भूमि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और संभवत: सबसे कम सुधार किए गए घटकों में से एक है। पिछले दो दशकों से अनवरत विकास एवं बढ़ते हुए शहरीकरण के परिणामस्वरूप भूमि बाजार में मांग आधारित परिवर्तन स्थापित हुए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है:

1. प्रशासनिक डिजायन एवं क्षमता में सुधार के लिए भूमि प्रशासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
2. प्रभावहीनता, न्यूनतर संव्यवहार लागतों एवं भूमि बाजार में बेहतर सम्पति अधिकारो के निर्माण के लिए भूमि अधिकारों एवं प्रतिबंधों की भूमिका का संज्ञान करना।
3. भूमि बाजारों की बाजार असफलताओं तथा भूमि व्यवस्था के डिजायन एवं विनियमन की भूमिका की जानकारी प्राप्त करना।

- **प्रभावशाली राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना के लिए संगठनात्मक डिजायन एवं आंतरिक प्रक्रियाएं (एनसीवीईटी)**

प्रायोजक: ओमिदयार नेटवर्क सर्विसेज
दल: इला पटनायक, प्रतीक दत्ता, सारंग मोहारिर
लक्ष्य: यह अध्ययन एनसीवीईटी (दो विनियामक निकायों, एनसीवीटी तथा एनएसडीए के विलय से गठित) को सम्पूर्ण भारत के कौशल विकास कार्यक्रमों गुणवत्ता में सुधार के लिए है। इस अध्ययन से एनसीवीईटीके लिए डिजायन का निर्माण संभव हो पाएगा; एनसीवीईटी को अपने निष्पादित के लिए अपेक्षित प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान, प्रमुख क्रियाकलापों एवं प्रक्रियाओं की सूची प्राप्त हो सकेगी। इस अध्ययन से विनियामक उपकरणों, संविदाओं तथा दिशानिदेशों का भी पता लगाया जा सकेगी जिनकी आवश्यकता एनसीवीईटी को अपनी स्थापना के पश्चात जारी तथा प्रवर्तन के लिए अपेक्षित होगी। एनआईपीएफपी द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा अन्य भागीदारों की संलिप्तता से एनसीवीईटी की स्थापना के लिए अपेक्षित

कार्यान्वयन योजना के निर्माण में सहायता प्रदान की जाएगी तथा इसके संबंध में परामर्श एवं बैठकों का आयोजन किया जाएगा। (फरवरी 2019-अगस्त 2019).

- **भारत में सकल घरेलू उत्पाद विकास के त्रैमासिक पूर्वानुमान (एनसीएईआर के सहयोग से)**

प्रायोजक: एनआईपीएफपी एवं एनसीएईआर
दल: रूद्राणी भट्टाचार्य (एनआईपीएफपी), सुदिप्तो मंडल (एनसीएईआर), बोरनली भंडारी (एनसीएईआर), एवं संध्या गर्ग (एनसीएईआर)
लक्ष्य: हाई फ्रिक्वेंसी मैक्रो डेटा के उपयोग से रियल टाइम त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान

- **वित्तीय संरचना, संस्थानिक गुणवत्ता एवं मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन : मेटा विश्लेषण**

प्रायोजक: एनआईपीएफपी
दल: श्रुति त्रिपाठी (एनआईपीएफपी), सहाना राय चौधरी (आईएमआई, कोलकाता)
लक्ष्य: अनुभवजन्य पुराने साहित्य में मौद्रिक नीति के ट्रांसमिशन के संदर्भ में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक गतिविधियों और मुद्रास्फीति के लिए मौद्रिक नीति के लपेट से हुए कमजोर ट्रांसमिशन की स्वीकृति दी गई है। कमजोर वित्तीय प्रणाली, वित्तीय एकीकरण के निम्न स्तर और कमजोर संस्थानों को अक्सर इन अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन की कमी के उदाहरणोंके रूप में उद्धृत किया जाता है। यह पेपर में इस तथ्य की जांच की गई है कि मेटा-विश्लेषण ढांचे का उपयोग करके विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के एक व्यापक सेट में मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन की सीमा में भिन्नता को ये कारक किस हद तक सुलझा सकते हैं। हमने यह पाया है कि विभिन्न वित्तीय संकेतकों द्वारा कब्जा किए गए वित्तीय विकास की डिग्री से मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन परिमाण और समय अंतराल में क्रॉस-कंट्री विविधताओं की व्याख्या प्रस्तुत होती है। हम उत्पादन वृद्धि के लिए ट्रांसमिशन परिमाण में वित्तीय आउटपुट की भूमिका भी पाते हैं।

- **भारत में निजी कारपोरेट निवेश का निर्धारण: मौद्रिक एवं आर्थिक नीति की अवस्थिति का निर्धारण (नवम्बर** 2017-2018)

प्रायोजक/सहयोजन: फोरधम यूनिवर्सिटी**,** न्यूयार्क
दल: लेखा चक्रबर्ती**,** ऋषिकेश विनोद **(**फोरधम यूनिवर्सिटी**)** एवं हनी करूण (आईएमएफ)
लक्ष्य: भारत में कारपोरेट निवेश के निर्धारकों का औसत स्तर पर विश्लेषण मौद्रिक एवं आर्थिक नीति की भिन्नताओं एन्ट्रोपी एनसेम्बल्स एवं बूट स्ट्रैपिंग विधि के उपयोग से विश्लेषण करना।

- **उप राष्ट्रीय सरकारों की बजट विश्वसनीयता: भारत के 28 राज्यों की आर्थिक पूर्वानुमान चूकों का विश्लेषण**

प्रायोजक: गेट्स कम्पोनेंट
दल: पिनाकी चक्रबर्ती, लेखा चक्रबर्ती, रूजेल श्रेष्ठ
लक्ष्य: भारत में 28 राज्यों (तेलंगाना को छोड़कर) के लिए पूर्वानुमान और पूर्वानुमान त्रुटियों के स्रोतों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से माइक्रो आर्थिक भिन्नताओं के पूर्वानुमानों और वास्तविकताओं के बीच महत्वपूर्ण विचलन की जांच करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करता है।

- **आर्थिक नीति**, **सरकारों के मध्य अंतरण एवं लिंग समानता : भारतीय राज्यों का अध्ययन** (**दिसम्बर** 2017-**दिसम्बर** 2019)

प्रायोजन/सहयोजन: जेनेट स्टोटस्की, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी एवं वाशिंगटन विश्वविद्यालय
दल: लेखा चक्रबर्ती, जेनेट स्टोटस्की एवं पियुष गांधी (आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय)
लक्ष्य: सभी राज्यों के संबंध में भारत में राजकोषीय अंतरणों और लैंगिक समानता की उप-राष्ट्रीय राजनैतिक आर्थिक प्रक्रियाओं और लिंकेज का अनुभवजन्य विश्लेषण करने के लिए।

- **लिंग समानता एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य में आर्थिक विस्तार पर सेक्टर व्ययों की प्रभाव्यता: एशिया प्रशांत क्षेत्र का अध्ययन** (**सितम्बर** 2017 –**अगस्त** 2020)

प्रायोजक: स्वयं प्रयासों द्वारा
दल: लेखा चक्रबर्ती, पियुष गांधी (आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय)
लक्ष्य: आर्थिक नीति व्यवहारों के प्रभाव का आनुभविक विश्लेषण - विशेष रूप से लैंगिक बजट की प्रक्रियाओं और विश्लेषणात्मक रूपरेखा के संदर्भ में - करने के लिए एशिया प्रशांत देशों में, राजनीतिक आर्थिक फ्रेमवर्क के दायरे में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में लिंग समानता के आधार पर वितरित किए गए लिंग बजटिंग।

- **पोषण - लोक व्यय समीक्षा** (**सितम्बर** 2018- **सितम्बर** 2020)

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)
दल: लेखा चक्रबर्ती, अमनदीप कौर, रसेल श्रेष्ठ, कोमल जैन
लक्ष्य: यूनिसेफ तथा गुजरात सरकार के साथ समन्वय से पोषण – पीईआर का विश्लेषण।

- **ओईसीडी देशों में पीएफएम के रूप में लिंग बजटिंग: स्वीडन से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्य** (**अगस्त** 2018-**अगस्त** 2019)

प्रायोजक/सहयोजन: यूनिवर्सिटी ऑफ उप्पासला एवं स्वीडन सरकार
दल: लेखा चक्रबर्ती
लक्ष्य: यह विश्लेषण करना कि किस स्वीडन द्वारा श्रम बाजारों एवं अन्य सामाजिक आर्थिक लिंग असमानताओं को लैंगिक बजटिंग के उत्तरदायी उपकरण के उपयोग कम करने में सफलता प्राप्त की है।

- **लोक वित्त के प्रभाव के लिए नवोपाय**

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), यूएसए
दल: पिनाकी चक्रबर्ती, लेखा चक्रबर्ती, मनीष गुप्ता
लक्ष्य: यह अध्ययन तीन वर्षीय परियोजना के अंतर्गत है जो भारत में लोक वित्त के प्रभाव के नवोपायों के लिए लोचक तकनीकी सहायता से किया जाना है।

- **वस्तु एवं सेवा कर के प्रवर्तन के वित्तीय प्रभाव - पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा कमीशंड**

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)
दल: सच्चिदानंद मुखर्जी, आर.कविता राव

- **करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के अनुपालन किए जाने के प्रभाव का सर्वेक्षण**

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)
दल: आर.कविता रावएवंसुरांजली टंडन

- **मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा**

प्रायोजक: मध्य प्रदेश सरकार
दल: रथिन राय एवं प्रताप रंजन जेना
लक्ष्य: इस अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक निष्पादन तथा उनके द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान किए गए अनुपालन के मूल्यांकन का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। इस अध्ययन में राजस्व निष्पादन, व्यय प्राथमिकताओं, बजट प्रबंधन व्यवस्था सहित राज्य वित्त के विस्तृत मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। इस अध्ययन में राज्य मापदंडों को विचार में लेते हुए एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का सरकार द्वारा किए गए अनुपालन का मूल्यांकन किया गया है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय प्रभाव: भविष्य के लिए प्रभाव एवं प्रज्ञता**

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)
दल: मीता चौधरी, रंजन कुमार मोहंती, राशि मित्तल
लक्ष्य: यह अध्ययन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रवर्तित राज्यों के स्वास्थ्य व्ययों के माध्यम से केन्द्रीय अंतरणों के विस्तार का परीक्षण किए जाने के लिए आशित है।

- **भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के 71वें दौर के अनुसार स्वास्थ्य पर घरेलू व्यय का विश्लेषण**

प्रायोजक: विश्व स्वास्थ्य संगठन
दल: मीता चौधरी, जय देव दुबे, बिदिशा मंडल
लक्ष्य: यह विश्लेषण भारत में स्वास्थ्य पर ओओपीई की प्रकृति, विस्तार एवं प्रभाव की आधार रेखा का संज्ञान करने के लिए आशित है तथा भविष्य में इसका उपयोग बेंचमार्क के रूप में वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के प्रति भारत की अभिमुखता को ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकेगा।

- **भारत में स्वास्थ्य पर लोक वित्तीयन : आगे की दिशा**

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन
दल: मीता चौधरी, रंजन कुमार मोहंती, श्रुति त्रिपाठी, प्रीतम दत्ता, जय देव दुबे, बिदिशा मंडल, सुनेत्रा घटक, राशि मित्तल
लक्ष्य: यह एक ऑनगोइंग तीन वर्षीय परियोजना है जो भारत में स्वास्थ्य पर लोक वित्तीयन के प्रभाव को ज्ञात करने तथा औचित्यपरक विकल्प सुझाने के विचार से की जा रही है।

नव प्रवर्तित परियोजनाएं

- **उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था के निष्पादन ऑडिट के लिए विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने का अनुबंध(मई** 2018 –**जुलाई** 2019)

प्रायोजक: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)
दल: अजय शाह, इला पटनायक, शुभो राय, अमेय सप्रे, हरलीन कौर, महिमा गुप्ता, मनप्रीत सिंह, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, समीर पेठे, शैफाली मलहौत्रा, सुप्रिया कृष्णन

- **आईसीएसएसआर - विशेष क्षेत्रों के जटिल मामले** (**अप्रैल** 2018 – **दिसम्बर** 2019)

प्रायोजक: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)
दल: इला पटनायक, अशिम कपूर, रचना शर्मा, समीर पेठे, शैफाली मलहौत्रा, चिराग आनन्द

- **एमसीए अनुसंधान कार्यक्रम** (**फरवरी** 2019 – **जनवरी** 2021)

प्रायोजक: कारपोरेट कार्य मंत्रालय
दल: इला पटनायक, प्रतीक दत्ता, सुदिप्तो बैनर्जी, कार्तिक सुरेश, मेधा राजू, शुभो राय

- **भूमि बाज़ार को बेहतर बनाना** *(***अप्रैल** *2019 –* **मार्च** *2021)*

प्रायोजक: ओमिदयार नेटवर्क
दल: इला पटनायक, देवेन्द्र डामले

- **कॉफी बोर्ड द्वारा किसानों एवं निर्यातकों के लिए विस्तारित विभिन्न अनुदानों के प्रभाव का मूल्यांकन**

प्रायोजक: कॉफी बोर्ड, बंगलौर
दल: रथिन राय, भाबेश हजारिका एवं एन.आर. भानुमूर्ति

- **द्वार रिसर्च फाउंडेशन एवं एनआईपीएफपीके मध्य डाटा सहभाजन करार**

प्रायोजक: द्वार रिसर्च फाउंडेशन
दल: रेणुका साने

- **जैव विविधता – वित्त एवं एस्सेस तथा भारत में लाभ सहभाजन : राजस्व हानि के कारण प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन**

प्रायोजक: यूएनडीपी
दल: रीता पांडे
लक्ष्य: यह अध्ययन एनआईपीएफपी की जैव विविधता वित्त के संबंध में जारी परियोजना के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

- **एफआरबीएम अधिनियम**, 2010 **के अनुपालन के संदर्भ में सिक्किम सरकार की अनुपालन रिपोर्ट**, 2016-17 **को तैयार करने में एनआईपीपीएफ का सहयोग।**

प्रायोजक: सिक्किम सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना

- **प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत रोजगार उत्पति का मूल्यांकन**

प्रायोजक: आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय
दल: एन.आर.भानुमूर्ति, दिनेश कुमार नायक, भाबेश हजारिका, तानवी ब्राह्मे, कणिका गुप्ता, अशोक भाकर

- **इथोपिया में संघवाद**

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)
दल: रथिन राय, लेखा चक्रबर्ती, मनीष गुप्ता

- **बच्चों के लिए लोक वित्त : राज्य स्तरीय विश्लेषण – गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा तथा कर्नाटक** (**मार्च** 2019-**जनवरी** 2020)

प्रायोजक: बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)
दल: लेखा चक्रबर्ती, अमनदीप कौर

- **अनपेड केयर अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक नीति**

प्रायोजन/सहयोजन: अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी
दल: लेखा चक्रबर्ती

- **राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना तथा हिमाचल प्रदेश में एसबीएसएपी के कार्यान्वयन के लिए संसाधन एकत्रण की रणनीतियों का निर्माण** (**प्रारम्भ तिथिदिसम्बर**, 2018)

प्रायोजक: यूएनडीपी
दल: रीता पांडे, प्रिया यादव, अनुजा मलहौत्रा, गरिमा जसुजा, रेणुका साने

- **राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना को अद्यतन करना तथा हिमालय संरक्षण के लिए भारत सरकार की यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत एसबीएसएपी के कार्यान्वयन के लिए संसाधन एकत्रण की रणनीतियों का निर्माण** (**प्रारम्भ तिथिदिसम्बर**, 2018)

प्रायोजक: यूएनडीपी
दल: रीता पांडे, प्रिया यादव, अनुजा मलहौत्रा, गरिमा जसुजा, रेणुका साने

3. कार्यशालाएं, बैठकें तथा सम्मेलन

	शीर्ष	आयोजन कर्ता	तिथि तथा स्थान
1.	**आर्थिक संघवाद से क्या प्रभाव होते हैं?**पर गोलमेज चर्चा	एनआईपीएफपी एवं विश्व बैंक	01 अगस्त, 2018 एनआईपीएफपी ऑडिटोरियम
2.	**राज्य वित्तीय के मुद्दे – राज्य बजट 2018-19 का विश्लेषण** पर अर्ध-दिव्सीय सेमिनार	एनआईपीएफपी	10 अगस्त, 2018 मल्टी पर्पस हाल, आईएचसी नई दिल्ली
3.	**तीसरा आर्थिक नीति सम्मेलन**	एनआईपीएफपीएवंद इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू इकॉनिमिक थिंकिंग (आईएनईटी)	26-28 नवम्बर, 2018 इंडिया हेबीटेट सेंटर, नई दिल्ली
4.	**भारत में बाल बजट: बाल अधिकारों की उपयोज्यता में उत्तम निवेश''** के विषय पर अर्ध-दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी	सेव द चिल्ड्रन तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (एनसीई) के सहयोग से	20 दिसम्बर, 2018 एनआईपीएफपीऑडिटोरियम
5.	बांग्लादेश के युवा एवं मध्यम स्तरीय अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल के लिए **''भारत सरकार की लोक वित्त नीति एवं संगठनात्मक क्रियाकलापों की समीक्षा''**विषय पर अर्ध-दिवसीय परिचर्चा	एनआईपीएफपी	29 जनवरी, 2019 एनआईपीएफपी ऑडिटोरियम
6.	**डिफिक्ल्ट डॉयलाग''**विषय पर संगोष्ठी	गोवा इंटरनेशनल सेंटर, गोवा के साथ साझेदारी से एनआईपीएफपी	31 जनवरी – 2 फरवरी, 2019 गोवा इंटरनेशनल सेंटर, गोवा

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम

	शीर्ष	तिथि	स्थल	कार्यक्रम समन्वयक
1.	आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए'' **नए मुद्दे तथा लोक वित्त एवं नीति की चुनौतियां**''	अप्रैल 9-20, 2018	एनआईपीएफपी	लेखा चक्रबर्ती एवं अमनदीप कौर
2.	भारतीय आर्थिक सेवा के 2017 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए ''**लोक वित्त**''	जून 18 – 22, 2018	एनआईपीएफपी	रूद्राणी भट्टाचार्य
3.	आईए एवं एएस अधिकारियों के लिए'' **एनआईपीएफपी का उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम**''	दिसम्बर 10 – 14, 2018	एनआईपीएफपी	पिनाकी चक्रबर्ती एवं मनीष गुप्ता
4.	आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ''**नए मुद्दे तथा लोक वित्त एवं नीति की चुनौतियां**''	दिसम्बर 10 – 21, 2018	एनआईपीएफपी	अमनदीप कौर
5.	दक्षिण एशिया क्षेत्र के विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के लिए दो सप्ताह के 12वें **लोक अर्थशास्त्र पुनश्चर्या पाठ्यक्रम** का आयोजन	दिसम्बर 17-28, 2018	एनआईपीएफपी	अमेय सप्रे एवं सुरांजली टंडन
6.	भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए ''**लोक वित्त**''	दिसम्बर 24-28, 2018	एनआईपीएफपी	मनीष गुप्ता एवं रूद्राणी भट्टाचार्य
7.	भारतीय ऑडिट एवं लेखांकन सेवा (आईए एवं आईएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए ''**लोक वित्त**''	जनवरी 21 – फरवरी 01, 2019	एनआईपीएफपी	अमेय सप्रेएवं सुरांजली टंडन
8.	उड़ीसा सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों के लिए ''**लोक वित्त के परिणामों के लिए नवोपाय**'' चरण-।	जनवरी 14-18, 2019	भुवनेश्वर	पिनाकी चक्रबर्ती एवं मनीष गुप्ता
9.	उड़ीसा सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों के लिए ''**लोक वित्त के परिणामों के लिए नवोपाय**'' चरण-।।	फरवरी 11-14, 2019	भुवनेश्वर	पिनाकी चक्रबर्ती एवं मनीष गुप्ता

5. प्रकाशन एवं संचार

इस अकादमिक वर्ष के दौरान एनआईपीएफपी द्वारा दो मोनोग्राफ प्रकाशित किए गए हैं – (1) एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट 2017-18: एमर्जिंग इश्यूज (इम्पेक्ट ऑफ पावर सेक्टर डेब्ट – उदय आन स्टेट फाइनेंस)'', पिनाकी चक्रबर्ती, मनीष गुप्ता, लेखा चक्रबर्ती, अमनदीप कौर (2018) तथा (2) "एमर्जिंग इश्यूज इन स्टेट फाइनेंस पोस्ट फोर्टिन्थ फाइनेंस कमीशन : एनाजिसस ऑफ स्टेट बजट् 2017-18", मनीष गुप्ता, लेखा चक्रबर्ती एवं पिनाकी चक्रबर्तीद्वारा किए गए हैं। ये मोनोग्राफ बेल एंड मेलिन्दा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) से अनुदान प्राप्त विस्तृत अनुसंधान परियोजना का प्रतिफल हैं।

संस्थान का अर्धवार्षिक न्यूजलैटर जुलाई, 2018 तथा जनवरी, 2019 में प्रकाशित किया गया है जिसमें इसकी जारी परियोजनाओं, संकाय क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत अपडेट दिए गए हैं। एनआइपीएफपी के अनुसंधान संकाय एवं उनके सहयोगियों द्वारा कुल **32 कार्य दस्तावेजों** की रचना की गई है तथा इनका प्रकाशन एनआईपीएफपी कार्य पेपर श्रृंखला के अंतर्गत किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित कुल **06 एक पृष्ठीय एवं 20 ब्लॉग लेख** प्रकाशित किए गए हैं।

इस यूनिट द्वारा संस्थान की वेबसाइट www.nipfp.org.in. को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। वेबसाइट उपयोक्ता एनआईपीएफपी के संकाय सदस्यों द्वारा रचित लेखों से युक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी ब्लॉग भी अब देख सकते हैं जिसमें लोक वित्त एवं नीति विषयों पर सभी लेख उपलब्ध होते हैं। यह ब्लॉग http://nipfp.org.in/blog/पर उपलब्ध है। एनआईपीएफपीका का ट्वीटर पर सोशल मीडिया एकाउंट nipfp.org.org.in के यूजर नाम से तथा इसका कुशल उपयोग अनुसंधान कार्यों एवं कार्यक्रमों की जानकारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सर्कलों में प्रसारित करने के लिए किया जाता है। संस्थान के पास अपना यूट्यूब चैनल nipfp events के नाम से यहां से XXX वीडियो भी जारी किए जाते हैं।

(मूल्य अंकित प्रकाशनों की सूची अनुलग्नक *V, में दी गई है)*

6. पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र आटोमेटिड प्रचालनों से युक्त लोक वित्त के क्षेत्र में अनुसंधान एवं संदर्भ का एक पुस्तकालय है। इसमें लोक वित्त, आर्थिक नीति, स्थूल एवं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था एवं उद्योग अध्ययन, योजना एवं विकास, आर्थिक सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय एवं नैसर्गिक अर्थव्यवस्था, नगरीय अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र तथा संघवाद एवं विकेन्द्रीकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।

यह पुस्तकालय तीन तलों में स्थापित है तथा यहां आवश्यक अवसंरचना सहित पर्याप्त स्थन उपलब्ध है। भूतल पर स्थित विशाल पठन क्षेत्र में पाठकों के लिए वाईफाई इंटरनेट सम्पर्कता युक्त लैपटॉप उपलब्ध करवाए गए हैं। पुस्तकालय के सभी क्रियाकलापों तथा सेवाओं के प्रचालन एन्ट्रप्राइज जावाबिन्स (ईजीबी) आधारित पुस्तकालय साफ्टवेयर पैकेज एलआईबीएसवाईएस-7.0 कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं। इस पुस्तकालय के लिए उपयोक्ताओं के अनुरोध रिमोट एक्सेस सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

यह पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 9.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक खुला रहता ह। यहां विशेषतः आर्थिक संघवाद, लोक अर्थशास्त्र, लोक वित्त तथा नीति, करारोपण एवं लोक व्यय, लैंगिंक अध्ययन एवं अन्य लोक नीतियों से संबंधित 65133 से भी अधिक पुस्तकें एवं अन्य पेपर उपलब्ध हें। वर्ष 2018-19 के दौरान पुस्तकालय के संग्रह में 839 नए पेपर तथा 32 कार्यशील पेपर जोड़े गए थे जिनमें भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सोसायटियों, अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के प्रकाशन शामिल हैं। इस पुस्तकालय को अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डिपाजटरी के अंतर्गत 15 नए प्रकाशन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, इस पुस्तकालय को 15 सीडी-रोम भी प्राप्त हुई हैं जिनमें भारत की जनसंख्या के डाटा स्रोत इत्यादि शामिल हैं। इस पुस्तकालय द्वारा निम्नलिखित राष्ट्रीय / अतर्राष्ट्रीय जनरलों, डाटा बेस जनरलों तथा अन्य आनलाइन जनरलों के लिए अंशदान दिया जाता है / प्राप्ति की जाती है।

विवरण	कुल संख्या
अंतर्राष्ट्रीय जरनल	30
राष्ट्रीय जनरल	43
पत्रिकाएं	15
आनलाइन पत्रिका– "इकॉनोमिस्ट"	01
निम्नलिखित आनलाइन डेटाबेस के अंतर्गत जनरल: 1) साइंस डायरेक्ट: इॅकोनोमैट्रिक्स एंड फाइनेंस बंडल 2) ओयूपी आनलाइन इकॉनोमिक जरनल बंडल क्लेक्शन 3) जेएसटीओर (बिजनेस क्लेक्शन I तथा II) 4) पूर्ण टैक्स्ट वर्जन के साथ इकोनलिट 5) स्टाटा जनरल 6) फ्री आनलाइन एवं अन्य	3304

इस पुस्तकालय में 15 पत्रिकाओं के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्र भी उपलब्ध हैं:

क्र.सं.	राष्ट्रीय समाचार पत्र	प्रिंट/ आनलाइन
1.	बिजनेस लाइन	प्रिंट
2.	बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड+ वॉल स्ट्रीट जरनल	प्रिंट आनलाइन
3.	इकॉनोमिक टाइम्स	प्रिंट
4.	एम्प्लायमेंट न्यूज	प्रिंट
5.	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	प्रिंट
6.	इंडियन एक्सप्रेस	प्रिंट
7.	मिन्ट	प्रिंट
8.	नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	प्रिंट
9.	टेलीग्राफ (कोलकाता अंक)	प्रिंट
10.	द हिन्दु	आनलाइन
11.	द हिन्दुस्तान टाइम्स	प्रिंट
12.	द स्टेट्समैन	प्रिंट
13.	टाइम्स ऑफ इंडिया	प्रिंट
1.	फाइनेंशियल टाइम्स	आनलाइन

इस पुस्तकालय में प्राप्त होने वाले सभी पेपर एवं लेख नियमित तौर पर डेटाबेस में शामिल किए जाते हैं तथा इन्हें नीचे उल्लिखित प्रकाशन बुलेटिनों के माध्यम से जारी किया जाता है:-

- *करंट अवेयरनैस सर्विस (पुस्तकों का नया संवर्धन)*
- *आर्टिकल अलर्ट सर्विस (समाचार पत्रों की क्लीपिंग्स में नया संवर्धन)*

- *करंट कंटेंट्स सर्विस (पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली आवधिक पत्रिकाओं के कांटेट पृष्ठों का मासिक बुलेटिन)*
- *बजट पूर्व एवं बजट के पश्चात के विशेष बुलेटिन*

इस पुस्तकालय द्वारा करंट अवेयरनैस सर्विस; बिबलोग्राफिक्ल सर्विस एवं रेफरेंस सर्विस भी उपलब्ध कराई जाती है। ईमेल के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी के संकाय सदस्यों को बुक अलर्ट तथा आर्टिकल अलर्ट नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, पुस्तकालय द्वारा निम्लखित ई-रिर्सोसिस के लिए भी सब्सक्राइब किया गया हैः-

ई-रिसोर्सिस:

ई-जरनल डेटाबेस**:**

क्र. सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	एस्सेस करने का माध्यम
1.	आक्सफोर्ड आनलाइन इकॉनोमिक जरनल बंडल क्लेक्शन	http://www.oxfordjournals.org	आईपी आधारित
2.	जेएसटीओर (बिजनेस क्लेक्शन I तथा II)	http://www.jstor.org	आईपी आधारित
3.	एलसेवियर: साइंस डायरेक्ट जनरल: इकॉनोमिक्स, इकोनोमैट्रिक एंड फाइनेंस सब्जेक्ट बंडल	http://www.sciencedirect.com	आईपी आधारित
4.	पूर्ण टैक्स्ट युक्त इकोनलिट	http://www.search.ebscohost.com	आईपी आधारित

ई-डेटाबेस**:**

क्र. सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	एस्सेस करने का माध्यम
1.	ओईसीडी टैक्सेशन लायब्रेरी	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
2.	ओईसीडी इकॉनोमिक्स आई लायब्रेरी	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
3.	ओईसीडी गवर्नेस आई लायब्रेरी	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
4.	आईबीएफडी रिपोजिटरी	http://www.ibfd.org	आईपी आधारित (अधिकतम 5 उपयोक्ता)
5.	आईबीएफडी इलैक्ट्रानिक आनलाइन	http://www.ibfd.org	आईपी आधारित (अधिकतम 5 उपयोक्ता)
6.	आईएमएफ ईलायब्रेरी	http://www.elibrary.imf.org	आईपी आधारित
7.	स्टाटा जनरल	http://www.stata-journal.com	पीडीएफ उपलब्ध
8.	ईपीडब्ल्यूआरएफ इंडिया टाइम सीरिज	http://www.epwrfits.in	आईपी आधारित
9.	सीईपीआर (डिस्कशन पेपर)	http://www.cepr.org	आईपी आधारित (चयनित उपयोक्ताओं के लिए)
10.	इंटरनेशनल टैक्सेशन	http://www.internationaltaxation.taxmann.com	यूजर आईडी/ पासवर्ड आधारित
11.	मनुपत्र	www.manupatra.com	यूजर आईडी/ पासवर्ड आधारित

कारपोरेट डेटाबेस **:**

क्र. सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	एस्सेस करने का माध्यम
1.	सीएमआईई: इकॉनोमिक आउटलुक	http://www.economicoutlook.cmie.com	आईपी आधारित
2.	सीएमआईई: प्रोएसआईक्यू	http://www.prowess.cmie.com	आईपी आधारित
3.	सीएमआईई: कैपेक्स	http://www.capex.cmie.com	आईपी आधारित

ई-बुक डेटाबेस**:**

क्र. सं.	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	एस्सेस करने का माध्यम
1.	एडवर्ड एलगर ई-बुक्स	https://www.elgaronline.com/browse?access=user&level=parent	आईपी आधारित
2.	**स्प्रिंगर ई-बुक्स सब्जेक्ट बंडल आन इकॉनोमिक्स	http://www.link.springer.com	आईपी आधारित

Note: **यह स्प्रिंगर डेटाबेस वर्ष 2016 से समाप्त कर दिया गया है तथा इसका एस्सेस केवल 2005 से 2015 के लिए उपलब्ध है।

अध्ययन दौरे

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी पुस्तकालय में दिनांक 19 मार्च, 2019 को इस्लामिया डिग्री कालेज, देवबंद, सहारनपुर के लिए 50 बीबीए एवं बीसीए के विद्यार्थियों द्वारा अपने वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ अध्ययन दौरा किया गया था। उनका प्रमुख उद्देश्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीके संबंध में अभिमुखता प्राप्त करना एवं संस्थान द्वारा सरकार के लिए निर्मित की जाने वाली नीतियों का ज्ञान प्राप्त करना था। उनके इस अध्ययन दौरे के दौरान डा. अमेय सप्रे, सहायक प्रोफेसर तथा डा. हरी नायुडु, अर्थशास्त्री द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीएवं इसकी नीतियों के संबंध में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था।

- **संसाधन सहभाजन:**

पेपर डिलीवरी सेवा में संसाधन सहभाजन के संबंध में पुस्तकालय में डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (डीईएलएनईटी) के साथ अपनी सदस्यता बरकरार रखी गई थी। वर्ष के दौरान अन्य पुस्तकालयों से 172 दस्तावेज ऋण पर लिए गए तथा अन्य पुस्तकालयों को 27 दस्तावेज दिए गए। वर्ष 19-2018के दौरान लगभग 256 बाह्य अनुसंधान स्कालरों तथा नीति निर्माताओं द्वारा पुस्तकालय का दौरा किया गया।

विजिटर रिकार्ड: 2018-19

माह	विजिटरों की संख्या
अप्रैल	17
मई	60
जून	56
जुलाई	15
अगस्त	11
सितम्बर	6
अक्तूबर	6
नवम्बर	14
दिसम्बर	31
जनवरी	22
फरवरी	8
मार्च	10
	256

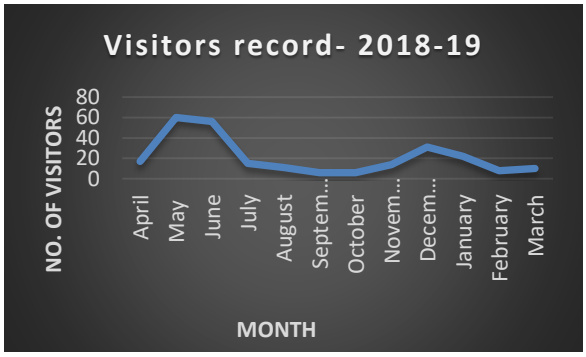

उपर्युक्त चार्ट में हमारे पुस्तकालय में आने वाले आंगुतकों की बारम्बारता दर्शाई गई है। इससे यह देखा जा सकता है कि मई/जून तथा दिसम्बर/जनवरी के दौरान अधिकतम संख्या में उपयोक्ताओं द्वारा पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है।

- आरईपीईसी (अर्थशास्त्र के लिए अनुसंधान पेपर) 87 देशों के सैंकड़ों स्वयंसेवको का सामूहिक प्रयास है जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र एवं संबद्ध विज्ञानों के अनुसंधान के वितरण को प्रोत्साहित किया गया है। इस परियोजना का मर्म कार्यशील दस्तावेजों, पुस्तकों, पुस्तक अध्यायों का आनलाइन विकेन्द्रित ग्रंथागार है जिसका अनुरक्षण स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी पुस्तकालय द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय विषय की इस रिपोजिटरी आरईपीईसी (अर्थशास्त्र के लिए अनुसंधान पेपर) में प्रतिभागिता करके संस्थान के कार्यशील दस्तावेजों का मैटाडाटा अपलोड किया गया है। वर्ष के दौरान आरईपीईसी (अर्थशास्त्र के लिए अनुसंधान पेपर) में 31 कार्यशील पेपर अपलोड किए गए थे। विश्व भर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी के इन कार्यशील पेपरों को 2273 बार डाउनलोड किया गया तथा 9508 बार इसके संक्षेप सार का अवलोकन किया गया।

आरईपीईसी कार्यशील पेपर सीरिज **2018-19**की एस्सेस सांख्यिकी

डाउनलोड तथा सार प्रेक्षण की संख्या		
अप्रैल 2018-मार्च 2019		
माह	**सार प्रेक्षण**	**डाउनलोड**
2018-04	**797**	**156**
2018-05	**893**	**283**
2018-06	**745**	**161**
2018-07	**583**	**140**
2018-08	**666**	**144**
2018-09	**721**	**170**
2018-10	**839**	**209**
2018-11	**984**	**192**
2018-12	**809**	**167**
2019-01	**825**	**175**
2019-02	**876**	**264**
2019-03	**770**	**212**
योग	**9508**	**2273**

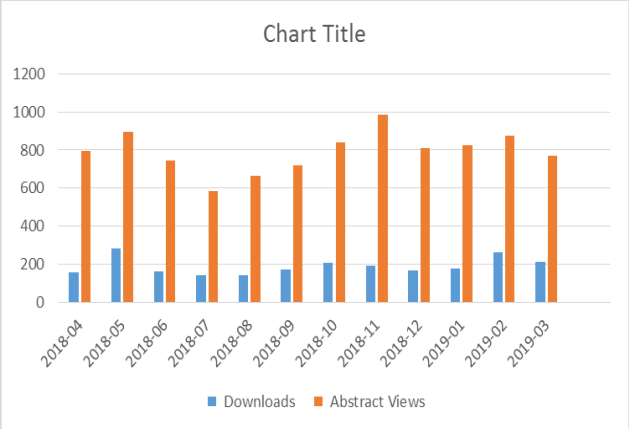

उपर्युक्त तालिका एवं चार्ट से यह ज्ञात होता है कि फरवरी, 2019 के दौरान सबसे अधिक 264 पेपर डाउनलोड किए गए थे तथा नवम्बर, 2018 के दौरान सबसे अधिक 984 लेखों का प्रेक्षण किया गया था।

रैप्रोग्राफिक सेवाएं

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय संसाधन सामग्री के लिए संकाय सदस्यों तथा बाह्य अनुसंधान स्कालरों को रैपरोग्राफिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। उपयोक्ताओं द्वारा हमारे रैपरोग्राफिक रोस्टर का सराहना की गई है। लगभग 6500 पृश्ठों की फोटोकापी की गई सामग्री अनुसंधान कार्य के लिए उपयोक्ताओं को वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीपुस्तकालय में रैप्रोग्राफिक नयाचार का अनुसरण कापीराइट उल्लंघन नहीं किया जाता है।

प्रकाशित / प्रस्तुत पेपर:

- मौहम्मद आसिफ खानतथा नवीन कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से ''***यूज ऑफ लायब्रेरी रिसोर्सिज बाइ द फैक्ल्टी मेम्बर्स ऑफ विनय, न्यू दिल्ली, इंडिया: ए कम्पेरिटिव स्टडी***'' शीर्षक युक्त पेपर का लेखन किया गया है। इस पेपर की प्रस्तुत डा. मौहम्मद आसिफ खान द्वारा 6-8 अगस्त, 2018 को सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर में आयोजित ''थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेस ऑफ एशियन लायब्रेरिज: बिल्डिंग स्मार्ट लायब्रेरिज: चेन्जिज, चैलेंजिस, इश्यूज एंड स्टैट्रजिस'' में प्रस्तुत किया गया था। इस पेपर का प्रकाशन अब्दुल मजीद बाबा एवं अन्यों द्वारा सम्पादित **'' बिल्डिंग स्मार्ट लायब्रेरिज: चेन्जिज, चैलेंजिस,**

इश्यूज एंड स्टैट्रजिस''सम्मेलन पेपरों में भी किया गया था।

सेमिनार सम्मेलन, **सिम्पोजिया कांग्रेस**, **प्रस्तुति/प्रतिभागिता**

- मौहम्मद आसिफ खानद्वारा 9 अप्रैल, 2018 को डेलनेट, जेएनयू कैम्पस, वसंत कुंज, नई दिल्ली में आयोजित डेवलपिंग लायब्रेरी नेटवर्क (डीईएलएनईटी) एजीएम में भाग लिया गया है।

- मौहम्मद आसिफ खानद्वारा इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट (आईएसआईडी), वसन्त कुंज, नई दिल्ली में दिनांक 1 मई, 2018 को आयोजित फाउंडेशन डे लेक्चर कार्यक्रम में भाग लिया गया है।

- मौहम्मद आसिफ खानद्वारा 3 मई, 2018 को इंडिया हेबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में हिलेरी क्रिन्न के ''ए केस स्टडी – यूजिंग साइटेशन मैट्रिक्स टू इवेल्यूएट बुक पब्लिशर्स'' के लेक्चर कार्यक्रम में प्रतिभागिता की गई है। यह कार्यक्रम एडवर्ड एल्गर पब्लिशिंग एवं बालानी इंफोटैक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था।

- मौहम्मद आसिफ खान, जोपुस्तकालय समिति के सदस्य भी हैं, को आईएसआईडी में दिनांक 30 जुलाई, 2018 को 'लायब्रेरी इंटर्नस'' के विषय विशेषज्ञ के तौर इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट (आईएसआईडी), वसन्त कुंज, नई दिल्ली मेंआमंत्रित किया गया था।

- मौहम्मद आसिफ खान, जो "भारत में विशेष क्षेत्रों के जटिल मामले" के दस्तावेज सेंटर की परामर्श समिति के सदस्य भी हैं, को एनआईपीएफपी, नई दिल्ली की दिनांक 20 अगस्त, 2018 को आयोजित प्रथम बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस परामर्श समिति का गठन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) एवं गृह मंत्रालय की परियोजना के अंतर्गत किया गया है।

- मौहम्मद आसिफ खानद्वारा इग्नु, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में दिनांक 17 सितम्बर, 2018 को आयोजित पुस्तकालय दिवस कार्यक्रम में भाग लिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर जी. राम रेड्डी लायब्रेरी, इग्नु द्वारा आईएएसएलआईसी के सहयोग से किया गया था।

- मौहम्मद आसिफ खान, जो "भारत में विशेष क्षेत्रों के जटिल मामले" के दस्तावेज सेंटर की परामर्श समिति के सदस्य भी हैं, को दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को आईसीएसएसआर, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम समीक्षा समिति में आमंत्रित किया गया था। इस परामर्श समिति का गठन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) एवं गृह मंत्रालय की परियोजना के अंतर्गत किया गया है।

- मौहम्मद आसिफ खान द्वारा प्रोफेसर राज नेहरू, कुलपति, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, हरियाणा द्वारा ''ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन रिसोर्सिस इन लायब्रेरिज'' के डीईएलएनईटी वार्षिक वक्तव्य में भाग लिया गया है।

- मौहम्मद आसिफ खानद्वारा डेलनेट, वसंत कुंज, नई दिल्ली में बुधवार, 13 फरवरी, 2019 को आयोजित ''राइडिंग द वेव: डिस्कवरिंग न्यू कम्पीटेंसिस फार एलआईएस प्रोफेशनल्स'' पर आयोजित गोष्ठी में भाग लिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन डेलनेट – डेवलपिंग लायब्रेरी नेटवर्क एंड स्पेशल लायब्रेरिज एसोसिएशन – एशियन चेप्टर द्वारा किया गया था।

- मौहम्मद आसिफ खान, जो पुस्तकालय समिति के सदस्य भी हैं, को इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट (आईएसआईडी), वसन्त कुंज, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2019 को आयोजित आईएसआईडी की लायब्रेरी समिति की दूसरी बैठक में आमंत्रित किया गया था।

7. संकाय क्रियाकलापों की हाइलाइट्स

रथिन राय

डा. रथिन राय, निदेशक द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं:- कॉफी बोर्ड द्वारा किसानों एवं निर्यातकों के लिए विस्तारित विभिन्न अनुदानों के प्रभाव का मूल्यांकन (नेतृत्व डा.एन.आर. भानुमूर्ति); मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा (नेतृत्व डा. प्रताप रंजन जेना); राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय प्रभाव: भविष्य के लिए प्रभाव एवं प्रज्ञता (नेतृत्व डा. मीता चौधरी); तथा एनआईपीएफपी-आर्थिक कार्य विभाग की अनुसंधान परियोजना का नया चरण।

डा. राय ने बिटिंग द बुलेट – प्राइवेटाइजेशन वर्सिस मर्जर्स के विषय पर दो दिवसीय सीईपीआर इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव, 2018 में आईटीसी मौर्य, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018 को आयोजित एक पैनल चर्चा में भाग लिया गया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज सोसायटी ऑफ इंडिया की आईआईएम नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2018 में आयोजित वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। उन्होंने टेंडेम रिसर्च और आईएलओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित **एमर्जिंग टैक्नोलॉजिस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया** की टेंडम रिसर्च रिपोर्ट में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया, जो आईएचसी, नई दिल्ली, सितम्बर 13, 2018 को आयोजित किया गया था। डा रॉयमिस्टर चार्ल्स बोमन, लॉर्ड मेयर लंदन सिटी की उपस्थिति मेंफिक्की फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में अक्तूबर 12, 2018 को आयोजित भारत-यूके ग्रीन फाइनेंस डायलॉग की गोलमेज चर्चा में प्रतिभागिता की गई। उन्होंने 13 अक्टूबर, 2018 को आईसीएच, नई दिल्ली में चिंतन एनवायरनमेंट रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप द्वारा आयोजित इवेंट ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट ऑफ इंडिया में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। उन्होंने 13 अक्टूबर, 2018 को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित **वट इस द ट्रू वैल्यु ऑफ रूपी** पर आयोजित गोलमेज चर्चा में प्रतिभागिता की। जीआईजैड द्वारा हयात रीजेंसी, नई दिल्ली में दिनांक 2 नवंबर, 2018 को **क्नेक्टिंग टूगेदर, वर्किंग टूगेदर** के वाटर सम्मेलन में टॉक शो में उन्होंने प्रतिभागिता की और वक्तव्य दिया। उन्हें विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी के अंतर्गत आरआईएस, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2018 को "लर्निंग साउथ-साउथ कोऑपरेशन" पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम में **डेवलपमेंट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड एजेंडा 2030** पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें पीजीडीएवी कॉलेज, नई दिल्ली के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) द्वारा पीजीडीएवी कॉलेज, नई दिल्ली में दिसंबर 11, 2018 को कंटैम्पोरेरी बिजनेस एनवायरनमेंट के संकाय विकास कार्यक्रम में **फिस्कल सिस्टम एंड कंटैम्परेरी बिजनेस सिनेरियो** पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

डा. राय ने यूएनडीपी एसडीजीपी फाइनेंस कमेटी, यूएनडीपी की यूएन हाउस, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली में 25 फरवरी, 2019 को आयोजित पहली बैठक में भाग लिया। उन्होंने ग्रीन फाइनेंस की परिभाषा पर एक आम सहमति बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया। 26 फरवरी 2019 को शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा **कैनेटीक्स और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव** पर आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में उन्होंने प्रतिभागिता की थी। दिनांक 9 अप्रैल, 2018 को मलागा, स्पेन में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि (यूएनसीडीएफ) द्वारा आयोजित **म्यूनिसिपल फाइनेंस एनटायटल्ड रिपर्पसिंग म्यूनिसपल फाइनेंस : टूर्वा ए फाइनेंशियल इकोसिस्टम फार म्यूनिसिपैलिटिज** डैट मिट्स द एसडीजी चैलेंजिस के विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय नीति संवाद में भाग लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज (सीबीपीएस), बसावगुड़ी, बैंगलोर द्वारा 18 अप्रैल 2018 को आयोजित बजट के वार्षिक एंडोवमेंट वक्तव्य में उन्हें **वाय किनेशियन्स शुड बि वरिड एबाउट द फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया** विषय पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कॉलेज ऑफ एग्रीक्चरल बैंकिंग पुणे में 3-4 मई, 2018 को **पॉल्टिकल इकॉनोमी ऑफ इंडियन फिस्कल रूल्स** पर प्रधान वक्तव्य देने तथा **फिस्कल रिस्क एंड मोनेट्री पॉलिसी** की पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। डा. राय को **टैक्स पालिसी एंड रिफार्मस इन साउथ एशिन कंट्रीज** शीर्षक के 15 वें वार्षिक सनेई सम्मेलन में भाग लेने तथा सनेई नेटवर्क के कार्यकारी संकाय एवं कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, समझ और विकास की व्यापक चिंताओं से संबंधित मजबूत अनुसंधान अंतर-संबंध स्थापित करना था। बैठक का आयोजन 10-11 मई,

2018 को काठमांडू, नेपाल में किया गया है। वे एनआईएफएम, वित्त मंत्रालय द्वारा एनआईएफएम में भारतीय आर्थिक लेखा सेवा और भारतीय पीएंडटी वित्त और लेखा सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के बारे में जानकारी तथा इन चुनौतियों को पूरा करने में अधिकारियों के योगदान पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए गए थे।डा. राय को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 3 जून, 2018 को डब्ल्यूईडी 2018 के तत्वाधान में यूएनईपी, फिक्की तथा क्लाइमेट बांड्स द्वाराआयोजित गैल्वेनाइजिंग सस्टेएबल फाइनेंस फार इंडियाज डेवलपमेंट के सम्मेलन में वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे 'नेचुरल कैप्टिल ऑफ इंडिया : स्टेट्स एंड पालिसी इम्पलीकेशंस सेशन ऑफ द हाई लेवल डायलाग सिरिज'' की पैनल चर्चा में शामिल थे जिसकी डायलाग श्रृंखला का सह आयोजन यूएन एनवार्यनमेंट तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 4 जून, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था। वे आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जून, 2018 को मुम्बई में आयोजित एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक में **डिस्क्शन आन की रिकोमेंडेशनंस ऑफ लीड अप इवेन्टस आन डिफ्रेंट इंफ्रास्टक्चर सेक्टर** के सेमिनार में पैनलबद्ध प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित किए गए थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत के संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहकारिता काकर्यालय एवं रायल थाई सरकार द्वारा बैंकाक में 27-29 जून, 2018 आयोजित **रिजनल कंसलटेशन आन साउथ साउथ कोओपरेशन फार एशिया एंड द पैसेफिक : टूवार्ड्स द ब्यूनस एयर्स प्लान फोर्टिथ एनिवर्सिटी** में प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड सम्मेलन के 15वे एडीशन में प्रधान वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन फोरटैल बिजनेस सॉल्यूशन द्वारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) से समर्थन प्राप्त इंडिया बुलियन एंड ज्वैर्ल्स एसोसिएशन (आईबीजेए), एसोसिएशन ऑफ गोल्ड रिफाइनर्स एंड मिन्टस ऑफ इंडिया (एजीआरएमआई), एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सपोर्टर्स ऑफ घाना, ओनटेरिया, कनाडा एंड सिंगापुर बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा ले मेरिडियन, कोच्चि, भारत में दिनांक 3-5 अगस्त, 2018 को किया गया था। वी.वी. गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा द्वारा आयोजित स्कील डेवलपमेंट एंड एम्पलायमेंट जनरेशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। लगभग 30 सरकारी अधिकारी तथा दक्षिण एशियाई देशों के लगभग बीस भिन्न देशों से आए अन्य भागीदारों द्वारा वी.वी. गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में 10 सितम्बर, 2018 को आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

डा. राय एनआईएफएम, फरीदाबाद द्वारा आईएचसी, नई दिल्ली में 6 अगस्त, 2018 को केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों के लिए आयोजित रोल ऑफ एफए के उद्घाटन सत्र में विशेषज्ञ वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए थे। डा. राय यूएन कंट्री टीम (यूएनसीटी) की वार्षिक रिट्रिट के अवसर पर इम्पलीटेशन प्लान फार यूनाइटिड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क (2018-2022), संयुक्त राष्ट्र की भारत में फ्रेमवर्क की पंचवर्षीय कार्यक्रम, जो भारत की नई एवं उदीयमान विकास प्राथमिकताओं एवं संवहनीय विकास के लिए एजेंडा 2030 के साथ संरेखित किया गया है, पर गेटवे रिजोर्ट, दमदमा लेक, गुड़गांव में दिनांक 30-31 अगस्त, 2018 को आयोजित विस्तृत चर्चा में अपना प्रधान वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किए गए थे। उन्हें 31 अक्तूबर, 2018 को पुणे के कालेज ऑफ एग्रीकचरल बैंकिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित नीतिगत मामलों के सेमिनार में इंकलुजिव एवं संस्टेनेबल ग्रोथ इन इंडिया - पालिसी चैलेंजिस एंड प्रोसपेक्टस के विषय पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। 14-15 नवम्बर, 2018 को बैंकाक में इकानोमिक एंड सोशन कमीशन फार एशिया एंड द पैसेफिक (ईएससीएपी) के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय विशेष समूह बैठक (ईजीएम) में कंम्प्रीहेंसिव एस्सेमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट रिक्वार्यनमेंट्स फार एचिविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाई 2030 के विकास में प्रतिभागिता के लिए वे आमंत्रित किए गए थे।

डा. राय को मालवंकर हाल, नई दिल्ली में दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित 53वें स्कॉच सम्मेलन के अवसर पर **इनवेस्टिंग इन न्यू इंडिया** के सत्र में : द फाइव ईयर :2019 मेक्स फाइव ईयर्स ऑफ नरेन्द्र मोदी गर्वनमेंट, वट आर इट्स इम्पलीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस? पैनलबद्ध के रूप में आमंत्रितकिया गया था। कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में 22 दिसम्बर, 2018 को आयोजित 55वें स्कॉच सम्मेलन में डा.राय द इकॉनोमिक मैनिफेस्टो के सत्र के लिए भी पैनलबद्ध के रूप में आमंत्रित किए गए थे। उन्हें ओआरएफ तथा विदेश मंत्रालय द्वारा ताज पैलेस होटल, नई दिल्ली में 8 जनवरी, 2019 को संयुक्त रूप से आयोजित ''रायसीना डायलाग 2019'' में 'व्हैन डब्ल्यूटीओ मैट वेस्टफालिया: प्रिजर्विंग द लिबरल इकॉनोमिक आर्डर' के सत्र में वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। ओआरएफ तथा विदेश मंत्रालय द्वारा ताज पैलेस होटल, नई दिल्ली में 9 जनवरी, 2019को संयुक्त रूप से आयोजित ''रायसीना डायलाग 2019'' में**स्टेट ऑफ प्ले: इन डिफेंस ऑफ द**

लिबरल आर्डरके सत्र में भाग लेने के लिए वे आमंत्रित किए गए थे। मुम्बई में दिनांक 10 जनवरी, 2019 को आयोजित 55वें इंडियन इकॉनोमिक सोसायटी कांफ्रेस में वेलेडिक्टरी एड्रैस देने के लिए वे आमंत्रित थे। एसडीजी के संस्थानिकरण के राष्ट्रीय कंकलेव में**स्टेट बजट्स एंड अदर रिसोर्सिज फार एसडीजी**के पैनलबद्ध के रूप में वे नीति आयोजन, यूएन भारत तथा एनएफआई द्वारा 4 फरवरी, 2019 को होटल पार्क, संसद मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में आमंत्रित किए गए थे। उन्हें डच बैंक द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 11 फरवरी, 2019 को आयोजित **नाइन्थ एनुअल डीबीएस्सेस इंडिया मैक्रो डे इनवेस्टर कांफ्रेस 2019** के विषय पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। डा.रायको ओ.पी.जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी तथा नेटवर्क ऑफ स्कूल्स ऑफ पब्लिकपालिसी, अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेशनल ट्रस्ट फार द हैंडीकैप्पड परिमिसिस,नई दिल्ली में 26 फरवरी, 2019 को**गर्वेनस इन एन ऐरा ऑफ इक्विलेटी: ट्रेनिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पालिसी प्रैक्टिशनर्स इन साउथ एशिया** के समापन सत्र की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया था।

डा.रॉय को 1) लंदन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस कांफ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान देने के लिए, 2) प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों की भागीदारी प्राप्त के लिएगेट्स फाउंडेशन पब्लिक फाइनेंस प्रोग्राम के शोध विषयों पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक राउंड-टेबल का आयोजन और अध्यक्षता करने 3) लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आमंत्रित व्याख्यान देने के लिए 4) भारत के उच्चायोग के अनुरोध पर, नेहरू केंद्र अथवा उच्चायोग द्वारा व्यवस्था किए जाने वाले किसी अन्य स्थल पर 3-11 मार्च 2019 को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें **पीआईसी पब्लिक पॉलिसी एजेंडा 2019-2024**पर पीआईसी पुणे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली में 26 मार्च 2019 को आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें विदेश सेवा संस्थान, ओल्ड जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली में दिनांक मार्च 29, 2019 को विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित प्रोफेशनल पाठयक्रम के अवसर पर विदेशी डिप्लोमैट्स ने 67वें द वर्ल्ड इकॉनोमी : एन इंडियन पर्सपेक्टिव विषय पर डिप्लोमेट्स को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था|

डा. राय अनेक समितियों / कार्य समूहों तथा अकादमिक संस्थानों के सदस्य हैं: सदस्य, एक्सपर्ट ग्रुप फार यूएनईएससीएपीः इकॉनोमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिकः सदस्य, जी-20 मामलों पर वित्त मंत्री का परामर्शी ग्रुप; सदस्य, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद में नीति कार्यान्वयन में निर्देशन के लिए, (3 सितम्बर, 2013 के पश्चात से); सदस्य, गवर्नर मंडल, इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनोमिक ग्रोथ, दिल्ली; सदस्य, संचलन निकाय, नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी), नई दिल्ली; सदस्य, रीडर ग्रुप, ग्लोबल ह्यूमन डेवलमेंट रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास योजना, फैलो, कैम्ब्रिज कामनवेल्थ सोसायटी; सदस्य, के.एम. मणि सेन्टर फार बजट स्टडीज की परामर्शी परिषद, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टैक्नोलाजी; के एम मणि सेंटर फार बजट स्टडीज की परामर्शी परिषद, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी; संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य (यूएनईपी) इंक्वारी इनटु ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम - सदस्य, इंडिया एडवाइजरी कमिटी;सदस्य, मेटा काउंसिल आन इंक्ल्यूसिव ग्रोथ, वर्ल्ड इकानामिक फोरम, जेनेवा; सदस्य, टास्क आन एलीमिनेशन ऑफ पावर्टी इन इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग); सदस्य: भारत में जैव विविधता वित्त प्रयास का तकनीकी परामर्शी समूह, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (8 मई, 2015 के पश्चात से) ; सदस्य, आरआईएस समीक्षा समिति, आरआईएस के संकाय पदों तथा उनके वेतनमानों की विस्तृत समीक्षा के लिए; सदस्य, अध्यक्ष के ज्ञान / अनुसंधान प्रयासों की लोक सभा कोर गुप समिति; सदस्य, अनुसंधान परामर्शी परिषद (आरएसी); सदस्य, कार्यकारी निकाय, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पालिसी एनालिसिस; एडवाइजरी बोर्ड ऑफ अर्बनाइजेशन, आईआईएचएस, बंगलौर; सदस्य, अकादमिक परिषद, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), दो वर्ष की अवधि क लिए (14.1.2018 तक); सदस्य, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल वर्किंग ग्रुप आन फाइनेंशियल सर्विसेज (एफएसडब्ल्यूजी) फ्राम इंडिया; सदस्य, एफआरबीएम के लिए भावी रोडमैप तैयार करने की वृहद समीक्षा करने तथा अनुशंसाएं करने की समिति - अक्तूबर, 2016 तक; सदस्य, 10-19 जुलाई, 2017 से संचलित किए जाने वाले हाई-लेवल पालिटिक्ल फोरम (एचएलपीएफ) आन सस्टेनेबल डेवलमेंट में वर्ष 2017 से भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) का कार्य समूह; सदस्य, ''आर्थिक सेक्टर'' के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग;मूल्यांकन मानीटरिंग समिति (ईएमसी), विकास मानीटरिंग एवं मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष; सदस्य, संचलन निकाय, उत्कृष्टता केन्द्र, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, उत्पाद एवं नारकोटिक्स (2.3.2013 से 3.3.2017); सदस्य, अनुसंधान परामर्श समिति, सीपीआर, नई दिल्ली 20.3.2017 से प्रभावी एक वर्ष के लिए,सदस्य, नीति आयोग द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव 'समावेष' के अध्याधीन राष्ट्रीय संचालन समिति - मैकेनिज्म फार नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप्स विद नोलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सदस्य, सी।। इकानोमिक अफेयर्स

काउंसिल 2017-18; ज्यूरी सदस्य, ब्रिक्स इकानोमिक रिसर्च अवार्ड फार 2017, एक्जिम बैंक; सदस्य, वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल सेक्टर रेग्यूलेटरी एपवांयटमेंट सर्च कमेटी (एफएसआरएएससी); सदस्य, नीति आयोग की कमेटी टू ट्रांसफार्म इंडिया'ज गोल्ड मार्केट;सदस्य, टेन्डेम एडवायजरी बोर्ड – मई के पश्चात से 2018; विशेष अतिथि, कार्यवाहक समिति, एसडीजी फाइनेंशियल फैकल्टी, यूएनडीपी।

एन.आर. भानुमूर्ति

डा. एन.आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं का नेतृत्व किया गया है: कॉफी बोर्ड द्वारा किसानों एवं निर्यातकों के लिए विस्तारित विभिन्न अनुदानों के प्रभाव का मूल्यांकन। उन्हें फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन एंड इकॉनोमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया के अपने अनुसंधान पेपर के लिए बैंक इंडोनेशिया (इंडोनेशिया का सेंट्रल बैंक) द्वारा बाली, इंडोनेशिया में दिनांक 30-31 अगस्त, 2018 को आयोजत ''मैंनटेंनिंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रैंनथिंग मोमेंटम ऑफ ग्रोथ एमिड्स्ट हाई अनसर्टेनिटी'' को आयोजित 12वें वार्षिक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड प्रदान किया गया है।

डा. भानुमूर्ति द्वारा आईएमटी, गाजियाबाद में 21 जनवरी, 2019 को "केंद्रीय बजट: 2019-20" पर आयोजित चर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया गया; ग्रोथ प्रोसपेक्टस फार इंडियन इकॉनोमी: रोड अहेड फार $ 5 बिलियन इकॉनोमी, पीएचडीसीसीआई, 23 मई, 2018. डा. भानुमूर्ति ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जयपुर द्वारा 19 अप्रैल, 2018 को आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की तैयारी पर एक कार्यशाला संसाधक की सेवाएं प्रदान की हैं।

डा. भानुमूर्ति को विशेषज्ञ वक्ता के तौर पर 11 फरवरी, 2019 को आईएनजीएएफमें "फिस्कल मोनेट्री इंटरेक्शन इन इंडिया'' विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था; आईसीएएस प्रोबेशनर्स के लिए आयोजित कार्यक्रम में **डेफिसिट्स और डेब्ट** को लक्षित करते हुए, 10 अप्रैल, 2018 को दो-सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए "**एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी**" के लिए, भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए जून 20, 2018 को पब्लिक फाइनेंस फार इंडियन इकोनिमिक सर्विस; आईए एवं एएस अधिकारियों के लिए उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम में ओपन इकॉनामी मैक्रो लिंक्स, विनियम दर, ब्याज दर तथा मूल्यह्रास पर; 10-14 दिसंबर 2018; डेट और डेफ़िसिट्स को लक्षित करना, और सार्वजनिक व्यय दक्षता का आकलन, दिसंबर 12 और 13 दिसंबर, 2018 को "वित्त और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर आईसीएएस प्रोबेशनर्स के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम" 10-21 दिसंबर, 2018; भारतीय वित्तीय और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त में पाठ्यक्रम में 24 जनवरी, 2019 को राजकोषीय-मौद्रिक नीति लिंकेज, 21 जनवरी - 1 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत की गई |

डा. भानुमूर्ति को इंडिया टूडे के मेक इन इंडिया में पैनलबद्ध किया गया है: 6 जुलाई 2018 को ताजमहल होटल, नई दिल्ली में एमर्जिंग एंटरप्राइजर्स अवार्ड की प्रस्तुति; उनके द्वारा बाली, इंडोनेशिया में 30-31 अगस्त, 2018 के दौरान आयोजित मैंनेटेनिंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रैंथनिंग मोमेंटम ऑफ ग्रोथ एमिड्स्ट हाई अनसर्टिनिटी विषय पर बैंक इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 12 वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटिज मार्केट्स, मुम्बई द्वारा 7-10 जनवरी, 2019 को आयोजित इंडियन इकोनोमैट्रिक सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। भारतीय इकोनोमिक एसोसिएशन द्वारा उन्हें वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, वैल्लौर में 27-29 दिसम्बर, 2018 को आयोजित 101वें वार्षिक सम्मेलन में उन्हें प्रधान वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था । एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनिला में उन्हें इकॉनोमिक रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा नवम्बर 19-23, 2018को आमंत्रित किया गया था;जीएस यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर में नवम्बर 9-10, 2018को ट्रासफार्मिंग इंडिया : इश्यूज एंड चैलेंजिस के विषय पर आयोजित दो दिव्सीय सम्मेलन में उन्हें वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था ; एस्सेसिंग पब्लिक एक्पीडिचर एफीसियेंसी इन इंडिया पर एडीआरआई, पटना में 15वें वित्त आयोग द्वारा 1 अक्तूबर, 018 को आयोजित ''एड्रेसिंग द प्राब्लम्स ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्स डिस्पैरिटी ऑफ इंडिया'' के राष्ट्रीय सेमिनार में उन्हें पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था; यूएन-डीईएसए द्वारा उन्हें सितम्बर 5-

7, 2018को यूएन-ईसीएलएसी, सेनटियागो, चिली की वार्षिक परियोजना लिंक बैठक में ग्रोथ प्रास्पेक्ट्स फार इंडिया के विषय पर वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया था।

डा. भानुमूर्ति द्वारा 5 मार्च, 2019 को भारतीय निर्यात के पूर्वानुमानों की एक्जिम बैंक की स्टेंडिंग तकनीकी समिति की बैठक में भाग लिया गया था; नीति आयोग की दिनांक 21 जनवरी, 2019 को आयोजित गन्ने एवं चीनी उद्योग कार्यबल समिति की पहली बैठक में भाग लिया; आईआईटी-पालाक्काड की संकाय चयन समिति की बैठक में दिनांक 24 फरवरी, 2019 को भाग लिया; भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक एवं नीति अनुसंधान द्वारा 1-2 मार्च, 2019 को जयपुर में आयोजित अनुसंधान सम्मेलन की पैनल चर्चा में प्रतिभागिता की; मणिपुर विश्वविद्यालय में 16 जुलाई, 2018 को 15वें वित्त आयोग के समक्ष प्रमुख मामलों पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में प्रधान वक्तव्य दिया।

उनके द्वारा 8 मार्च, 2019 को एनएमआईएमएस, मुम्बई के वार्षिक सम्मेलन में प्रधान वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था; बिट्स पिलानी (गोवा कैम्पस) द्वारा उन्हें 17 मार्च,2019 को आयोजित अपनी वार्षिक सेमिनार में प्रधान वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था; हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में एसडीजी एवं भारत पर आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में उनके द्वारा प्रधान वक्तव्य प्रस्तुत किया गया 18 अप्रैल, 2018 को इंगाफ में आईटीईसी के कार्यक्रम में आर्थिक-मौद्रिक परिचर्चा में प्रतिभागिता की गई; प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंदौर में 14 मई, 2018 को टाइम सीरिज इकोनोमैट्रिक्स पर वक्तव्य दिया; 17 मई, 2018 को 15वें वित्त आयोग की परिचर्चा के अंतर्गत विख्यात अर्थशास्त्री के साथ उनकी चर्चा में भाग लिया; अमृता स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा इकोनोमैट्रिक्स विषय अपने पीएचडी कार्यक्रम के लिए 13-15 जून, 2018 के दौरान उनके वक्तव्य आयोजित किए गए; मध्य प्रदेश सरकार के लिए "लोक व्यय, गवर्नेंस एवं मानव विकास" विषय पर भोपाल में 3 अगस्त, 2018 को उनके द्वारा वक्तव्य की प्रस्तुति; जयपुर में दिनांक 7 अगस्त, 2018 को प्रिपेयर्डनेस फार इम्पलीमेंटेशन ऑफ एसडीजी के संबंध में इंटरनेशनल सेंटर फार एनवायरनमेंट आडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में परिचर्चा के आयोजन; फ्लेम यूनिवर्सिटी, पुणे में 8 अगस्त, 2018 को भारतीय मैक्रोइकॉनोमिक्स के मुद्दों पर वक्तव्य की प्रस्तुति; आरबीआई स्टाफ कालेज, चेन्ने में दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को मिड-कैरियर अधिकारियों के साथ परिचर्चा; आईआईएम, लखनऊ में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय 3 अक्तूबर, 2018 को लखनऊ में परिचर्चा; भारत में आर्थिक-मौद्रिक सम्बद्धता के विषय पर आईआईएम लखनऊ, नोएडा शाखा में दिनांक 20 अक्तूबर, 2018 को परिचर्चा; आईएनजीएएफ में 7 दिसम्बर, 2018 को भारत के आर्थिक नीति मामलों पर परिचर्चा; 14 जनवरी, 2019 को क्लब कनाडा, कनाडा उच्चायोग, दिल्ली क्लब हाउस में कनाडा के डिप्लोमेट्स के साथ बैठक।

अनेक समितियों / कार्यकारी समूहों तथा अकादमिक संस्थानों के साथ डा. भानुमूर्ति की सदस्यता बनी हुई है: वे गन्ना तथा चीनी उद्योग की कार्यबल समिति, नीति आयोग (अध्यक्ष: प्रोफेसर रमेश चन्द) में दिसम्बर, 2018 से सदस्य हैं; दिसम्बर, 2018 से सदस्य, कार्य बल दल नेतृत्व एवं सदस्य, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का उत्तराखंड में ग्रामीण विकास के कार्यान्वयन के मूल्यांकन का चौथा कॉमन समीक्षा मिशन; भारतीय इकोनोमैट्रिक सोसायटी के सचिव; अनुसंधान एवं विकास के लिए भारतीय आर्थिक संघ के प्रबंधन ट्रस्टी; आरबीआई की कार्यशील पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आरबीआई डीआरजी स्टडी के रैफरी की भूमिका का निर्वाह, टैक्नोलोजिकल पूर्वानुमान तथा सामाजिक बदलाव, अर्थशास्त्र एवं वित्त की तिमाही समीक्षा, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्राप्त पाण्डुलिपि, भारतीय आर्थिक समीक्षा, जरनल ऑफ क्वांटिटेटिव इकॉनोमिक्स, इंटरनेशनल जरनल ऑफफाइनेंस एंड इकोनोमिक्स, जरनल ऑफ सोशल एंड इकोनोमिक डेवलमेंट, माइक्रोफाइनेंस रिव्यू। जून, 2018 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की उप-राष्ट्रीय लेखा समिति के सदस्य (अध्यक्ष: प्रोफेसर रविन्द्र ढोलकिया); भारत में किशोर स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन में निवेश के अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटिड नेशन पापुलेशन फंड (यूएनएफपीए) की तकनीकी परामर्श समिति में जून, 2018 से सदस्य; मार्च, 2018 से एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्टेंडिंग टैक्नीकल कमिटी ऑफ एक्सपोर्ट के सदस्य; फरवरी, 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक, ओकेजनल पेपर्स के सम्पादन परामर्श बोर्ड में सदस्यता; इंडिया टूडे के इकोनोमिस्ट्स बोर्ड में सदस्यता।

उनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, आईजीआईडीआर, आईआईटी-बम्बई, इंडियन स्टेटिस्टीकल इंस्टीट्यूट (कोलकाता), अमिटी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट

ऑफ हायर लर्निंग, जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय की पीएचडी का परीक्षण किया गया है। आईआईएम लखनऊ से एक पीएचडी विद्यार्थी के लिए उन्होंने सह-गाइड का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है। (डिग्री मार्च, 2019 में जारी)

पिनाकी चक्रबर्ती

डा.पिनाकी चक्रबर्तीद्वारा ओवरव्यू ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन के शीर्षक युक्त रिपोर्ट की अपनी अनुसंधान योजना को पूरा कर लिया गया है तथा यह 15वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। इस अध्ययन में विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा विभिन्न राज्यों की स्थानी सरकारों के संसाधनों के अंतरण के लिए अंगीकार की गई अभिमुखता का अध्ययन किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अनुरोध पर इस परियोजना के लिए 25 राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है। राज्य वित्त आयोगों के अंतरों एवं प्रचालन की चुनौतियों तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभाव का इसमें अध्ययन विश्लेषण किया गया है।

केन्द्र एवं राज्यों के मध्य संसाधन सहभाजन से संबंधित रिपोर्ट : डा. चक्रबर्ती द्वारा वर्ष के दौरान सिद्धांतों एवं प्रचालन से संबंधित कार्य प्रारम्भ किए गए थे जिसके अंतर्गत राज्य स्तर पर वृहद राजनैतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते हुए अपकेन्द्री रूझानों का परीक्षण किया गया। इस अध्ययन के अंतर्गत केन्द्र से राज्यों के लिए संसाधन सहभाजन एवं इसके सिद्धांतों का परीक्षण किया गया था ।

दिनांक 6 अगस्त, 2018 को उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर में वित्तीय मैक्रोइकॉनोमिक्स पाठ्यक्रम (आईआईएमबी) पर तथा दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को सेन्टर फार ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (सीटीआरपीएफपी), कोलकाता द्वारा आयोजित ''ब्रॉडर एम्बिट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड जीएसटी'' पर वक्तव्य प्रस्तुत किए थे। सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा गंगटोक में उन्हें 5-6 अक्तूबर, 2018 को आयोजित ''इंडिया आफ्टर ए क्वार्टर सेंच्युरी ऑफ इकोनामिक रिफोर्मस – द बेनिफिट्स एंड कास्ट्स'' शीर्षक युक्त राष्ट्रीय सेमिनार में वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया था तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), कोलकता में दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 को उन्होंने संघवाद पर लोक वक्तव्य की प्रस्तुति दी थी।

दिनांक 27 अक्तूबर, 2018 को उन्होंने सेन्टर फार द स्टडी ऑफ कंटेम्पोरेरी सोसायटिज (सीएससीएस), भुवनेश्वर में 'इम्पलीकेशंस ऑफ फिफ्टीन्थ फाइनेंस कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फार फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया'' विषय पर वक्तव्य दिया था तथा अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, भोपाल के 27 अगस्त, 20;18 से 7 दिसम्बर, 2018 के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं एवं केन्द्रीय सेवाओं (समूह क) के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित 93वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम में उन्होंने 30 अक्तूबर, 2018 को भोपाल में फिस्कल सिस्टम तथा मोनेट्री सिस्टम, स्टेबिलाइजेशन बाई फिस्कल पालिसी एंड मोनेट्री पालिसी, इम्पोसिबल ट्रिंटी एंड करंट इंडियन थिंकिग आन मैक्रो एंड फाइनेंस पालिसी पर वक्तव्य प्रस्तुत किए थे।

उनके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबद्ध अनुसंधान स्कालरों अध्यापकों के लिए 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2018 के दौरान इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, वसंत कुंज, नई दिल्ली में समाज विज्ञान अनुसंधान के 10 दिव्सीय अनुस्थापन पाठ्यक्रम में दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 को चेंजिंग नेचर ऑफ फिस्कल फेडरेशन इन इंडिया, विषय : फिस्कल कंसोलिडेशन एंड डेब्ट सस्टेनेबिल्टी पर वक्तव्य प्रस्तुत किया गया तथा 10-21 दिसम्बर, 2018 के दौरान एनआईपीएफपी में आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग के मामलों पर ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिज इन पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी पर 10 दिसम्बर, 2018 को वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। एनआईपीएफपी में 21 तथा 23 जनवरी, 2019 को उन्होंने आईएएएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए आयोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंटर गर्वनमेंट फिस्कल ट्रांसफर्स तथा एआरबीएम, फिस्कल पालिसिज एवं डेब्ट सस्टेनिबिल्टी पर वक्तव्य प्रस्तुत किए थे। केरल सरकार द्वारा उन्हें वित्त मंत्रियों, दक्षिणी राज्यों के वित्त सचिवों तथा अर्थशास्त्रियों के साथ तिरूवनंतपुरम में दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को आयोजित एक दिव्सीय कार्यशाला में वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत मामलों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। वे भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के वार्षिक अनुसंधान

सम्मेलन में कालेज ऑफ एग्रीक्लचरल बैंकिंग में दिनांक 3-4 मई, 2018 को पुणे में ''फिस्कल रिस्क एंड मोनेट्री पालिसी'' के विषय पर पैनल चर्चा में पैनलबद्ध के रूप में आमंत्रित किए गए थे। इंटरगर्वनमेंट फिस्कल रिसोर्सिज: द रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट फाइनेंस कमीशन इन काठमाण्डु, नेपाल में दिनांक 28-29 जून, 2018 के संबंध में फोरम ऑफ फेडरेशन्स, ओटावा ने उन्हें नेशनल नेचुरल रिसोर्सिज तथा फाइनेंस कमीशन ऑफ नेपाल द्वारा आयोजित बैठक में आमंत्रित किया था। वे मणिपुर तथा हुबली में 15वें वित्त आयोग के परामर्श सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित थे।

फोरम ऑफ़ फ़ेडरेशन और कोनराड एडेनॉयर स्टेफ़टंग द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर एंड लोकल गर्वनमेंट (डीआईएलजी) तथा सेंटर फार फ़ेडरलिज़्म एंड कॉन्स्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म के संयोजन से आर्थिक संघवाद के तुलनात्मक व्यवहारों तथा फिलिपिंस में संघीय व्यवस्था की व्यवहार्यता पर विचार विमर्श के लिए फिलिपिंस के संघीय संविधान के मसौदे पर मनीला में दिनांक 6-7 सितम्बर, 2018 को आयोजित समारोह के अवसर पर वक्तव्य दिया तथा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को ईवाई इंडिया तथा मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ''भारत में आर्थिक संघवाद : समकालीन परिप्रेक्ष्य पर आयोजित गोलमेज चर्चा में प्रतिभागिता की।

उन्होंने निम्नलिखित प्रकाशनों के लिए सह-लेखन किया है – एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स 2017-18 : एमर्जिंग इश्यूज (इम्पैक्ट ऑफ पावर सेक्टर डेब्ट – उदय आन स्टेट फाइनेंसिस), दिसम्बर, 2018, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान , नई दिल्ली तथा कैन द ब्रिक्स पार्टनरशिप चेंज सबनेशनल फिस्कल बिहेवियर? के विषय पर एक अध्याय में योगदान। स्टेनटल्र निको (सम्पादित) में एन इंडियन फेडरलिज्म पर्सपेक्टिव, द ब्रिक्स पार्टनरशिप चैलेंजिस एंड प्रोस्पैक्टस फार मल्टीलेवल गर्वनमेंट, जेयूटीए, साउथ अफ्रीका। उन्होंने विनोद राय एवं अमितेन्दु पालित (सम्पादित), सेवन डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया (2018) में टैक्स पालिसी डिजायन एंड डेवलपमेंट: द इंडियन स्टोरी के शीर्षक के एक अध्याय का लेखन भी किया है।

उन्होंने दो अकादमिक संदर्भित जनरलों – फिस्कल प्रेशर ऑफ माइग्रेशन एंड होरिजेन्टल फिस्कल इनइक्वेलिटी : इविडेंस फ्राम इंडियन एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल माइग्रेशन, एंड फेडरल फिस्कल एसीमेट्रिस तथा इकॉनोमिक गर्वनेंस: इविडेंस फ्राम इंडियन स्टेट्स, एशिया पैसेफिक जरनल ऑफ रिजनल साइसेंस, स्प्रिंगर, भाग 2, पीपी 83-113 के दो पेपरों का सह-लेखन भी प्रकाशित किया है। उनके द्वारा फेडरेलिज्म, फिस्कल एसीमेट्रिस एंड इकानोमिक कनवर्जेंस : इविडेंस फ्राम इंडियन स्टेट्स शीर्षक का एक कार्यशील पेपर प्रकाशित किया गया है। अप्रैल, 2018 में उन्होंने फाइनेंशियल न्यूजपेपर मिन्ट में 15 फाइनेंस कमीशन: इज इट जस्ट ए साउथ इंडिया वर्सिस नार्थ इंडिया डिबेट?शीर्षक का एक कालम प्रकाशित किया है।

उन्होंने केरल सरकार द्वारा उन्हें केरल वित्त के वित्तीय इतिहास के समेकन के लिए गठिन पैनल में सदस्य के रूप सेवाएं प्रदान की हैं।

रीता पांडे

डा.रीता पांडे द्वारा 16 जुलाई को क्लाइमेट बोन्डस एवं फिक्की द्वारा लन्दन में आयोजित 'ड्राइविंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीन फाइनेंस : इंडिया-यूके डायलॉग में प्रतिभागिता की गई है। उन्हें लन्दन में 17 जुलाई को आयोजित 'ग्रीन फाइनेंस सम्मिट 2018 – मेनस्ट्रीमिंग ग्रीन फाइनेंस'' में प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें नीति आयोग, भारत सरकार तथा मैटिरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 6 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित ''इंटरनेशनल कांफ्रेंस आन सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रु मैटिरियल रिसाइकलिंग : पालिसी प्रेसक्रिप्शंस'' में तथा जीआई, यूरोपियन यूनियन एवं नीति आयोग द्वारा 6-8 सितम्बर, 2018 को आयोजित 'सर्कुलर इकॉनोमी मिशन'' के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ता के तौर पर एवं अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया था।

केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में 11-14 सितम्बर, 2018 को आयोजित यूआरबीआईओ इंटरनेशनल नेटवर्क फार अर्बन बायोडायवर्सिटी एंड डिजायन सम्मेलन में ''मोबिलाइजिंग बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इन इंडिया : चैलेंजिस एंड ओर्पोच्युनिटीज''

की अध्यक्षता उन्होंने की थी तथा सिंगापुर में दिनांक 2-31 अक्तूबर, 2018 को आयोजित बॉयोडायवर्सिटी इंडेक्स फार सिटिज : ए डायग्नोस्टिक, प्लानिंग एंड पालिसी टूल की कार्यशाला में उन्होंने वक्तव्य दिया था; श्रम अल शेख, मिस्त्र में 19-25 नवम्बर, 2018 को सीबीडी सीओपी 13 में वे प्रतिभागिता तथा वक्ता के रूप में आमंत्रित की गई थी; उनके द्वारा 'रिविजटिंग स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रैटरजी एंड एक्शन प्लान्स एंड रिर्सोस मोबिलाइजेशन स्ट्रैटरजिस फार इट्स मोबिलाइजेशन पर 14 दिसम्बर को शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक कार्यशाला का आयोजन एवं प्रस्तुति दी गई थी तथा गंगटोक, सिक्किम में 20 दिसम्बर को आयोजित कार्यशाला में उन्होंने 'रिसोर्सिज मोबिलाइजेशन स्ट्रैटरजिस फार इम्पलीमेंटिंग द सिक्किम बॉयोडायवर्सिटी स्ट्रैटरजी एंड एक्शन प्लान पर वक्तव्य दिया था।

समितियों में नियुक्ति: राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित ''रिव्यु द गाइडलाइंस आन एबीएस एंड एसोसिएटिड नोलेज एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशंस, 2014 एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट्स मिजर्स'' की विशेष समिति के लिए जनवरी 2019 – अप्रैल, 2019 के दौरान नामित किया गया था; तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में उन्हें एक्सपर्ट ग्रुप आन एनवायरनमेंट डैमेज एस्सेसमेंट के लिए नामित किया गया था।

इला पटनायक

डा. इला पटनायक ने 14 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में सेन्टर फार पालिसी रिसर्च एंड कार्नेजी एंडोवमेंट द्वारा ''इंडियाज अपेक्स इंस्टीट्यूट्स'' पर आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यशाला में प्रधान वक्ता के रूप में प्रतिभागिता की थी।

इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (आईएसएएस), नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड एस राजाजलउम स्कूल और इंटरनेशनल स्टडीज (आरएसआईएस), नयंग टैक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा 28 फरवरी से 1 मार्च के दौरान सिंगापुर में संयुक्त रूप से आयोजित ''इंडिया – राइजिंग पावर इन एन एज ऑफ अनसर्टिनिटी'' की कार्यशाला में इकॉनमिक चैलेंजिस इन इंडियाज एर्मजेंस : रिफोर्मस एंड द ट्रेड टेंशंस के सत्र में उन्होंने प्रतिभागिता की तथा ''फाइनेंशियन सेक्टर रिफार्मस इन इंडिया'' के विषय पर अपनी प्रस्तुति दी थी। राजस्थान के महालेखाकार द्वारा 18-19 फरवरी, 2019 को जयपुर में आयोजित ''हायर एजुकेशन'' तथा ''मेडिकल केयर डिलीवरी इन ईएसआई हॉस्पिट्ल्स'' की कार्यशाला में उन्होंने पैनल विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया था। हर्टलैंड स्टोरिज द्वारा भोपाल में 12-14 जनवरी, 2019 के दौरान भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टीवल में उन्होंने ''द पैथ अहेड – ट्रांसफोर्मेटिव आइडियाज फार इंडिया'' पर आयोजित चर्चा में उन्होंने भाग लिया था। नई दिल्ली में दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को आइडियाज फार इंडिया द्वारा आयोजित ''द वे फारवर्ड फार द इंडियन इकॉनोमी'' पर आयोजित पैनल चर्चा में उन्होंने भाग लिया था। ''नेविगेटिंग इंडियाज 21 सेंच्युरी ट्रांजिशन्स'' विषय पर 17 दिसम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित सीपीआर डायलाग 2018 में सेंटर फार पालिसी रिसर्च के आयोजन में उन्होंने भाग लिया था; नेशनल काउंसिल फार एपलायड इकॉनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा निमराना फोर्ट पैलेस, जिला अलवर, राजस्थान में 14-16 दिसम्बर, 2018 को आयोजित 20वें निमराना सम्मेलन में निमराना राउंडटेबल : पालिसी प्रायर्टिज में उन्होंने भाग लिया था।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेन ट्रेड (आईआईएफटी) द्वारा नई दिल्ली में 13 दिसम्बर, 2018 को आयोजित ''एम्पीरिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस'' के छठे अनुसंधान सम्मेलन में वैल्यु एडिड एंड इन्फ्रा इंडस्ट्री के टैक्नीकल सेशन में उन्होंने भाग लिया था तथा अध्यक्षता की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकके कार्यालय द्वारादिसम्बर 10, 2018 को नई दिल्ली में उनके कार्यालय में आयोजित ''इम्प्रुविंग एजुकेशन आउटकम्स'' की कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया तथा जर्मन मार्शल फंड ऑफ द यूनाइटिड स्टेट्स (जीएमएफ) एवं द स्विडिश मिनिस्ट्री फार फोरेन अफेयर्स द्वारा 29-30 नवम्बर को स्टॉकहोम, स्वीडन में आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित 15 इंडिया ट्राइलेटरल फोरम में ''ग्लोबल ट्रेड नार्मस अंडर प्रेशर'' के सत्र में भाग लिया था।

विनय, नई दिल्ली तथा इंस्टीट्यूट फार न्यू इकॉनोमिक थिंकिंग, न्यूयार्क द्वारा 27-28 नवम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित

तीसरे लॉ इकॉनोमिक्स पालिसी कांफ्रेस आन हैल्थ में उन्होंने भाग लिया तथा स्वागत वक्तव्य की प्रस्तुति की थी। नई दिल्ली में दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को ब्रुकिंग इंडिया के आयोजित ''नॉन-पर्फार्मिंग एस्सेट्स एंड स्लो पैथ टू बैंक रिफार्मस'' के सेमिनार में हुई परिचर्चा में उन्होंने भाग लिया था। नई दिल्ली में विश्व बैंक द्वारा 12-13 नवम्बर, 2018 को आयोजित ''डिजास्टर रिस्क मैनेजमें (डीआरएम) फाइनेंसिंग इन इंडिया'' की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में आयोजित टॉकिंग स्टाक ऑफ इक्जिस्टिंग फंड्स इन इंडिया : करंट स्टेट्स एंड कम्पेरेटिव एक्सपीरियंस फ्राम अदर फेडरल एंड हाई रिस्क कंट्रीज के सत्र में पैनलबद्ध के रूप में उन्होंने प्रतिभागिता की थी। 19 अक्तूबर, 2018 को अंकारा, टर्की में ''ट्रेड इन नेशनल करंसीज : चैलेंजिस एंड ओपोरच्युनिटिज'' विषय पर द सेंटर फार इरानियन स्टडीज इन अंकारा (आईआरएएम) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैनल में वक्ता के रूप में वे उपस्थित हुई थीं। विश्व बैंक ग्रुप द्वारा काठमांडु, नेपाल में 17-18 सितम्बर, 2018 को हाउ इम्पोरेटेंट इज फिस्कल पालिसी इन साउथ एशिया ? के सत्र में आयोजित चर्चा में प्रारम्भ विचार प्रस्तुत करने के साथ साथ उन्होंने ''रिजनल वर्कशाप आन फिस्कल पालिसी इन साउथ एशिया'' के विषय पर विशेष वक्तव्य भी प्रस्तुत किया था तथा नेपाल इकॉनोमिक फोरम द्वारा विश्व बैंक ग्रुप के साथ 18 सितम्बर, 2018 को काठमांडु, नेपाल में आयोजित ''फिस्कल फेडरेशन इन नेपाल'' के प्रमुख सत्र में पालिसी पैनल के रूप में भाग लिया था। ओडिश डेवलमेंट इनिशियेटिव द्वारा 24-26 अगस्त, 2018 को भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा डेवलमेंट कांकलेव में रिसाइलेंट ओडिशा के थीम के अंतर्गत ''फाइनेंसिंग फार रिसाइलेंस बिल्डिंग'' के सत्र में वक्तव्य दिया था। नई दिल्ली में 23 अगस्त, 2018 को सेन्टर फार इकॉनोमिक पालिसी रिसर्च द्वारा ''इंडिया कांकलेव 2018'' में इंडियन डेब्ट, इंडियन प्रोब्लम, इंडियन साल्युशन की पैनल चर्चा में उन्होंने प्रतिभागिता की थी।

उन्होंने कंफिड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा आस्ट्रेलियन उच्चायोग के साथ साझेदारी से 20 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित ''इंडिया इकॉनोमिक स्ट्रेटजी टू 2035 : नेवीगेटिंग फ्राम पोटेंशियन टू डिलीवरी'' तथा एनर्जी पालिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो (ईपीआईसी-इंडिया) तथा टाटा सेंटर फार डेवलपमेंट एट यू शिकागो (टीसीडी) में द्वारा नई दिल्ली में 13 अगस्त, 2018 को आयोजित ''नेशनल कांफ्रेंस आन इनोवेशन इन पाल्युशन रेगुलेशन'' के सत्र में भाग लिया है। आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा मैकआर्थर फाउंडेशन के सहयोग से 18 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित ''फाइनेंसिंग ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस एंड क्लाइमेंट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया'' की कार्यशाला में ब्रिजिंग द इंटरनेशनल गैप-टैक्नीकल एनालिजिज के सत्र में उन्होंने परिचर्चा तथा प्रतिभागिता की है। डा. पटनायक द्वारा नई दिल्ली में 10-11 जुलाई, 2018 को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनोमिक रिसर्च द्वारा आयोजित इंडिया पालिसी फोरम में ''द इम्पेक्ट ऑफ टैक्स ब्रेक्स आन हाउसहोल्ड फाइनेंशियन सेविंग्स'' शीर्षक युक्त पेपर की प्रस्तुति की गई तथा प्रतिभागिता की गई।

नई दिल्ली में दिनांक 3 जुलाई, 2018 को आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ओर्गनाइजेशन फार इकॉनोमिक कोओपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) के साथ सहकारिता से आयोजित इनवेस्टिंग इन ए लो-कार्बन इंडिया के सत्र में ''इनवेस्टिंग इन द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर फार लो-कार्बन डेवलपमेंट'' पर तथा नई दिल्ली में दिनांक 28 जून, 2018 को स्कूल ऑफ पोलिसी एंड गवर्नेंस द्वारा आयोजित ''बिल्डिंग ए हैल्थकेयर पालिसी इकोसिस्टम इन इंडिया'' की कार्यशाला में कॉनटैक्टूलाइजिंग यूनिवर्सल हैल्थ कवर के सत्र में अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए।

उन्होंने गोवा में दिनांक 15-17 जून, 2018 को आईडीएफसी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित आईडीएफसी इंस्टीट्यूट पोल्टिकल इकॉनोमी डायलॉग; कारनेज इंडिया द्वारा फुंडाकाओ ओरियन्टे तथा यूरोपियन काउंसिल आन फोरेन रिलेशंस के संयोजन से 7-8 जून, 2018 को लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित ''इंडिया स्ट्रेटजी ग्रुप'' की बैठक में बिल्डिंग ब्लॉक्स टूवार्ड इन्क्रीज्ड ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट के सत्र में; एशियन डेवलमेंट बैंक द्वारा 30-31 मई, 2018 को मनीला, फिलिपिंस में आयोजित ''मैंनटेंनिंग मैक्रोइकॉनोमिक स्टेबिल्टी इन द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट'' शीर्ष कार्यशाला में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2018 अपडेट थीम चेप्टर में; एशियन डेवलमेंट बैंक इंस्टीट्यूट (एडीबीआई) द्वारा ओर्गनाइजेशन फार इकॉनोमिक कोओपरेशन एंड डेवलमेंट (ओईसीडी) तथा एशिया डिजास्टर प्रिपेयरडनेस सेन्टर (एडीपीसी) द्वारा 8-9 मई, 2018 को बैंकाक में आयोजित ''डेवलपिंग द एलीमेंट्स ऑफ ए डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग स्ट्रैटजी'' शीर्षक युक्त कार्यशाला में प्रतिभागिता की है।

उन्होंने इंडिया फाउंडेशन द्वारा 27-28 अप्रैल, 2018 को मुम्बई में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक सम्मिट 2018 में भाग लिया तथा विनय, नई दिल्ली द्वारा 21-25 जनवरी, 2019 को आयोजित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों

के पब्लिक फाइनेंस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ''कंटैम्पोरेरी इश्यूज इन मैक्रोइकॉनोमिक्स'' विषय पर अपना वक्तव्य दिया तथा विनय, नई दिल्ली द्वारा 17-21 दिसम्बर, 2018 को आयोजित ''पब्लिक इकॉनोमिक्स फार यूनिवर्सिटी टिचर्स एंड रिसर्चर्स'' के 12वें एनआईपीएफपी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में ''फाइनेंशियल सेक्टर रिफार्मस'' पर वक्तव्य की प्रस्तुति की। उनके द्वारा विनय, नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनमेंट एकाउंटस एंड फाइनेंस (आईएनएफएएफ), वित्त मंत्रालय के समन्वय से 10-21 दिसम्बर, 2018 को भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी के दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''मोनेट्री पालिसी इन इंडिया'' के विषय पर वक्तव्य दिया है। विनय, नई दिल्ली द्वारा 10-14 दिसम्बर, 2018 को आईए एवं एएस अधिकारियों के लिए आयोजित एक सप्ताह के एडवांस्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम (एएमडीपी) में उन्होंने ''फाइनेंशियल सेक्टर रिफार्म्स'' तथा विनय, नई दिल्ली द्वारा 9-20 अप्रैल, 2018 को भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए आयोजित एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी के दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''डिजास्टर रिस्क एंड रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग'' विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं।

समितियों, कार्यकारी समूहों, कार्य बलों में सदस्यता : सदस्य, अकादमिक काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेन ट्रेड, नई दिल्ली तथा सदस्य, टास्क फोर्स टू प्रिपेयर ए प्लान फार द इस्टैबिलिशमेंट ऑफ कोयेलिशन फार डिजास्टर रिसाइलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई)।

आर.कविता राव

डा. आर.कविता राव द्वारा एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित दो सप्ताह के पब्लिक फाइनेंस पाठ्यक्रम में जनवरी 21, 2018 को ''अनएकाउंटिड इंकम्स एंड वैल्थ इन इंडिया'' तथा दिनांक जनवरी 28, 2018 को ''जीएसटी इन इंडिया – वेयर डू वी स्टैंड?'' के विषयों पर दो वक्तव्य तथा दिनांक 19 दिसंबर, 2018 को एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए पब्लिक इकॉनोमिक्स के दो सप्ताह की अवधि के 12वें पुनश्चर्या कार्यक्रम में ''टैक्स एक्जम्शन'' पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने दिनांक 14 दिसंबर, 2018 को ''अनएकाउंटिड इंकम'' तथा ''जीएसटी''पर दो वक्तव्य प्रस्तुत किए तथा आईए एंव एएस अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के एडवांस्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट कार्यक्रम में ''जीएसटी''के विषय पर उद्घाटन वक्तव्य प्रस्तुत किया था तथा आईसीएएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अप्रैल 9, 2018 को एमर्जिंग इश्यूज उद्घाटन वक्तव्य प्रस्तुत किया था । डा.राव ने एनआईपीएफपी द्वारा गुवाहाटी में दिनांक मार्च 27, 2019 को आयोजित फिस्कल फेडरेशन की राउंडटेबल कार्यशाला में ''इश्यूज इन जीएसटी रिफार्म्स'' पर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। उन्होंने एनआईपीएफपी द्वारा भुवनेश्वर में इश्यूज इन टैक्सेशन एंड टैक्स रिफार्म्स इन इंडिया पर आयोजित चरण 2-के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनोवेटिव इफैक्ट्स आन पब्लिक फाइनेंस पर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था।

अजय शाह

डा. अजय शाह ने एडवोकाटा इंस्टीट्यूट द्वारा 28 फरवरी – 1 मार्च, 2019 के दौरान कोलम्बो में आयोजित एशिया लिबर्टी फोरम 2019 में ''कंरसी डैपरीसिएशन एंड इट्स कांसिक्वेंस'' के विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में वक्ता के रूप में प्रतिभागिता की; बाल्टीमोर, मैरीलैंड में 26-27 मार्च, 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित डब्ल्यूएचओ नोलेज प्रोग्राम आन फाइनेंसिंग कॉमन गुड्स फार हैल्थ – टैक्नीकल एक्सपर्ट बैठक में ''इश्यूज एंड मैकेनिज्म टू फाइनेंस कॉमन गुड्स फार हैल्थ एट द कंटरी लैवल'' के सत्र की पैनल चर्चा में भाग लिया; नई दिल्ली में 18-19 मार्च, 2019 को आयोजित एनआईपीएफपी टैक्नोलॉजी पालिसी द्वारा आयोजित रेग्युलेटरी प्रेक्टिसिस एंड इकॉनोमिक एनालिजज फार एन आईसीटी रेग्यूलेटर की कार्यशाला में ''फाउंडेशन ऑफ पब्लिक इकॉनोमिक्स – मार्केट फेलियर वर्सिस स्टेट कैपेसिटी'' तथा ''इविडेंस बेस्ट डिस्जिन मेकिंग बाई रेग्युलेटर्स'' पर वक्तव्य प्रस्तुत किए।

जयपुर में दिनांक 18-19 फरवरी, 2019 को प्रधान महालेखाकार, राजस्थान द्वारा ''हायर एजुकेशन'' एवं ''मेडिकल केयर डिलीवरी'' के विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने विशेषज्ञ पैनलिस्ट की सेवाएं प्रदान की हैं; नई दिल्ली में 14 फरवरी, 2019 को बिजनेस टूडे द्वारा आयोजित बिजनेस टूडे माइंडरश – रिब्रेन अथवा रॉट में ''फायरसाइड चैट'' की पैनल चर्चा में आपने भाग लिया; टीमवर्क आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जयपुर में 24 जनवरी, 2019 को आयोजित जी जयपुर लिट्रेचर फैस्टीवल 2019 में उन्होंने ''द लास्ट माइल : हैल्थकेयर इन इंडिया'' की पैनल चर्चा में भाग लिया।

सेन्टर ऑफ सिविल सोसायटी द्वारा 2-3 फरवरी, 2019 को आयोजित पोल्टिक्स ऑफ डेवलमेंट के आवासीय पाठ्यक्रम में उन्होंने ''टू रेगुलेट ऑर नॉट टू रेगुलेट'', ''इंडियाज एप्रोच टू पब्लिक सर्विस पेंशन रिफोम : वट आर द रिमेनिंग चैलेंजिस एंड लैसन्स फार द रिजन?'' के सत्र में भाग लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए ; तथा विश्व बैंक द्वारा 17-18 जनवरी, 2019 को बैंकाक, थाइलैंड में आयोजित चैलेंजिस एंड रिफार्म ऑप्शंस इन साउथ एशियन पब्लिक सर्विस पेंशंस स्कीम्स की कार्यशाला में भारत, मालदीव्स तथा भूटान से आए प्रतिनिधियों के साथ सौम्य पैनल चर्चा में भी प्रतिभागिता की।

नई दिल्ली में 10 जनवरी, 2019 को ओब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा एकाउंटेबिल्टी गैप इन साइबरस्पेस के विषय पर आयोजित मध्याह्न भोजन बैठक में उन्होंने प्रतिभागिता की ; भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय मेंजनवरी 7, 2019 को आयोजित ''बी.आर.अम्बेडकर लेक्चर सीरिज' में उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर रिफार्म्स एंड लेगिसलेशन बाई जस्टिस (रिटायर्ड) बी.एन. श्रीकृष्णा पर वक्तव्य प्रस्तुत किया; इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट चेन्नै सेंटर द्वारा चेन्नै मैथेमिटिक्ल इंस्टीट्यूट के साथ 17-20 दिसम्बर, 2018 को चेन्नै में ''द स्टैटिस्टिक्ल मैथड्स इन फाइनेंस, 2018'' पर संयुक्त रूप से आयोजित द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजिम्स: रिसेंट डेवलमेंट्स एंड पोसिबिल्टिज फार न्यू रिसर्च विषय पर सम्पूर्ण चर्चा; इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर) द्वारा वन्डेरबिल्ट लॉ स्कूल के साथ 13-15 दिसम्बर, 2018 को मुम्बई में आयोजित ''नाइन्थ एमर्जिंग मार्किट्स फाइनेंस कांफ्रेस 2018'' में फाइनेंशियल क्राइसिस के सत्र में विचार प्रस्तुति; भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकके कार्यल द्वारा 10 दिसम्बर, 2018 को नई दिल्ली में ''इम्प्रुविंग एजुकेशन आउटकम्स'' की कार्यशाला में प्रतिभागिता; द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल द्वारा नई दिल्ली में 6-7 दिसम्बर, 2018 को आयोजित ''लाइफ इन इंडियाज स्लम्स'' के सम्मेलन में प्रतिभागिता।

डा.शाह द्वारा ओपन डिस्कशन्स में मोडरेटर के रूप में की गई प्रतिभागिता : विनय, नई दिल्ली द्वारा 4 दिसम्बर, 2018 को ''द वे फारवर्ड फार पर्सनल इंसोवेंसी इन द आईबीसी'' पर आयोजित गोलमेज चर्चा; तथा ''द राइस ऑफ गर्वनमेंट फंडिड हैल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया'' में रेगुलेशन ऑफ हैल्थ इंश्योरेंस के दौरान प्रस्तुति तथा विनय, नई दिल्ली एवं इंस्टीट्यूट फार न्यू इकॉनोमिक थिंकिंग, न्यूयार्क द्वारा 27-28 नवम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित थर्ड लॉ इकॉनोमिक्स पालिसी कांफ्रेस आन हैल्थ, 2018 के समापन अवसर पर प्रस्तुति दी गई।

उन्होंने नई दिल्ली में 24 नवम्बर,2018 को इंसोवेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) द्वारा आयोजित आईबीबीआई के वक्तव्यों में प्रतिभागिता की तथा ''मार्केट फेलयर्स एंड द रोल फार रेगुलेशन'' के विषय पर विचार प्रस्तुत किए और मुम्बई में दिनांक 17 नवम्बर, 2018 को आल्मस रिस्क कंसलटिंग द्वारा आयोजित ''आल्मस फिफ्थ एनुअल कांफ्रेस'' में समापन प्रस्तुति प्रस्तुत की थी।

नई दिल्ली में दिनांक 13-14 नवम्बर, 2018 को आईएनएसओएल इंडिया द्वारा आयोजित ''आईएनएसओएल इंडिया एनुअल कांफ्रेंस 2018'' में लैसन्स एंड लर्निंग्स फ्राम 2 ईयर्स ऑफ आईबीसी, स्पेशल फोकस आन द टॉप 40 एकाउंटस के सत्र तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकके कार्यालय द्वारा 31 अक्तूबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित ''बी.आर. अम्बेडकर लेक्चर सीरिज'' में पैनेलिस्ट के रूप में प्रतिभागिता की थी। उन्होंने गोपनीयता, आधार और राज्य पर सत्र को संचालित किया, ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर प्रस्तुति दी तथा विनय, नई दिल्ली द्वारा फ्रिड्रिच नौमान्न फाउंडेशन एवं ओमिदया नेटवर्क के सहयोग से 30 अक्तूबर, 2018 को मुम्बई में आयोजित ''रेगुलेटिंग एमर्ज़िंग टैक्नोलॉजी'' के सम्मेलन तथा लीगल ईरा पत्रिका द्वारा 21 सितम्बर, 2018 को मुम्बई में द न्यू विन्डो टू रिस्ट्रकचरिंग यूवर बिजनेस'' की थीम पर आयोजित थर्ड एनुअल इंसोवेंसी सम्मिट 2018 में हाउ टू मेक आईसी प्रोस्सेस मोर इफेक्टिव के सत्र में समापन टिप्पणियां प्रस्तुत की तथा नई दिल्ली में दिनांक 4 सितम्बर,2018 को ओब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ''ओवरवियू ऑफ द वीडियो-आन-डिमांड इंडस्ट्री इन इंडिया'' पर आयोजित गोलमेज चर्चा में भाग और विनय, नई दिल्ली द्वारा 5 सितम्बर, 2018 को को नई दिल्ली में आयोजित ''प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन के सम्मेलन में पेपर की प्रस्तुति की एवं समापन टिप्पणियां प्रस्तुत की।

डा. शाह द्वारा "हाउ इज आईबीसी वर्किंग?" के सत्र की परिचर्चा में भाग लिया गया तथा इनसोंलवेंसी एंड बेंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया एवं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च द्वारा 3-4 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित ''इंसोलवेंसी एंड बेंकरप्टसी रिफार्म्स कांफ्रंस'' में चैलेंजिस पोस्ट आईआरपी के पैनल में संयोजक की भूमिका निर्वाह किया तथा विश्व बैंक द्वारा 2 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में ''वर्ल्ड बैंक इन द ह्यूमन डेवलमेंटर सेक्टर : एन इनवीटेशन टू इंटरएक्ट विद हार्ट स्काफर, वाइस प्रेजीडेंट, साउथ एशिया रिजन, वर्ल्ड बैंक की गोलमेज चर्चा में प्रतिभागिता की थी।

उन्होंने 16 जुलाई, 2018 को लन्दन में सिटी ऑफ लंदन द्वारा आयोजित ''इंडियन सोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड : रिसेंट ज्यूरिसप्रुडेंस, डेवलपमेंट एंड ओपरच्युनिटिज फार डिपनिंग द यूके-इंडिया लिंक्स'' की गोलमेज चर्चा में संयोजक की भूमिका निभाई तथा नई दिल्ली में दिनांक 10-11 जुलाई, 2018 को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनोमिक रिसर्च द्वारा आयोजित ''फिफटिन्थ इंडिया पालिसी फोरम 2018'' में भाग लिया। उन्होंने गोवा में 15-17 जून, 2018 को आईडीएफसी द्वारा आयोजित आईडीएफसी इंस्टीट्यूट पोल्टिकल इकॉनामी डायलॉग में भाग लिया।

बंगलौर में 23-24 मई, 2018 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीद्वारा आयोजित एमर्जिंग टैक्नोलोजिस इनोवेशन, कम्पीटिशन एंड रेगुलेशन की कांफ्रेस में ''रेगुलेटिंग एमर्जिंग टैक्नोजिस'' के सत्र की अध्यक्षता की तथा ''कम्पीटिशन इश्यूज इन द आनलाइन इकॉनोमी'' पर वक्तव्य प्रस्तुत किया तथा समापन टिप्पिणयां प्रस्तुत की।

नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड एकाउंट्स, शिमला द्वारा 22-26 अक्तूबर, 2018 को शिमला में इंडियन ऑडिट एवं एकाउंट सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित 5 दिव्सीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''स्टेट्युरी रेगुलेटरी एजेंसिज'' एवं ''मैक्रमोइकॉनोमिक एंड फाइनेंस डेवलमेंट'' तथा मसूरी में दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के चरण IV में ''रेगुलेशन'' के संयुक्त सत्र में; तथा मसूरी में दिनांक 19 जून, 2018 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के चरण V में ''इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी इश्यूज'' पर उन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किए।

लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी द्वारा मसूरी में दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के चरण III में ''रेगुलेशन'' पर वक्तव्य दिया गया। विनय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 9-20 अप्रैल, 2018 के दौरान नई दिल्ली में भारतीय सिविल लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी विषय पर आयोजित दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''स्टेट कैपेसिटी'' तथा ''फाइनेंशियल सेक्टर रिफार्मस'' पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए।

डा. शाह निम्नलिखित के सदस्य हैं : सदस्य, कम्पीटिशन लॉ रिव्यू कमिटी के अंतर्गत गठित वर्किंग ग्रुप आन रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, नवम्बर, 2018; सदस्य, दूरसंचार विभागआईटीयू-टी एसजी3 टैरिफ्स एंड एकाउंटिंग मैटर्स फार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस सर्विसेज 2017–2020; कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के कार्यान्व्यन के लिए गठित इंफोरेमेशन यूटिलिटिज के कार्यकारी समूह में सदस्य; सेन्टर फार मोनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी प्राइवेट लिमिटेड, 1993; निदेशक मंडल, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल लिमिटेड, 2006; निदेशक मंडल, नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 2014; निदेशक मंडल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2017;

एच.के.अमरनाथ

डॉ. अमरनाथ ने "हाफ डे नेशनल कंसल्टेशन ऑन चाईल्ड बजटिंग इन इंडिया : टूवार्डस बैटर इनवेस्टमेंट फार द रियलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन्स राईट " समन्वय किया जिसका आयोजन सेव द चिल्ड्रेन्स एंड नेशनल कोयलिशन फार एज्यूकेशन (एनसीई), एनआईपीएफपी, नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में 20 दिसंबर, 2018 को किया गया था | वे सेव द चिल्ड्रन, एनआईपीएफपी एवं नेशनल कोयलिशन फार एज्यूकेशन, नई दिल्ली द्वारा 20 दिसंबर, 2018 को आयोजित नेशनल कंसल्टेशन कांफ्रेस के प्रमुख वक्ता था | वे सहज द्वारा इक्विल मिजर 2030, दिल्ली के साथ 23 अक्तूबर, 2018 को आयोजित बजट्स फार एसडीजी स्पैशियली द एलोकेशंस फार एसडीजी रिलेटिड टू जेंडर इक्विलिटी अर्थात् एसडीजी 5, नेशनल कंसलटेशन आन लिविंग नो वन बिहाइंड कंजर्वेशंस एराउंड : एसडीजी लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए वक्तव्य दिए | उन्होंने भारतीय सिविल सेवा, आईएनजीएएफ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में दिनांक 9 अगस्त, 2018 को इंडियन बजट मेकिंग

प्रोसेस पर वक्तव्य दिया | उन्होंने सेव द चाईल्ड द्वारा पश्चिम बंगाल, कोलकाता और पटना, बिहार के स्वयंसेवकों के लिए चाइल्ड बजटिंग के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए अक्तूबर 25 एवं 26, 2018 को आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में वक्तव्य प्रस्तुत किए | वे इंटरनेशनल ट्रेनिंग फार इकॉनोमिक कोआपरेशन, आईएनजीएएफ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 11 दिसम्बर, 2018 के लिए इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के विजिटंग संकाय में थे।

लेखा चक्रबर्ती

डा.लेखा चक्रबर्तीको अटलांटा में दिनांक जनवरी 5-3, 2019 को अमेरिकन इकॉनोमिक एसोसिएशन कांफ्रेस में अपने (एईए) शीर्षक (लेखन-सह) पेपर''फिस्कल पालिसी इफैक्टिनैस फार जैन्डर इक्विलिटी एम्पीरिकल एविडेंस फ्राम एशिया पैसिफिक :'' की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था तथा फिस्कल एफेयर्स डिविजन ऑफ इंटरनेशनल मोनेट्री फंड (आईएमएफ), वाशिंगटन डीसी में दिनांक जनवरी 24, 2019 को ''इफक्टिवनैस ऑफ फिस्कल पालिसी आन जैन्डर इक्विलिटी'' के लिए भी आमंत्रित किया गया था। उनके द्वारा ''फेडरल एसिम्मेट्रिस एंड इकॉनोमिक कंवर्जेंस'' के शीर्ष नाम युक्त अपना पेपर पिनाकी) 74वें एनुअल कांग्रेस की प्रस्तुति भी (लेखन-चक्रबर्ती के साथ सहऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ), 2018, टम्पारे सिटी हाल, फिनलैंड में अगस्त 23-21, 2018 को आयोजित द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पालिसिज आन लेबर मार्किट्स एंड इंकम डिस्ट्रीब्यूशनके आयोजन अवसर पर की गई थी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में उन्होंने आईआईसी-एनसीएईआर मालको एडीसेशिह मिड ईयर रिव्यू ऑफ इंडियन इकॉनोमी के आयोजन अवसर पर ''जेन्डर एंड मैक्रो इकॉनोमी'' के विषय पर विशेष वक्तव्य प्रस्तुत किया है, तथा उप्पस्ला यूनिवर्सिटी, स्विडन में सितम्बर, 2018 में उन्होंने ''मैक्रोइकॉनोमिक पालिसी फार जेन्डर इक्विलिटी'' पर प्रस्तुत किया जहां उन्होंने अगस्तसितम्बर-, 2018 के दौरान विजिटंग प्रोफेसर के रूप में दौरा किया था।

डा.चक्रबर्ती नेवाईबुक लांच (2019) रेड्डी.आर.रेड्डी एंड जी.वी.; 'इंडियन फिस्कल फेडरेलिज्म'', मार्च 28 2019 में बिबेक डेबराय, हसीब ड्राबु, मोंटेक सिंह अहलुवालिया तथा एनसिंह के साथ पैनेलिस्ट के रूप में सेवाएं प्रदान की हैं जिसका .के. आयोजन आक्सफोर्ड इंडिया प्रेस तथा आईसीआरआईईआर द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था।

डा.लेखा चक्रबर्ती द्वारा द पोल्टिकल इकॉनोमी ऑफ फिस्कल इंटरवेंशंस टू रिड्रैस जेन्डर इनइक्वैलिटिजएम्पीरिकल एविडेंस : लेखन किया गया है जिसकी प्रस्तुत आईएएफएफई की एसयूएनवाई न्यू पाल्ज-फ्राम इंडिया शीर्ष नाम के पेपर का सह, न्यूयार्क में दिनांक जून 21-19, 2018 को आयोजित बैठक में की गई थी। फिस्कल इंसिडेंस ऑफ पब्लिक हैल्थ सर्विस एप्पलाइंग द डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल कलासिफिकेशन ऑफ डिसिज एविडेंस फ्राम इंडियन स्टेट्स पर लिखे उनके : कोड्स (आईसीडी) पेपर को एसयूएनवाई न्यू पाल्ज, न्यूयार्क में जून, 2018 में आयोजित 27वें आईएएफईई एनुअल कांफ्रेस में स्वीकार किया गया था। उन्होंने आईएचसी, नई दिल्ली में दिनांक अगस्त 3, 2018 को आयोजित आईएसएसटीस्टिफटंग पैनल में -बोयल-हेनरिच- जेंडर इन द पालिसी एंड प्रेक्टिसऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियन इंस्टीट्यूशंस में प्रतिभागिता की थी तथा उन्हें फिक्की एवं आईआईसीएसआर, नई दिल्ली द्वारा दिनांक अगस्त 17, 2018 को आयोजित सस्टेनिबिल्टिी इन एक्सपलोरेशन की प्रस्तुति के लिए नेशनल सम्मिट आन मिनरल एक्सपलोरेशन सस्टेनिबिल्टी फार बुस्टिंग इनवेस्टमेंट्स इन द मिनरल एक्सपलोरेशन के सत्र में आमंत्रित किया गया था।

यूनिसेफ तथा गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर सचिवालय में 20 सितम्बर, 2018 को आयोजित न्यूट्रीशन-पब्लिक एक्सपीडिंचर रिव्यु – पब्लिक फाइनेंस फार चिल्ड्रन (पीएफ4सी) पर एक गोलमेज चर्चा का उन्होंने सूत्रपात किया। कनाडियन उच्चायोग में आयोजित इकॉनोमिक चैलेंजिस बिफोर इलेक्शन पर एक पैनल चर्चा में उन्होंने उेनियल होल्टन, काउंसलर तथा जेस थोमस, पोल्टिकल एवं इकॉनोमिक सैक्रेटरी के साथ भाग लिया। उच्चायोग द्वारा उन्हें 18 मई, 2018 को वुमैन्स इकॉनोमिक एम्पवारमेंट आन द ओकेशन ऑफ द ईयर 2018, जो कनाडा की जी7 प्रेजिडेंसी एवं डब्ल्यूईई द्वारा अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है, पर पैनल चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। महाराजा कालेज फार वुमैन, त्रिवेन्द्रम में 5 जून, 2018 को उन्होंने फिस्कल रूल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ डेफिस्टिस; 19 जून, 2018 को उन्होंने नेशनल रिफ्रेशर प्रोग्राम फार यूनिवर्सिटी फैक्ल्टी,

यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलमेंट फैक्ल्टी, यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के लिए फिस्कल रूल्स एंड मैक्रो पालिसी फार ह्यूमन डेवलपमेंट; जून 2018 में महाराजा गर्वनमेंट कालेज फार आर्ट्स में न्यू फिस्कल रूल्स एंड पब्लिक एक्सपीडिंचर रिकास्टिंग; 28 जून, 2018 को नेपाल में एम.फिल तथा पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, काठमांडु में एफिकेसी ऑफ फिस्कल रूल्स फार डेडरलाइजिंग जैसे विभिन्न विषयों पर वक्तव्य प्रस्तुत किए।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 28 सितम्बर, 2018 को इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वुमैन वर्क एंड देयर चाइल्ड केयर नीड्स'' की कार्यशाला में उन्होंने ''फिस्कल पालिसी इंटरवेंशन्स फार चाइल्ड केयर'' शीर्षक के अपने एक पेपर की प्रस्तुति की; उन्होंने 4 अक्तूबर, 2018 को ह्यूमन सैटलमेंट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हुडको, नई दिल्ली में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ जेन्डर बजटिंग के विषय पर; शास्त्री इंडो-कनाडा इंस्टीट्यूट, आईएचसी, नई दिल्ली में 10 अक्तूबर, 2018 को कनाडा इकॉनोमिक ग्रोथ के विषय पर; भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित पब्लिक पालिसी इनोवेशंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिनांक 13-14 फरवरी, 2019 को जेंडर बजट एंड चाइल्ड बजट्स के विषय पर; 19 फरवरी, 2019 को आरआईएस के आईटीईसी के कार्यक्रम में ''पब्लिक फाइनेंस'' के विषय पर; 24 फरवरी, 2019 को आस्ट्रेलिया उच्चायोग में ''फेडरलिज्म, जेन्डर बजटिंग एंड फाइनेंस कमीशन'' के विषय पर; 11 अप्रैल तथा 18 अप्रैल को आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए आयोजित दो सप्ताह के ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिजरिंग डेफिसिस्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट, एंड फिस्कल स्पेस फार जेन्डर इक्वेलिटी (आन डिमांड) के विषय पर; 18-22 जून, 2018 के दौरान भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के आयोजित पब्लिक फाइनेंस के पाठ्यक्रम में 21 जून को फिस्कल पालिसी एंड जेंडर बजटिंग एंड न्यू फिस्कल रूल्स एंड रिकास्टिंग पब्लिक एक्सपींडिचर के विषयों पर; आईए एवं एएस अधिकारियों के लिए 10-14 दिसम्बर, 2018 को आयोजित एडवांस्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट कार्यक्रम में 12 दिसम्बर, 2018 को जेंडर बजटिंग के विषय पर; आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 10-21 दिसम्बर, 2018 के दौरान ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' पर आयोजित दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एम्पीरिक्स ऑफ पब्लिक एक्सपींडिचर, एंड फिस्कल पालिसी ह्यूमन डेवलपमेंट के विषयों पर दिनांक 11 तथा 15 दिसम्बर, 2018 को; भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 24-28 दिसम्बर,2018 को पब्लिक फाइनेंस के पाठ्यक्रम में 24.12.2018 को पब्लिक एक्सपींडिचर – थियोरी एंड एम्पीरिक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स के विषयों पर वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं।

वे 9-20 अप्रैल, 2018 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीमें आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी पर आयोजित दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यक्रम निदेशक थी। 8 जनवरी, 2019 को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनोमिक्स, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सेवा प्रदान की। उन्हें कनाडा में अपने अनुसंधान प्रकाशनों के लिए इंडो-कनाडा अवार्ड (एसआईसीआई-एमएचआरडी-डीएफएआईटी) प्रदान किया गया है।

उनकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंसकी सदस्यता; फल्बराइट सैलेक्शन बोर्ड की सदस्यता जारी है; उन्होंने उप्पसला यूनिवर्सिटी स्वीडन तथा डिर्पाटमेंट ऑफ इकॉनोमिक्स, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी में विजिटिंग प्रोफेसर; जेएनयू, नई दिल्ली, मुम्बई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटर्सरेंड, जोहान्सबर्ग के लिए पीएचडी थिसिस, सीईएसपी के एक्टर्नल एक्जामिनर की सेवाएं प्रदान की हैं; एप्पलाइड इकॉनोमिक्स, ईपीडब्ल्यू, स्प्रिंगर जरर्लस तथा इंटरनेशनल जरनल ऑफ इकॉनोमिक्स पॉलिसी इन एमर्जिंग इकानोमिस(टेलर एंड फ्रेंसिस) के समीक्षक के रूप में उन्होंने सेवाएं प्रदान की हैं।

प्रताप रंजन जेना

डा. जेन को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 16 अगस्त, 2018 को अपने अधिकारियों के सर्टिफिकेट प्रोग्राम आन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में ''इश्यूज इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स में वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था; जिन्दल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में वे 12 सितम्बर, 2018 को ''कंटैकम्पोरी इश्यूज इन पब्लिक फाइनेंशियन मैनेजमेंट सिस्टम्स" के विषय पर भारतीय राजस्व सेवा (प्रत्यक्ष कर) के अधिकारियों के लिए आयोजित मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम वक्तव्य के आंमत्रित किए गए थे ; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ में आईएनजीएएफ में 29 नवम्बर, 2018 को वे पब्लिक एक्सपींडिचर

मैनेजमेंट के कार्य क्रम में ''पीएफएम पर्फामेंस मिजरमेंट फ्रेमवर्क'' के विषय पर वक्तव्य के लिए आमंत्रित थे; जिन्दल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में 22 नवम्बर, 2018 को उन्होंने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट कार्यक्रम में ''पीएफएम एंड फिस्कल पालिसी इन ए मिडियम टर्म:इश्यूज रिलेटिंग टू पर्फामेंस'' तथा 5 फरवरी, 2019 को ''पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट पर्फामेंस मिजरमेंट फ्रेमवर्क'' के विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए थे। उनके द्वारा आईसीएएस (भारतीय सिविल लेखा सेवा) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' के विषय पर आयोजित कार्यक्रम में दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को ''इश्यूज इन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिफार्म आप्शंस'' के विषय पर वकतव्य दिया गया था। 18 जून, 2018 को भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षधीन अधिकारियों के पब्लिक फाइनेंस पाठ्यक्रम पर उन्होने ''इश्यूज इन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम'' के संबंध में अनेक वक्तव्य दिए थे; 13 दिसमबर, 2018 को आईए एवं एएस अधिकारियों के एडवांस्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट कार्यक्रम में उन्होंने ''कंटैम्पोरेरी इश्यूज इन पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम''; दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को आईसीएएस (भारतीय सिविल लेखा सेवा) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उन्होंने ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' के विषय पर संबोधित किया था; एनआईपीएफपीमें दिसम्बर 21, 2018 को आयोजित ''पब्लिक एक्सपैंडिचर एंड फाइनेंशियल एकाउंटेबिल्टी'' के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में; एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में ही 18 जून, 2018 को भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पब्लिक फाइनेंस के पाठ्यक्रम के लिए ''इश्यूज इन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम'' के विषय पर संबोधित किया था। मधुसुदन दास रिजनल अकादमी ऑफ फाइनेंशियन मैनेजमेंट, भुवनेश्वर में दिनांक 17 तथा 18 जनवरी, 2019 को उन्होंने ''पब्लिक एक्सपैंडिचर एंड फाइनेंशियल एकाउंटेबिल्टी'' तथा ''पीएफएम एंड फिस्कल पालिसी: बजटिंग एंड पफर्मामेंस'' के विषय पर दो वक्तव्य प्रस्तुत किए थे। दिनांक 25 जनवरी, 2019 को उनके द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के पब्लिक फाइनेंस के पाठ्यक्रम के लिए ''इश्यूज इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम'' पर वकतव्य दिया गया था।

डा. जेना को भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएएस) – ''पब्लिक डेब्ट एंड अदर लायबिल्टिज ऑफ द गर्वनमेंट'' गर्वनमेंट एकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड (जीएएसएबी), में भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की सदस्यता प्रदान की गई है। उन्होंने ''कमेटी ऑफ नोलेज सेंटर – गर्वनमेंट एकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड'' भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सदस्य का कार्यभार ग्रहण किया है। उन्हें पीएचडी स्कालरों – डॉली गौड़ : अमिटी कालेज ऑफ कामर्स एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी : अमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पीएचडी विषय : एन एम्पीरिकल एनालिजिज ऑफ नान-पर्फामिंग एस्सैट्स एंड देयर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर डयूरिंग 2008-2018; तथा गोपाल चंद: अमिटी बिजनेस स्कूल, अमिटी यूनिवर्सिटी, पीएचडी विषय : एन इकॉनोमिक एंड फाइनेंशियल एनालिजिज ऑफ मेजर इंडियन एयरपोर्ट्स डयूरिंग 2000-2017 के लिए सह-गाइड भी नियुक्त किया गया है। उन्होंने हर सिमरत कौर की डाक्टरल थिसिस, थिसिस का शीर्ष: प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्कूल एजुकेशन : ए स्टडी ऑफ सैलेक्ट पार्टरनरशिप इन इंडिया, जवाहरला नेहरू यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन भी किया है।

मीता चौधरी

डा. मीता चौधरी को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एनबीएसएनएए) मसूरी द्वारा हावर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ (एचएसपीएच), हावर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित फ्लैगशिप कोर्स आन हैल्थ सिस्टम्स स्ट्रैंनथनिंग एंड सस्टेंनिंग फाइनेंसिंग में ''पब्लिक बजट मैनेजमेंट इन इंडिया : द केस ऑफ हैल्थ'' के विषय पर वकतव्य देने के लिए विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस पाठ्यक्रम का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एनबीएसएनएए) मसूरी द्वारा किया गया था।

सच्चिदानंद मुखर्जी

डा. सच्चिदानंद मुखर्जी ने प्रमुख संस्थानों और फोरा में कराधान से संबंधित विषयों पर कई व्याख्यान दिए। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: डिकेड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफार्म्स इन इंडिया: ए जर्नी टूवार्डस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एमए (अर्थशास्त्र) छात्रों के लिए 29 मार्च 2019 को प्रस्तत किया गया था; टैक्सेशन: इम्पैक्टस, शिफ्टिंग

एंड इनसिडेंस जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाके प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 28 जनवरी 2019 कोएनआईपीएफपीमें उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था।; एनआईपीएफपीमें 25 जनवरी 2019 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में थियोरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन; एनआईपीएफपीमें ही दिनांक 19 दिसम्बर 2018 को दक्षिण एशिया क्षेत्र के विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के लिए पब्लिक इॅकोनोमिक्स के दो सप्ताह के 12वें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स; एनआईपीएफपीमें दिनांक 13 दिसम्बर 2018 को आईसीएएस (भारतीय सिविल लेखा सेवा) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' विषय पर; एनआईपीएफपीमें दिनांक 20 जून 2018 को भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पब्लिक फाइनेंस के कार्यक्रम में डिकेड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफार्म्स इन इंडिया: ए जर्नी टूवार्डस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी); दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को आयोजित आईसीएस परिविक्षाधीन अधिकारियों के ओवरआल इनडायरेक्ट टैक्स रिर्फोम्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' के विषय पर वक्तव्य दिए हैं।

डा. मुखर्जी द्वारा 19 मार्च, 2019 को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईएस), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ''एक्सप्लोरिंग लो-कार्बन एनर्जी सिक्योरिटी पैथ फार इंडिया : रोल ऑफ एशिया-पैसेफिक एनर्जी कोओपरेशन'' का शीर्षक युक्त एक पेपर ''इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी: इंटर-रिजनल कोओपरेशन टू एनर्जी सिक्योर सोसायटी'' के अंतराष्ट्रीय सममेलन में प्रस्तुत किया गया है; मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (एमएसई), चेन्नै में 23 फरवरी, 2019 को ''फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया- कानटैम्पोरेरी पर्ससपेक्ट्सि के संबंध में एमएसई-एर्नस्ट एंड यंग राउंडटेल आयोजन में ''इंटर-गर्वनमेंटनल फिस्कल ट्रांसफर्स इन द प्रेजेन्स ऑफ रेवन्यू अनसर्टिनिअ‍: द केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी); एशियन डेवलमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआई), पटना में 8 दिसम्बर,2018 को पब्लिक फाइनेंस : थियोरी, प्रैक्टिस एंड चैलेंजिस'' के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ''इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी एंड वट माइट हैप्पन?';

उन्हें ग्लोबल सब्सिडिज़ इनिशिएटिव (जीएसआई) ऑफइंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवार्यनमेंट एंड वाटर द्वारा 27 मार्च, 2019 को लै मैरीडियन, नई दिल्ली में आयोजित ''रोल ऑफ गर्वनमेंट सपोर्ट एंड मार्केट बेस्ट फाइनेंसिंग इन इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन'' की कार्यशाला में पैनलबद्ध के रूप में आमंत्रित किया गया था; इसके अलावा दिनांक 27 जुलाई, 2018 को इंडिया हेबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में अर्नस्ट एंड यंग इंडिया एवं शक्ति सस्टेनेबल एनजी फाउंडेशन (शक्ति) के ''कार्बन टैक्स स्ट्रक्चर फार इंडिया: मेरिट्स एंड चैलेंजिज'' की गोलमेज चर्चा के लिए वे आमंत्रित किए गए थे। 12 अक्तूबर, 2018 को सेन्टर फार पालिसी रिसर्च (सीपीआर), नई दिल्ली द्वारा ''वाटर एंड फेडरलिज्म'' के अध्ययन के संबंध में आयोजित आरम्भ कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया था।

डा. मुखर्जी अनेक विख्यात जनरलों में रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं जिनमें प्रमुख हैं – जरनल ऑफ एनवार्यनमेंट इकॉनोमिक्स एंड पालिसी (टेयलर एंड फ्रांसिस ग्रुप), प्राजनन – जरनल ऑफ सोशल मैनेजमेंट साइंसेज (नेशनल स्कूल ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे); दक्षिण एशिया इकॉनोमिक जरनल (सेग इंडिया); सस्टेनेबिल्टी साइंस (स्प्रिंगर); वाटर पालिसी (आईडब्ल्यूए पब्लिशिंग)।

रेणुका साने

डा. रेणुका साने को दिनांक 11 तथा 12 अप्रैल, 2018 को मुम्बई में आयोजित एनुअल पेंशन फंड इनवेस्टमेंट सम्मिट में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। उनके द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को मुम्बई में ''कैच एंड रिलीज : डेटा इन द आईबीसी इकोसिस्टम'' के विषय पर आइ्रबीबीआई-आईजीआईडीआर-एफआईसीसीआई इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी रिफार्मस वर्कशाप में तथा दिनांक 23 एवं 24 मई, 2018 को बंगलौर में ''एमर्जिंग टैक्नोलॉजिस : इश्यूज एंड वे फारवर्ड'' के विषय पर एनआईपीएफपी के सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया गया था।

उन्होंने आईसीएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एनआईपीएफपी में दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को आयोजित एक कार्यक्रम 'क्रेडिट मार्किट' के विषय पर वक्तव्य की प्रस्तुति की थी; एनआईपीएफपी में ही दिनांक 10-21 दिसम्बर, 2018 को उन्होंने आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' के दो सप्ताह के कार्यक्रम में पर्सनल इनसोलवेंसी एंड द क्रेडिट मार्केट के विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किया था।; एनआईपीएफपी में

दिनांक 10-21 दिसम्बर, 2018 को आयोजित ''एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' के दो सप्ताह के कार्यक्रम में आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ''मार्केट फेलियर्स एंड पब्लिक च्वायस'' पर वक्तव्य प्रस्तुत किया; एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में दिनांक 17-28 दिसम्बर, 2018 को आयोजित दक्षिण एशिया रिजन के विश्वविद्यालयों तथा कालेज अध्यापकों के लिए 12वें दो सप्ताह के पब्लिक इकॉनोमिक्स विषय के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में ''मार्केट फेलियर्स'' के विषय पर वकतव्य दिया; एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में 21 जनवरी - 1 फरवरी, 2019 के दौरान भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को उन्होंने ''मार्केट फेलियर्स'' के विषय पर संबोधित किया। मुम्बई में दिनांक 11 तथा 12 अप्रैल, 2018 को आयोजित दूसरे एनुअल पेंशन फंड इनवेस्टमेंट सम्मिट में उन्होंने अतिथि वक्ता के रूप में प्रस्तुति दी थी। मुम्बई में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को आईबीबीआई-आईजीआईडीआर-एफआईसीसीआई इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी रिफार्म्स की कार्य शाला में ''कैच एंड रिलीज : डेटा इन द आईबीसी इकोसिस्टम'' के विषय पर पेपर प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा एनसीएईआरद्वारा नई दिल्ली में आयोजित इंडिया पालिसी फोरम में प्रतिभागिता करके इंपेक्ट ऑफ टैक्स ब्रेक्स आन हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेंविग'' (राधिका पांडे, इला पटनायक एवंरेणुका साने, एनआईपीएफपी के साथ सह-लेखन) पर पेपर की प्रस्तुति की थी; सिडनी, आस्ट्रेलिया में 17-27 जुलाई, 2018 को आयोजित यूएनएसडब्ल्यू सेमिनार में उन्होंने भाग लिया; दिनांक 3-4 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित आईबीबीआई-आईजीआईडीआर इनसोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कांफ्रंस में उन्होंने प्रतिभागिता की; नई दिल्ली में दिनांक 23.8.2019 को मीडियानामा द्वारा आयोजित ''डेटा प्रोटेक्शन अथारिटी एंड कम्पलायंस'' के कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभागिता की; एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में दिनांक 5 सितम्बर, 2018 को कांफ्रेस आन प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन का आयोजन एवं उसमें प्रतिभागिता की। उन्होंने फिक्की, नई दिल्ली में 21 सितम्बर, 2018 को ''इंडिया एंड ईयू – को-क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एलाइनमेंट विद सस्टेनेबल डेवलमेंट गोल्स (एसडीजी) आन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज'' के आयोजन में उपस्थिति दी तथा केसर दास बी एंड एसोसिएट्स द्वारा 12 नवम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित ''राउंड टेबल आन इनसोलवेंसी एकैडमिक्स फोरम'' में उन्होंने भाग लिया।

उनके द्वारा तीसरे लॉ इकॉनोमिक पालिसी कांफ्रेंस आन हैल्थ (विनय, नई दिल्ली तथा इंस्टीट्यूट फार न्यू इकॉनोमिक थिंकिंग, न्यूयार्क द्वारा आयोजित) में 26-28 नवम्बर, 2018 को दिल्ली में प्रतिभागिता की गई। एनआईपीएफपी, नई दिल्ली द्वारा 4 दिसम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित राउंड टेबल: द वे फारवर्ड फार पर्सनल इनसोल्वेंसी इन द सोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के आयोजन की व्यवस्था एवं प्रतिभागिता उनके द्वारा की गई थी। विश्व बैंक द्वारा काठमाण्डु, नेपाल में 22 फरवरी, 2019 को आयोजित नेपाल पेंशन कार्यशाला में उनके द्वारा भाग लिया गया था। नई दिल्ली में 16 मार्च, 2019 को एसआईपीआई एवं द इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया के संयुक्त सम्मेलन में परिचर्चा के लिए उन्होंने प्रतिभागिता की थी। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंसोलवेंसी अकादमिक्स फोरम स्थापित किए जाने की संयुक्त कार्यवाहक समिति में नवम्बर, 2018 में सदस्य रही हैं।

रूद्राणी भट्टाचार्य

सुश्रीभट्टाचार्य ने 6-7 अगस्त, 2018 को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च में आयोजित डीएसजीई कार्यशाला एवं कांफ्रेस में प्रतिभागिता की थी। उन्होंने आर्थिक विभाग, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड में 22 नवम्बर, 2018 को टाइम सीरिज एवं पैनल डेटा माडलिंग पर वक्तव्य प्रस्तुत किए थे और आमंत्रित समीक्षक के रूप में दिसम्बर में आयोजित छठे पैन-आईआईएम कांफ्रेस, आईआईएम, बंगलौर में पेपर की समीक्षा की थी।

उनके द्वारा आरबीआई ओकेजनल पेपर, इकॉनोमि माडलिंग, एमर्जिंग मार्केट फाइनेंस एवं ट्रेड, जरनल ऑफ क्वाटिटेटिव इकॉनोमिक्सकी समीक्षा भी की गई थी।

सुकन्या बोस

डा.सुकन्या बोसद्वारा रिफार्म ऑफ द गर्वनमेंट स्कूल सिस्टम: टूवार्ड ग्रेटर ट्रेटर परियोजना की अध्यक्षता की गई थी। ''आरटीई एंड द रिसोर्स रिक्वार्यमेंट्स : द वे फारवर्ड'' की उनकी अनुसंधान रिपोर्ट की प्रस्तुति अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बंगलौर में की गई थी। वर्ष के दौरान उन्होंनें ''मैक्रो-फिस्कल लिंकेज फार द फिफ्टिन्थ फाइनेंस कमीशन'' शीर्षक युक्त परियोजना की मैक्रोमाडलिंग के कार्य किए गए हैं।

वर्ष के दौरान उन्होंने अनेक अकादमिक कार्यक्रमों में भाग लिया जिनमें से अधिकांश शिक्षा से संबंधित थे। उनमें से कुछ कार्यक्रमों में एनसीईआरटीद्वारा 27 अगस्त को आयोजित टीचिंग एंड लर्निंग एबाउट पावर्टी; अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बंगलौर में 27-28 अक्तूबर को आयोजित वर्कशाप ऑन सीओआरई : द इकॉनमी में ''फिस्कल पालिसी एंड अनएम्पलायमेंट'; हैं। उन्होंने निम्नलिखित परिचर्चाओं में पैनलिस्ट के रूप में प्रतिभागिता की थी – सेव द चिल्ड्रन - एनआईपीएफपी एवं नेशनल कोयलिशन फार एजुकेशन द्वारा 20 दिसम्बर, 2018 को आयोजित नेशनल कंसलटेशन आन चाइल्ड बजटिंग इन इंडिया के कार्यक्रम में ''टूवार्ड बैटर इनवेस्टमेंट एंड स्पैंडिंग प्रायर्टिज फार चिल्ड्रन'', इंटरनेशनल सेंटर गोवा एवं गोवा यूनिवर्सिटी द्वारा 1 फरवरी को आयोजित डिफिकल्ट डिसिजन की पैनल चर्चा में ''फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन : बाइडिंग कांस्ट्रेन्ट?''।

एनआइपीएफपी में 13 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को ''फाइनेंसिंग एलीमेंटरी एजुकेशन'' के विषय पर; 17 दिसम्बर को एनपीएफपी में भारतीय सिविल लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ''एलीमेंट्री एजुकेशन एंड द रिसोर्स क्वशन'' के विषय पर; भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों को एनआईपीएफपी में 26 दिसम्बर को ''आरटीई एंड द एडिक्वेसी क्वशन'' के विषय पर; विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पब्लिक इकानोमिक्स के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में एनआईपीएफपी में 27 दिसम्बर को ''बेसिक एजुकेशन एंड पब्लिक पालिसी'' के विषय पर; एनआईपीएफपी में 29 जनवरी को भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को ''बेसिक एजुकेशन एंड पब्लिक पालिसी'' के विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकॉनोमिक्स में पीएचडी विद्यार्थियों का को-सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था।

भारती भूषण दास

डा.बी.बी.दास द्वारा सेन्टर फार ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (सीटीआरपीएफपी), कोलकातामें जनवरी, 2019 को आयोजित 8वें एनुअल इंटरनेशनल कांफ्रेस आन पब्लिक पोलिसी में 'इकॉनोमिक पर्फामेंट एंड इलैक्ट्रोल वोलेटिलिटी: टेस्टिंग द इकोनोमिक वोटिंग हाइपोथेसिस आन इंडियन स्टेट्स 1957-2013' तथा नई दिल्ली में दिसम्बर, 2018 में इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (आईएसआई) के 14वें एनुअल कांफ्रेंस आन इकॉनोमिक ग्रोथ एंड डेवलमेंट में 'द प्राइवेटनेस ऑफ पब्लिक एक्सपींडचर : ए मॉडल एंड एम्पीरिक्स फार द इंडिया स्टेट्स' पर पेपर की प्रस्तुति की गई थी।

उन्होंने रावेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक में अक्तूबर, 2018 में 'इकॉनोमिक पर्फामेंस एंड इलैक्ट्रोल वोलेटिलिटी : टेस्टिंग द इकॉनोमिक वोटिंग हाइपोथेसिस आन इंडियन स्टेट्स, 1957-2013' पर वक्तव्य की प्रस्तुति की थी।

श्रुति त्रिपाठी

डा.श्रुति त्रिपाठीद्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के सम्मुख ''इवेल्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंसिस फार द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर : 2005-06 टू 2016-17'' की रिपोर्टें तथा वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को ''इवेल्युएशन ऑफ स्टेट फाइनेंसिस फार द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश : 2005-06 टू 2016-17 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने मनी एंड फाइनेंस इ एमर्जिंग मार्केट इकानोमिस एंड एमर्जिंग मार्केट फाइनेंस एंड ट्रेड के पेपरों की समीक्षा की है।

शताद्रू सिकदर

डा.शताद्रू सिकदरद्वारा 21-25 जनवरी, 2019 को हरारे, जिम्बावे में आयोजित 11वें एनुअल अग्रेरियन समर स्कूल, सोशल पालिसी इन द ग्लोबल साउथ : द चैलेंज ऑफ सोशियो-इकॉनोमिक जस्टिस एंड एग्रो-इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में ''कंडीशनल इंकम ट्रांसफर्स एंड वैल-बिइंग : सम पालिसी लैस्सन्स फ्राम इंडियन एक्सपीरियेंस'' शीष्रक के एक पेपर की प्रस्तुति की गई है। उन्होंने 14 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में काउंसिल फार सोशल डेवलपमेंट, दिल्ली द्वारा आयोजित यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सैकेंडरी एडुकेशन के सेमिनार में ''पब्लिक प्रोविजनिंग फार सैकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया : ए सिचुएशन एस्सेसमेंट'' शीर्षक के एक पेपर की प्रस्तुति की थी। इंडियन सिविल लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 10-21 दिसम्बर, 2018 को आयोजित ''एमर्जिंग इश्युज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी के'' के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने 'एडुकेशन, एम्पलायमेंट ओपोरच्युनिटीज एंड स्किल लेवेल्स इन इंडिया : स्टडी बेस्ड आन एनएसएसओ 68 राउंड'' शीर्षक के एक सत्र की उन्होंने प्रस्तुति की थी। उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फार डेवलपमेंट एंड डिसेंट वर्क (आईसीडीडी), यूनिवर्सिटी ऑफ कास्सेल, जर्मनी में 29 नवम्बर, 2018 को 'यूनिवर्सल बेसिक इंकम : हाउ टू फाइनेंस इट' पर एक पेपर की प्रस्तुति की थी। दिनांक 20 अप्रेल, 2018 को विनय, नई दिल्ली में उन्होंने एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय सिविल सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 'स्कूल एडुकेशन क्वालिटी' का सत्र लिया था। उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फार डेवलपमेंट एंड डिसेंट वर्क (आईसीडीडी), यूनिवर्सिटी ऑफ कस्सेल, कस्सेल, जर्मनी में नवम्बर 15 से दिसम्बर, 15ए 2018 के दौरान आयोजित जर्मन अकादमिक एक्सचेंज प्रोग्राम (डीएएडी) फ़ैलो शिप प्रदान की गई थी तथा उन्होंने विजिटंग साइंटिस्ट की सेवाएं प्रदान की थी।

राधिका पांडे

डा.राधिका पांडेद्वारा 20 सितम्ब्र, 2018 को पीआरएस लेगिस्लेटिव रिसर्च द्वारा एलएएमपी फ़ैलो स के लिए आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी एंड क्रिप्टोकरंसी के विषय पर तथा एनआईपीएफपी द्वारा 22 सितम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए आयोजित पब्लिक इकॉनोमिक्स के 12वें एनआईपीएफपी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में ''नीड फार एन इंडीपेंडेंट पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी'' के विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किया था। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 23 जनवरी, 2019 को ''इश्यूज इन पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट इन इंडिया'' के विषय पर तथा 31 जनवरी, 2019 को ''कैप्टिल कंट्रोल'' के विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए थे।

सम्मेलनों के दौरान पेपर प्रस्तुति : उन्होंने 22 फरवरी, 2019 को आयोजित 5वें इंटरनेशनल कांफ्रेस आन साउथ एशियन इकॉनोमिक डेवलमेंट के आयोजन अवसर पर फिस्कल पालिसी साइक्लिटी इन साउथ एशियन इकॉनोमिज (इला पटनायक के साथ सह-लेखन) पर एक पेपर की प्रस्तुति की थी।

दिनेश कुमार नायक

डा. डी.के. नायक द्वारा 11 -13 जनवरी, 2019 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज (आरडी एंड पीआर), हैदराबाद द्वारा ''डेवलपमेंट एंड चेंज'' की थीम पर आयोजित 19वें एनुअल कांफ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूट (आईएएसएसआई) में *''सीजनल माइग्रेशन एंड स्पैटिकल डावर्सिफिकेशन इन रूरल लेबर मार्किट''* शीर्षक युक्त एक पेपर की प्रस्तुति की गई थी। विनय, नई दिल्ली में दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 को भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने *''फिस्कल चैलेंजिज इन डिसाइडिंग एग्रीक्चरल कास्ट्स एंड सपोर्ट''* के विषय पर तथा 27 अगस्त, 2018 को पी.जी. डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनोमिक्स, सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, उड़ीसा में *''फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन एंड इकॉनोमिक ग्रोथ''* के विषय पर, विनय, नई दिल्ली में 20 अप्रैल, 2018 को आईसीएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में *''फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन एंड इकॉनोमिक ग्रोथ''* पर वक्तव्य प्रस्तुत किए थे।

भाबेश हजारिका

डा.बी. हजारिका द्वारा विनय, नई दिल्ली में 28 दिसम्बर, 2018 को भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नत फीडर पोस्ट धारकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''पब्लिक रिव्यु पार्टनरशिप : रिस्क्स इन रिस्क एलोकेशन'' के विषय पर वक्तव्य दिया गया तथा विनय, नई दिल्ली में 14 दिसम्बर, 2018 को आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ''एमर्जिंग इश्युज एंड चैलेंजिस इन पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी'' पर आयोजित दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''पीपीपी – आपुच्युर्निटिज एंड चैलेंजिस'' के सत्र में वक्तव्य दिए गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार, जिन्दल स्कूल ऑफ गर्वनमेंट एंड पब्लिक पालिसी के फाइनेंस मैनेजमेंट के अधिकारियों के लिए 12 सितम्बर, 2018 को सर्टिफिकेट प्रोग्राम का एक सेशन संबोधित किया तथा एसआईएनडीए, श्री लंका, आईएनजीएएफ के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में 12 सितम्बर, 2018 को आयोजित एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागिता की।

''टैक्नीक्स इन प्रोग्राम इवेल्यूएशन : एन ओवरव्यू'' के विषय पर उन्होनें 9 अगस्त, 2018 को आईनजीएफ, नई दिल्ली में आईसीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संबोधन प्रस्तुत किया था। जेएनयू में 9-12 अप्रैल, 2019 को जियोस्पैटियल डेटा एंड रिसर्च : द दिल्ली आर स्कूल, सेन्टर फार स्टडी ऑफ रिजनल डेवलपमेंट के सिम्पोजियम में प्रतिभागिता की थी तथा आईएलआर स्कूल ऑफ कोरनैल यूनिवर्सिटी, यूएसए एंड ग्रास्सरूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट (जीआरएएएम) द्वारा 3-18 जुलाई, 2018 को आईएसईसी बंगलौर में पालिसी एनालिजिज एंड प्रोग्राम इवेल्युएशन वर्कशाल (पीए एंड पीई) में प्रतिभागिता की थी।
उन्होंने निम्नलिखित फाइनेंशियन नवोपायों के लिए रेफरी की सेवाएं प्रदान की थी : जरनल ऑफ स्माल बिजनेस मैनेजमेंट (विल्ली); जरनल ऑफ स्माल बिजनेस एंड एन्टरपरेनरशिप (टेयलर एंड फ्रांसिस); इंटरनेशनल जरनल ऑफ डेवलपमेंट इश्यूज (एमराल्ड); इकॉनोमिक रिव्यु।

रंजन कुमार मोहंती

डा.रंजन मोहंती द्वारा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड़गांव में आईटीएस अधिकारियों के फाउंडेशन पाठयक्रम में ''थियोरी ऑफ ग्रोथ'' के विषय पर वक्तव्य की प्रस्तुति की गई। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीद्वारा 10-21 दिसम्बर, 2018 को भारतीय सिविल लेखा सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में''इमैक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट – ए मैक्रो फिस्कल आउटलुक'' तथा 9-20 अप्रैल, 2018 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीमें भारतीय सिविल लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''पब्लिक एक्सपींडिचर एफिशेंसी'' के विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए गए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में 5-10 नवम्बर, 2018 के दौरान रिसर्च मैथेडोलॉजी इन इकॉनोम्किस के एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने टाइम सीरिज इकोनोमैट्रिक्स के सात वक्तव्यों की सीरिज की प्रस्तुति की थी।

उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटज मार्केट (एनआईएसएम) पातालगंगा कैम्पस, महाराष्ट्र में 8 से 10 जनवरी, 2019 के दौरान आयोजित 55वें एनुअल कांफ्रेस ऑफ द इंडिया इकोनोमैट्रिक सोसायटी (टाइईस) में ''हाउ डज पब्लिक डेब्ट द इंडिया मैक्रो इकोनॉमी? ए स्ट्रक्चरल वीएआर एप्रोच'' तथा नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, ताइपेह, ताइवान में में 27-28 अक्तूबर, 2018 को 16वें ईस्ट एशियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (ईएईए) में ''एनालाइजिंग द डायानामिक रिलेशंसशिप बिटविन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियन डेवलपमेंट एंड इकॉनोमिक ग्रोथ इन इंडिया'' के विषयों पर पेपर की प्रस्तुति की थी।

विश्व बैंक ग्रुप एवं विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के चीफ इकॉनोमिस्ट द्वारा 18 सितम्बर, 2018 को काठमाण्डु, नेपाल में आयोजित साउथ एशिया वर्कशाप आन फिस्कल पालिसी में उन्होंने ''हाउ डज पब्लिक डेब्ट द इंडिया मैक्रो इकोनॉमी? ए स्ट्रक्चरल वीएआर एप्रोच''पर पेपर की की प्रस्तुति की थी।नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटज मार्केट (एनआईएसएम) पातालगंगा कैम्पस, महाराष्ट्र में 7 जनवरी, 2019 को इंडिया इकोनोमैट्रिक सोसायटी (टाइईस) के 55वें वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने डेटा एनालिटिक्स की सम्मेलन पूर्व कार्यशला में उन्होंने भाग लिया तथा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा 24-28 सितम्बर, 2018 को आयोजित ''फाइनेंशियल टाइम सीरिज मॉडेलिंग इन आर: एफआईएनएचडीई-2018'' की एक सप्ताह की कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया था।

''एफिशियेंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिपोजिट-टेकिंग एंड नॉन-डिपोजिट-टेकिंग माइक्रोफाइनेंस इन कम्बोडिया'' के पेपर पर आयोजित चर्चा में उन्होंने भाग लिया था जिसकी प्रस्तुति 27-28 अक्तूबर को नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, ताइपेह, ताइवान में 16वें ईस्ट एशियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (ईएईए) के अवसर पर की गई थी तथा ''इफैक्टिवनैस ऑफ फिस्कल पालिसी इन स्टीमुलेटिंग इकॉनोमि ग्रोथ : एन एम्पीरिकल स्टडी आन बांग्लादेश'' शीर्षक युक्त पेपर की प्रस्तुति विश्व बैंक ग्रुप एवं विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के चीफ इकानोमिस्ट द्वारा 17 एवं 18 सितम्बर, 2018 को काठमाण्डु, नेपाल में आयोजित साउथ एशिया वर्कशाप आन फिस्कल पालिसी के आयोजन अवसर पर की गई थी। इसके अलावा उन्होंने ''वट आर द फिस्कल इम्पलीकेशंस ऑफ पैरास्टाटल्स एंड रेगुशन? के एक सत्र की अध्यक्षता भी की थी।

अमेय सप्रे

डा. अमेय सप्रे प्रधान मंत्री की आर्थिक परामर्श परिषद द्वारा संचालित (अक्तूबर, 2018 – फरवरी, 2019) वर्किंग ग्रुप आन नेशनल एकाउंट्स (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के समन्वय से), नेशनल एकाउंटिंग फ्रेमवर्क फार ब्लयू इकॉनोमी तथा ओसियन गर्वनेंस के सदस्य रहे हैं।

सुरांजली टंडन

डा.सुरांजली टंडनद्वारा जनवरी, 2019 में अनुसंधान यूनिट, वित्त मंत्रालय के सम्मुख ''टैक्स कम्प्लायंस इन इंडिया : एन एक्सपेरिमेंटल एप्रोच'' का संशोधित मसौदा प्रस्तुत किया गया है। उन्हें अक्तूबर, 2018 में ''टूवार्डस एन एशियन नैरेटिव आन टैक्स जस्टिस एंड फाइनेंशियन ट्रांसप्रेंसी'' पर आयोजित गोलमेज चर्चा में पैनेलिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। टीटीपीआई, क्राफर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पालिसी, एएनयू के सम्मुख उन्होंने अगस्त, 2018 में ''टैक्स कम्पलायंस इन इंडिया : एन एक्पैरीमेंट एप्रोच'' शीर्षक युक्त एक पेपर की प्रस्तुति की है।

हरी नायुडु

आपने विनय, नई दिल्ली में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ''सोवेरिजन डेब्ट क्राइसिस'' के विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली में आपने 11 सितम्बर, 2019 को स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पालिसी एंड सोशल एन्टरप्रेनरशिप (एसबीपीपीएसई) में ''डिमोनेटाइजेशन'' के विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किया था।

अनुलग्नक

अनुलग्नक – I
अध्ययनों की सूची 2017-18

निष्पादित अध्ययन

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक / अनुसंधन दल
1.	भारतीय कारपोरेट सेक्टर पर क्रेडिट दबाव का अध्ययन (जुलाई 2017 – जून 2018)	कारपोरेट कार्य मंत्रालय(एमसीए)	अजय शाह राधिका पांडे एवं प्रमोद सिन्हा अमेय सप्रे
2.	डिजिटल आब्जेक्ट आर्किटैकचर के संबंध में नीतिगत इनपुट (डीओए) (अगस्त 2017 – जनवरी 2018)	दूरसंचार विभाग	अजय शाह स्मृति परिशरा विशाल त्रेहान सुदिप्तो बैनर्जी
3.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की आडिटर्स विशेषज्ञ समिति - कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं एनआईपीएफपी के मध्य समझौता ज्ञापन (मई 2018 – अगस्त 2018)	कारपोरेट कार्य मंत्रालय(एमसीए)	अजय शाह शुभो राय आशिष अग्रवाल शैफाली मलहौत्रा सुदिप्तो बैनर्जी
4.	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद (एनसीवीटी) की पुन: संरचना तथा सुदृढ़ीकरण के लिए अनुसंधान एवं परामर्शी सेवाएं (मई 2017 – मार्च 2019)	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	अजय शाह अनिरूद्ध बर्मन सुयश राय आदित्य सिंह राजपूत
5.	क्या मौद्रिक नीति से भारत में वित्तीय स्थिरता उत्पन्न हो सकती है(मई 2017 – दिसम्बर 2018)	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)	इला पटनायक राधिका पांडे शालिनी मित्तल
6.	जनजातिय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई), भोपाल का संस्थानिक मूल्यांकन एवं अंतर विश्लेषण	जनजातिय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई), भोपाल , मध्य प्रदेश सरकार के अध्याधीन	पिनाकी चक्रबर्ती श्रुति त्रिपाठी
7.	समावेशित विकास के लिए अवसंरचना निर्माण	एशियन डेवलपमेंट बैंक	अभिजित सेन गुप्ता (एडीबी) शताद्रू सिकदर ऋचा जैन
8.	भारत में आर्थिक विकास के पूर्वानुमान : समय परिवर्तित मापदंडों पर रिग्रेशन एप्रोच	एनआईपीएफपी	सुदिप्तो मंडल परम चक्रबर्ती (अम्बेडकर विश्वविद्यालय) ऋचा जैन

9.	दक्षिण एशिया में वित्तीय वैश्वीकरण एवं आर्थिक विकास: एक प्रयोगसिद्ध अध्ययन	आईसीएसएसआर	एन.आर.भानुमूर्ति लोकेन्द्र कुमार (रामजस कालेज) दिनेश कुमार नायक
10.	प्रधान मंत्री आवास योजना के संचलन मापदंडों का मूल्यांकन - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	एन.आर.भानुमूर्ति एच.के.अमरनाथ भाबेश हजारिका कृष्णा शर्मा कणिका गुप्ता तानवी ब्राह्मे
11.	सरकारी स्कूल व्यवस्था में सुधार: नव विश्वास का आधार	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अनुदान, 2016.	सुकन्या बोस प्रियंता घोष अरिवंद सरदाना (एकलव्य, मध्य प्रदेश)
12.	भारत में सरकारों के मध्य आर्थिक अंतरणों का अध्ययन	आईडीआरसी	पिनाकी चक्रबर्ती लेखा चक्रबर्ती मनीष गुप्ता अमनदीप कौर शताक्षी गर्ग मौहम्मद अजरूद्दीन रजेल श्रेष्ठा
13.	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों की समीक्षा (बीएमजीएफ परियोजना के अंतर्गत पंद्रहवा वित्त आयोग -लोक वित्त में नवोपाय)	बीएमजीएफ	पिनाकी चक्रबर्ती मनीष गुप्ता
14.	केन्द्र एवं राज्यों के मध्य संसाधन सहभाजन : सिद्धांत तथा रूझान	पंद्रहवां वित्त आयोग	पिनाकी चक्रबर्ती
15.	वर्ष 2022 तक के लिए राज्य राजस्व पूर्वानुमान	बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)	आर.कविता राव सच्चिदानंद मुखर्जीसुरांजली टंडन हरी नायुडु
16.	भारत के स्वास्थ्य बीमा नेटवर्क में निजी अस्पताल: आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन पर विचार	बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)	मीता चौधरी प्रीतम दत्ता
17.	बीआईओएफआईएन: जैवविविधता के संरक्षण के लिए संसाधनों का एकत्रण (दिसम्बर 2017 - सितम्बर 2018)	यूएनडीपी	रीता पांडे रेणुका साने प्रिया यादव सुमित अग्रवाल

चल रही परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्ष	प्रायोजक	लेखक / अनुसंधान दल
1.	ट्राई-एनआईपीएफपी अनुसंधान का कार्यान्वयन **(**जून **2016 –** मई **2019)**	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण **(**ट्राई**)**	अजय शाह इला पटनायक स्मृति परिशरा मयंक मिश्रा फैजा रहमान सुदिप्तो बैनर्जी देवेन्द्र डामले ऋषभ बेली सारंग मोहारिर अशिम कपूर रचना शर्मा सुदिप्तो बैनर्जी विशाल त्रेहान श्रृष्टि शर्मा
2.	उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था के निष्पादन ऑडिट में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए करार	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक **(**सीएजी**)**	अजय शाह इला पटनायक शुभो राय अमेय सप्रे हरलीन कौर महिमा गुप्ता प्रमोद सिन्हा रचना शर्मा समीर पेठे शैफाली मलहौत्रा सुप्रिया कृष्णन
3.	स्वास्थ्य एवं इसके वित्तीयन के अनुसंधान एवं नीतियों में सुधार**(**दिसम्बर **2015-**दिसम्बर **2019)**	बिल एवं मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन	अजय शाह इला पटनायक शुभो राय शैफाली मलहौत्रा हरलीन कौर रचना शर्मा संहिता सपतनेकर महिमा गुप्ता मनप्रीत सिंह समीर पेठे सुप्रिया कृष्णन मधुर मेहता सिद्धार्थ श्रीवास्तव मोमिता दास
4.	भारत में विशेष क्षेत्रों के जटिल मामलेका अध्ययन **(**अप्रैल **2018 –** दिसम्बर **2019)**	आईसीएसएसआर	इला पटनायक**,** अशिम कपूर रचना शर्मा समीर पेठे

			शैफाली मलहौत्रा चिराग आनन्द
5.	एमसीए अनुसंधान कार्यक्रम **(**फरवरी **2019 –** जनवरी **2021)**	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	इला पटनायक प्रतीक दत्ता सुदिप्तो बैनर्जी कार्तिक सुरेश मेधा राजू शुभो राय
6.	भूमि बाज़ार को बेहतर बनाना **(**अप्रैल **2019 –** मार्च **2021)**	ओमिदयार नेटवर्क	इला पटनायक देवेन्द्र डामले
7.	प्रभावशाली राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना के लिए संगठनात्मकडिजायन एवं आंतरिक प्रक्रियाएं (एनसीवीईटी) **(**फरवरी **–** अगस्त **2019)**	ओमिदयार नेटवर्क	इला पटनायक प्रतीक दत्ता सारंग मोहारिर
8.	भारत में सकल घरेलू उत्पाद विकास के त्रैमासिक पूर्वानुमान (एनसीएईआर के सहयोग से)	आईपीएफपी एवं एनसीएईआर	रूद्राणी भट्टाचार्य **(**एनआईपीएफपी**)** सुदिप्तो मंडल **(**एनसीएईआर**)** बोरनली भंडारी **(**एनसीएईआर**)** संध्या गर्ग **(**एनसीएईआर**)**
9.	वित्तीय संरचना**,** संस्थानिक गुणवत्ता एवं मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन : मेटा विश्लेषण भारत में निजी कारपोरेट निवेश का निर्धारण: मौद्रिक एवं आर्थिक नीति की अवस्थिति का निर्धारण **(**नवम्बर **2017-2018)**	एनआईपीएफपी	श्रुति त्रिपाठी **(**एनआईपीएफपी**)** सहाना राय चौधरी **(**आईएमआई**,** कोलकाता**)**
10.	भारत में निजी कारपोरेट निवेश का निर्धारण: मौद्रिक एवं आर्थिक नीति की अवस्थिति का निर्धारण **(**नवम्बर **2017-2018)**	फोरधम यूनिवर्सिटी**,** न्यूयार्क	लेखा चक्रबर्ती ऋषिकेश विनोद **(**फोरधम यूनिवर्सिटी**)** हनी करूण (आईएमएफ)
11.	उप राष्ट्रीय सरकारों की बजट विश्वसनीयता: भारत के 28 राज्यों की आर्थिक पूर्वानुमान चूकों का विश्लेषण	गेट्स कम्पोनेंट	पिनाकी चक्रबर्ती लेखा चक्रबर्ती रूजेल श्रेष्ठ
12.	आर्थिक नीति**,** सरकारों के मध्य अंतरण एवं लिंग समानता : भारतीय राज्यों का अध्ययन **(**दिसम्बर **2017-**दिसम्बर **2019)**	जेनेट स्टोटस्की**,** आईएमएफ**,** वाशिंगटन डीसीएवंवाशिंगटन विश्वविद्यालय	लेखा चक्रबर्ती जेनेट स्टोटस्की पियुष गांधी (आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय)
13.	लिंग समानता एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य में आर्थिक विस्तार पर सेक्टर व्ययों की प्रभाव्यता: एशिया प्रशांत क्षेत्र का अध्ययन **(**सितम्बर **2017 –**अगस्त **2020)**	स्वयं प्रयास	लेखा चक्रबर्ती पियुष गांधी (आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय)

14.	पोषण - लोक व्यय समीक्षा **(**सितम्बर **2018-** सितम्बर **2020)**	गेट्स कम्पोनेंट	लेखा चक्रबर्ती अमनदीप कौर रसेल श्रेष्ठ कोमल जैन
15.	ओईसीडी देशों में पीएफएम के रूप में लिंग बजटिंग: स्वीडन से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्य **(** अगस्त **2018-** अगस्त **2019)**	यूनिवर्सिटी ऑफ उप्पासला एवं स्वीडन सरकार	लेखा चक्रबर्ती
16.	लोक वित्त के प्रभाव के लिए नवोपाय	बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन **(**बीएमजीएफ**),** यूएसए	पिनाकी चक्रबर्ती लेखा चक्रबर्ती मनीष गुप्ता
17.	वस्तु एवं सेवा कर के प्रवर्तन के वित्तीय प्रभाव - पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा कमीशंड	बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन **(**बीएमजीएफ**)**	सच्चिदानंद मुखर्जी आर.कविता राव
18.	करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के अनुपालन किए जाने के प्रभाव का सर्वेक्षण	बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन **(**बीएमजीएफ**)**	आर.कविता राव सुरांजली टंडन
19.	करदाताओं द्वारा कर नीति एवं उसका अनुपालन किए जाने के प्रभाव का सर्वेक्षण		आर.कविता राव
20.	मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा	मध्य प्रदेश सरकार	रथिन राय प्रताप रंजन जेना
21.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय प्रभाव: भविष्य के लिए प्रभाव एवं प्रज्ञता	बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन **(**बीएमजीएफ**)**	मीता चौधरी रंजन कुमार मोहंती राशि मित्तल
22.	भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के **71**वें दौर के अनुसार स्वास्थ्य पर घरेलू व्यय का विश्लेषण	विश्व स्वास्थ्य संगठन	मीता चौधरी जय देव दुबे बिदिशा मंडल
23.	भारत में स्वास्थ्य पर लोक वित्तीयन : आगे की दिशा	बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन	मीता चौधरी रंजन कुमार मोहंती श्रुति त्रिपाठी प्रीतम दत्ता जय देव दुबे बिदिशा मंडल सुनेत्रा घटक राशि मित्तल

अनुलग्नक – II

एनआईपीएफपी कार्य पत्र श्रृंखला

	शीर्षक	लेखक
1.	द इकॉनोमिक्स ऑफ रिलिजिंग द वी-बैंड एंड ई-बैंड इन इंडिया **(**सं. **226,** अप्रैल **2018)**	सुयश राय धीरज मुतरेजा सुदिप्तो बैनर्जी मयंक मिश्रा
2.	यूटिलाइजेशन**,** फंड फ्लो एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर द नेशनल हैल्थ मिशन **(**सं. **227,** मई **2018)**	मीता चौधरी रंजन कुमार मोहंती
3.	फेयर प्ले इन इडियन हैल्थ इश्योरेंस **(**सं. **228,** मई **2018)**	शैफाली मलहौत्रा इला पटनायक शुभो राय अजय शाह
4.	रेगुलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया **(**सं. **230,** मई **2018)**	संहिता सपतनेकर इला पटनायक कमल किशोर
5.	द राइज ऑफ गर्वनमेंट फंडिड हैल्थ इश्योरेंस इन हंडिया **(**सं. **231,** मई **2018)**	इला पटनायक शुभो राय अजय शाह
6.	फैडरलिज्म**,** फिस्कल एसीम्मेट्रिस एंड इकॉनोमिक कंवर्जेंस फ्राम इंडियन स्टेट्स **(**सं. **232,** मई **2018)**	लेखा चक्रबर्ती पिनाकी चक्रबर्ती
7.	फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन एंड इकॉनोमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया **(**सं. **233,** जून **2018)**	एन.आर. भानुमूर्ति लोकेन्द्र कुमावत
8.	हैज फिस्कल रूल चेंजड द फिस्कल मार्कसमैनशिप ऑफ यूनियन गर्वनमेंट**?** एनाटोमी ऑफ बजटरी फोरकास्ट एरर्स इन इंडिया **(**सं. **234,** जून **2018)**	लेखा चक्रबर्ती दृश्य सिन्हा
9.	टैक्स चैलेंजिस एराइजिंग फ्राम डिजिटलाइजेशन **(**सं. **235,** जुलाई **2018)**	सुरांजली टंडन
10.	डॉयग्लोजिंग एंड ओवरकमिंग सस्टेंड फूड प्राइस वोटेलिटी : इनेबलिंग नेशनल मार्केट फार फूड **(**सं. **236,** जुलाई **2018)**	अनिरूद्ध बर्मन इला पटनायक शुभो राय अजय शाह
11.	बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी फार रेगुलेशन इन इंडिया **(**सं. **237,** अगस्त**, 2018)**	शुभो राय अजय शाह बी.एन. श्रीकृष्णा सोमाशेखर सुन्दरसेन
12.	भारत में आर्थिक विकास के पूर्वानुमान : समय परिवर्तित मापदंडों पर रिग्रेशन एप्रोच **(**सं. **238,** सितम्बर **2018)**	रूद्राणी भट्टाचार्य परम चक्रवर्ती सुदिप्तो मंडल

13.	द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हैल्थ सर्विसेज इन एशिया एंड द रोल ऑफ द स्टेट **(**सं. **239,** अक्तूबर **2018)**	सुदिप्तो मंडल
14.	**(**संशोधित **)**इम्पैक्ट आफ इंटरगर्वनमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स ऑन जेन्डर इक्वेलिटी इन इंडिया : एन एम्पीरिकल एनालिजिज **(**सं. **240,** अक्तूबर **2018)**	जेनेट जी. स्टोटस्की लेखा चक्रबर्ती पियूष गांधी
15.	हैल्थ एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया **(**सं. **241,** अक्तूबर **2018)**	सुप्रिया कृष्णन इला पटनायक
16.	डेटा लोकलाइजेशन इन इंडिया क्वशनिंग द मीन्स एंड एंडस :**(**सं. **242,** अक्तूबर **2018)**	ऋषभ बेली स्मृति परिशरा
17.	एक्सपोर्टिंग एंड फर्म पर्फामेंस एविडेंस फ्राम इंडिया : **(**सं. **243,** नवम्बर **2018)**	अपूर्वा गुप्ता इला पटनायक अजय शाह
18.	उदय पावर डेब्ट इन रेट्रोस्पैक्ट एंड प्रोसपैक्टस एनालाइजिंग द एफिशेंसी : पैरामीटर्स**(**सं. **244,** नवम्बर **2018)**	अमनदीप कौर लेखा चक्रबर्ती
19.	एनालाइजिंग द डॉयनामिक रिलेशनशिप बिटविन फिजिकल इंफ्रास्ट्रचर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इकॉनोमि ग्रोथ इन इंडिया **(**सं. **245,** नवम्बर **2018)**	रंजन कुमार मोहंती एन.आर.भानुमूर्ति
20.	डिस्कलोजर्स इन प्राइवेसी पालिसिज डज :''नोटिस एंड कोन्सेंट'' वर्क**?** **(**सं. **246,** दिसम्बर **2018)**	ऋषभ बेली स्मृति परिशरा फैजा रहमान रेणुका साने
21.	वैल्यू डिस्ट्रक्शन एंड वैल्थ ट्रांसफर अंडर द इनसोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड, **2016 (**सं. **247,** दिसम्बर**, 2018)**	प्रतीक दत्ता
22.	एक्जामिनिंग द ट्रेड ऑफ बिटविन प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया- **(**सं. **248,** जनवरी **2019)**	इला पटनायक शालिनी मित्तल राधिका पांडे
23.	वट डू वी नो एबाउट चेंजिंग इकॉनोमिक एक्टिविटी ऑफ फर्म्स**? (**सं. **249,** जनवरी **2019)**	राधिका पांडे अमेय सप्रे प्रमोद सिन्हा
24.	हाउ डज पब्लिक डेब्ट अफैक्ट द इंडियन मैक्रो इकॉनोमी-**?** ए स्ट्रक्चरल वीएआर एप्रोच **(**सं. **250,** जनवरी **2019)**	रंजन कुमार मोहंती सिद्धेश्वर पांडा
25.	द वे फारवर्ड फार पर्सनल इंसोलवेंसी इन द इंडियन इनसोंलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड **(**सं. **251,** जनवरी **2019)**	रेणुका साने
26.	टूवार्ड इंडियाज न्यू फिस्कल फेडरलिज्म **(**सं. **252,** जनवरी **2019)**	विजय केलकर
27.	पब्लिक एक्सपिंडिचर ऑफ ओल्डलार्गेस फार ए फ्यू : एज इंकम स्पोर्ट इन इंडिया-**,** इल्लुजरी फार मोस्ट **(**सं. **253,** फरवरी **2019)**	मुकेश कुमार आनन्द राहुल चक्रबर्ती

28.	प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन हैल्थ इंश्योरेंस नेटवर्क इन इंडिया ए रिफलेक्शन फार : इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत**(**सं. **254,** फरवरी **2019)**	मीता चौधरी प्रीतम दत्ता
29.	इंटरद केस : गर्वनमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेवन्यु अनसर्टिनिटी- इन इंडिया (जीएसटी) एंड सर्विस टैक्स ऑफ गुड्स**(**सं. **255,** फरवरी **2019)**	सच्चिदानंद मुखर्जी
30.	द पॉल्टिकल इकॉनोमी ऑफ जेन्डर बजटिंग एम्पिरिकल एविडेंस फ्राम इंडिया :**(**सं. **256,** मार्च **2019)**	लेखा चक्रबर्ती वीणा नय्यर कोमल जैन
31.	इम्पैक्ट ऑफ चेंजिस इन फिस्कल फेडरेजिज्म एंड फोर्टिन्थ फाइनेंस कमीशन रिकोमैंडेशंस सिनेरियो ऑन स्टेट्स ऑटोनोमी एंड सोशल सेक्टर प्रायरटिज :**(**सं. **257,** मार्च **2019)**	एच.के.अमरनाथ अलका सिंह
32.	हाउ टू मॉडर्नाइज द वर्किंग ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनस इन इंडिया **(**सं. **258,** मार्च **2019)**	प्रतीक दत्ता मेहताब हंस मयंक मिश्रा इला पटनायक प्रशांत रेगी शुभो राय संहिता सपतनेकर अजय शाह अशोक पाल सिंह सोमाशंकर सुन्दरेसन

अनुलग्नक – III
आंतरिक सेमिनार श्रृंखला

दिन, तिथि	विषय
बृहस्पतिवार अप्रैल **05, 2018**	फाइनेंशियल फ्रिक्शंस एंड मौनेट्री ट्रांसमिशन इन इंडिया
बृहस्पतिवार अप्रैल **19, 2018**	द आईएमएफ लेटेस्ट वर्ल्ड इकॉनोमिक एंड फाइनेंशियल आउटलुक
बुधवार अप्रैल **25, 2018**	ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस)
बुधवार मई **23, 2018**	डू फिस्कल रूल्स कॉज फिस्कल डिसिप्लिन ओवर द इलैक्ट्रोल साइकल**?**
शुक्रवार मई **25, 2018**	पोल्टिकल इकॉनोमी आफ मार्केट डेवलपमेंट : वाई इंडियाज इक्विटी मार्केट रिफार्मस हैव सक्सिडिड व्हाइल इट्ज कारपोरेट डेब्ट हेज नाट
बुधवार अगस्त **01, 2018**	वाई डज फिस्कल फेडरलिज्म मैटर्स **?**
शुक्रवार अगस्त **10, 2018**	इश्युज इन स्टेट फाइनेंसिस – एनालिजिज आफ स्टेट बजट्स **2018-19**
बृहस्पतिवार सितम्बर **06, 2018**	क्लोजर्स ऑफ कोल-फायर्ड पावर स्टेशन्स इन आस्ट्रेलिया : लोकल अनएम्लायमेंट इफैक्टस
मंगलवार सितम्बर **18, 2018**	इफैक्टिव एनफोर्समेंट आफ ए डेटा प्रोटेक्शन रिजिम : ए मॉडल फार रिस्क-बेस्ड सुपरवीजन यूजिंग रस्पोंसिव रेगुलेटरी टूल्स
बृहस्पतिवार सितम्बर **27, 2018**	टैक्सिंग द डिजीटल इकॉनोमी : इंटरसेक्शन बिटविन इंटरनेशनल टैक्स**,** मोरेलिटी**,** प्राइवेसी एंड इकॉनोमिक्स
मंगलवार अक्तूबर **30, 2018**	एग्रीक्लचरल यील्ड एंड कम्फलिक्ट
सोमवार नवम्बर **12, 2018**	इंश्योरेंस **:** रिस्क ट्रांसफर सोल्यूशन इन द इनसोलवेंसी स्पेस
बृहस्पतिवार दिसम्बर **20, 2018**	नेशनल कंसलटेशन आन चाइल्ड बजटिंग इन इंडिया : टूवार्ड्स बैटर इनवेस्टमेंट फार द रियलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रनज राइट्ज
बृहस्पतिवार दिसम्बर **20, 2018**	मैनेजिंग वाटर यूटिल्टी इन द यूनाइटिड स्टेट्स : लैसन्स इन आपरेशंस एंड फाइनेंस
मंगलवार जनवरी **15, 2019**	क्रिटिक आफ एंड अल्टरनेटिव्स टू द एक्सट्रेक्टिव इमेजिनेशन आफ एआई
बृहस्पतिवार फरवरी **07, 2019**	मोनेट्री पालिसी इन ए लो-इंटरेस्ट रेट एनवार्यनमेंट
बृहस्पतिवार मार्च **07, 2019**	एक्सपलोरिंग द डोमेंस आफ आइडेंटिटी एंड एमर्जिंग ओपन स्टेंडर्ड फार डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंन्टिटी

अनुलग्नक –IV

शासी निकाय के सदस्यों की सूची

शासी निकाय द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में शासी निकाय का पुनर्गठन आगामी 4 वर्षों अर्थात 5 अप्रैल, 2016 से 4 अप्रैल, 2020 की आगामी अवधि के लिए किया गया था।
(10 अक्तूबर, 2019 को अद्यतन)

1.	डा. विजय केलकर अध्यक्ष, एनआईपीएफपी 134/4-6, अशोक नगर, ऑफ रेंज हिल रोड, भोंसले नगर, शिवाजी नगर, पुणे 411 007	अध्यक्ष
2.	श्री सुमित बोस उपाध्यक्ष एनआईपीएफपी नई दिल्ली-110 067	उपाध्यक्ष

<u>नियम 7(बी)(i) के अंतर्गत</u>
तीन नामांकन वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए हैं

3.	श्री अजय भूषण पांडे राजस्व सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली-110001	सदस्य
4.	श्री अतानु चक्रबर्ती सचिव (आर्थिक कार्य) वित्त मंत्रालय भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली-110001	सदस्य
5.	डा. कृष्णामूर्ति सुब्रमणियम मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार नार्थ ब्लाक	सदस्य

नई दिल्ली-110001

<u>नियम 7(बी)(ii) के अंतर्गत</u>
एक नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

6. डा. राजीव रंजन — सदस्य
परामर्शदाता एवं कार्यालय प्रभारी
आर्थिक विश्लेषण एवं नीति अनुसंधान विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुम्बई-400 001

<u>नियम 7(बी)(iii) के अंतर्गत</u>
एक नामांकन योजना आयोग द्वारा

7. सुश्री अन्ना राय — सदस्य
सलाहकार
नीति आयोग
संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

<u>नियम 7(बी)(iv) के अंतर्गत</u>
तीन नामांकन राजय सरकारें द्वारा

8. श्री मुद्ददा रविचन्द्रा, भा.प्र.से. — सदस्य
प्रधान वित्त सचिव (एफएसी)
वित्त विभाग
आंध्र प्रदेश सरकार
आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलागापुडी
गुन्तुर-522503

9. श्री आई.एस.एन. प्रसाद, भा.प्र.से. — सदस्य
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
कर्नाटक सरकार
कर्नाटक सरकार सचिवालय
विधान सभा
बंगलुरू-560001

10. श्री पी.ए. सिद्दिकी, भा.प्र.से. — सदस्य
सचिव, वित्त विभाग
पश्चिम बंगाल सरकार
कमरा नम्बर 1101

'नाबन्ना' एचआरबीसी भवन
325 शरत चटर्जी रोड
हावड़ा-711102

<u>नियम 7(बी)(vi) के अंतर्गत</u>
एक नामांकन आईसीआईसीआई बैंक से

11. श्री राकेश झा — सदस्य
उप मुख्य वित्त अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक टावर्स
बांद्रा – कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व
मुम्बई-400 051

<u>नियम 7(बी)(vii) के अंतर्गत</u>
दो नामांकन संस्थानों से

12. श्री बालकृष्ण गोयनका — सदस्य
अध्यक्ष
एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
5, सरदार पटेल मार्ग
चाणक्य पुरी
(निकट होटल डिप्लोमेट)
नई दिल्ली-110 021

13 श्री संदीप सोमानी — सदस्य
अध्यक्ष
फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-110 001

<u>नियम 7(बी)(viii) के अंतर्गत</u>
तीन विख्यात अर्थशास्त्री

14. प्रोफेसर शैबल गुप्ता — सदस्य
निदेशक
एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआई)
बीएसआईडीसी कालोनी
ऑफ बोरिंग पाटलीपुत्र रोड
पटना 800 013

15. डा. ईरोल डिसूजा — सदस्य
प्रोफेसर
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
वस्त्रपुर
अहमदाबाद 385 015

16. डा. सुदिप्तो मंडल — सदस्य
सी-380, डिफेंस कालोनी
नई दिल्ली– 110 024

<u>नियम 7(बी)(ix) के अंतर्गत</u>
तीन प्रतिनिधि सहयोगी संस्थानों से

17. डा. शेखर शाह — सदस्य
महानिदेशक
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनिमक रिसर्च
11, परिसिला भवन
आई.पी.एस्टेट, रिंग रोड
नई दिल्ली – 110 002

18. श्री एस.के. पट्टनायक**,** सेवानिवृत्त भा.प्र.से. — सदस्य
महानिदेशक
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया
राज भवन रोड, बेला विस्ता
हैदराबाद-500 082

19. सुश्री यामिनी अय्यर — सदस्य
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी
सेन्टर फार पालिसी रिसर्च
धर्म मार्ग, चाणक्य पुरी
नई दिल्ली 110 021

<u>नियम 7(बी)(x) के अंतर्गत</u>
एक सदस्य शासी निकाय से लिया जाना

20 सीए तरूण जे.घिया — सदस्य
आईसीएआई के परिषद सदस्य
द्वारा उप सचिव (परिषद कार्य)
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीएआई भवन
आई.पी.मार्ग
नई दिल्ली-110 002

नियम 7(बी)(xi) के अंतर्गत
संस्थान के निदेशक (पदेन)

21. डा. रथिन राय — सदस्य-सचिव
निदेशक, एनआईपीएफपी,
नई दिल्ली

नियम 7(बी)(xii) के अंतर्गत
रोटेशन में संस्थान से एक फ़ैलो

22. डा. आर. कविता राव — सदस्य
प्रोफेसर**,** एनआईपीएफपी**,**
नई दिल्ली

विशेष आमंत्रित

1. श्री प्रमोद चन्द्र मोदी
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
वित्त मंत्रालय

भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली -110 001

2. श्री प्रणब कुमार दास
अध्यक्ष
केन्द्रीयअप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली -110 001

अनुलग्नक V
मूल्य अंकित प्रकाशनों की सूची

इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया 1973-74 आर.जे. चेल्लिया एंवआर.एन.लाल (1978) भा. रूपए 10/- हिन्दी अंक (1981) भा. रूपए 20/-

ट्रेन्ड्स एंड इश्यूज इन इंडियन फेडरल फाइनेंस आर.जे. चेल्लिया एंवएसोसिएट्स (एलायड पब्लिशर्स) (1981) भा. रूपए 60/-

सेल्ज टैक्स सिस्टम इन बिहार आर.जे. चेल्लिया एंवएम.सी.पुरोहित (सौम्मेया पब्लिकेशंस) (1981) भा. रूपए 80/-

मिजरमेंट ऑफ टैक्स इफेक्ट ऑफ स्टेट गर्वनमेंट्स 1973-76 आर.जे. चेल्लिया एंवएनसिन्हा (सौम्मेया पब्लिकेशंस) (1982) भा. रूपए 60/-

इम्पेक्ट ऑफ पर्सनल इंकम टैक्स अनुपम गुप्ता एवं पवन के अग्रवाल (1982) भा. रूपए 35

रिसोर्स मोबीलाइजेशन इन द प्रावेट कारपोरेट सेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीडीलाल , श्रीनिवस माथुर एवं केके अत्री (1982) भा. रूपए 50/-

फिसकल इंसेटिव्स एंड कारपोरेट टैक्स सेविंग्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीडीलाल (1983) भा. रूपए 40/-

टैक्स ट्रिटमेंट ऑफ प्रावेट ट्रस्ट्स के श्रीविनासन (1983) भा. रूपए 140/-

सेंट्रल गर्वनमेंट एक्सपेंडिचर : ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड इम्पेक्ट(1950-51 to 1978-79) केएनरेड्डी, जेवीएमशर्मा एवंएनसिन्हा (1984) भा. रूपए 80/-

एंट्री टैक्स एस एन अल्टरनेटिव टू ऑक्ट्राय एम.जी राव (1984) भा. रूपए 40/- पेपरबैक, भा. रूपए 80/- हार्डकवर

इंफरमेशन सिस्टम एंड इवेजन ऑफ सेल्स टैक्स इन तमिलनाडु आर.जे. चेल्लिया एंवएम.सी.पुरोहित (1984) भा. रूपए 50/-

इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटिज इन इंडिया, प्लास्टिक एंड कॉटन टैक्सटाइल फैब्रिक्स ए.बागची एट ला (1986) भा. रूपए 180/-

आस्पेक्टस ऑफ ब्लैक इकॉनामी इन इंडिया(''ब्लैक मनी रिपोर्ट' के नाम से भी ज्ञात) शंकर एन आचार्य एंड एसोसिएट्स, आरजे चेल्लिाह के योगदान के साथ (1986) पुन:मुद्रित अंक भा. रूपए 270/-

इंफलेशन एकाउंटिंग एंड कारपोरेट टैक्सेशन तपस कुमार सेन (1987) भा. रूपए 90/-

सेल्स टैक्स सिस्टम इन वैस्ट बंगाल एबागची एवं एसकेदास (1987) भा. रूपए 90/-

रूरल डेवलपमेंट एलाउंस (आयकर अधिनियम, 1961 का खंड 35सीसी): समीक्षा एचकेसोंधी एवं जेवीएम शर्मा (1988) भा. रूपए 40/-

सेल्स टैक्स सिस्टम इन दिल्ली आर.जे. चेल्लिया एंवके.एन.रेड्डी (1988) भा. रूपए 240/-

इनवेस्टमेंट एलाउंस (आयकर अधिनियम, 1961 का खंड 32ए): एक अध्ययन जेवीएमशर्मा एवंएचकेसोंधी (1989) भा. रूपए 75/- पेपर बैकभा. रूपए 100/- हार्डकवर

स्टीमुलेटिव इफेक्ट ऑफ टैक्स इंसेटिव फार चेरिटेबल कंट्रीब्यूशंस: ए स्टडी ऑफ इंडियन कारपोरेट सेक्टर पवन के अग्रवाल (1989) भा. रूपए 100/-

प्राइसिंग फार पोस्टेज सर्विसेज इन इंडिया राघवेन्द्र झा, एम.एन. मूर्ति एवंसत्य पाल (1990) भा. रूपए 100/-

डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया – ट्रेन्ड्स एंड इश्यूज उमा दत्ता राय चौधरीएवंअमरेश बागची (सम्पादित) (1990) भा. रूपए 240/-

सेल्स टैक्सेशन इन मध्य प्रदेश एमगोविन्द राव, के.एन.बालासुब्रामनियन एवं वीबीतुलसीधर(विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) भा. रूपए 125/-

द आपरेशन ऑफ मोडवेट ए.वी.एल.नारायण, अमरेश बागचीतथा आर.सी.गुप्ता, (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) भा. रूपए 250/-

फिस्कल इंसेटिव्स एंड बैलेंस्ड रिजनल डेवलपमेंट: एन इवेन्यूेशन ऑफ सेक्शन 80एचएच पवन के अग्रवालएवंएचकेसोंधी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) भा. रूपए 195

डायरेक्ट टैक्सेज इन सैलेक्टिड कंट्रीज:ए प्रोफाइल (भाग I एवं II) भा. रूपए 100/-

इफेक्टिव इंसेटिव्स फॉर अल्युमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया मोनोग्राफ सिरिज - I बीगोलदार (1991) भा. रूपए 100/-

सर्वे ऑफ रिसर्च ऑन फिस्कल फेडरेलिज्म इन इंडिया मोनोग्राफ सिरिज - II एम.गोविन्द रावएवंआर.जे. चेल्लिया (1991) भा. रूपए 100/-

रेवन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शंस:इवेल्यूएशन एंड मेथेडोलॉजी वी.जी.राव, संशोधन एवं सम्पादन अतुल शर्मा (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1992) भा. रूपए 195/-

सेल्स टैक्स सिस्टम इन इंडिया: ए प्रोफाइल (1991) भा. रूपए 150/-

स्टेट फाइनेंसिस इन इंडिया अमरेश बागची, जेएलबजाज एवं विलियम एबर्ड (सम्पादित) (1992) भा. रूपए 450/-

फिस्कल पॉलिसी फार नेशनल कैपिटल रिजन महेश सी पुरोहित, सी.साई कुमार, गोपीनाथ प्रधान एवं ओपी बोहरा (1992) भा. रूपए 225

इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन इन द मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर मोनोग्राफ सीरिज III, हशीम एन सलीम (1992) भा. रूपए 150/-

सेल्स टैक्स सिस्टम इन इंडिया: ए प्रोफाइल(1993) भा. रूपए 150/-

द नाइन्थ फाइनेंस कमीशन:इश्यूज एंड रिकमंडेशंस (ए सेलेक्शन ऑफ पेपर्स) (1993) भा. रूपए 490/-

डायरेक्ट टैक्सेज इन सैलेक्टिड कंट्रीज: ए प्रोफाइल (भागIII) समेकन कर्ता के कानन एवं ममता शंकर (1993) भा. रूपए 80/-

इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट वेरियेशंस इन इकॉनोमि डेवलमेंट एंड स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग (मोनोग्राफ सीरिज IV) (1993) उमा दत्ता राय चौधरीभा. रूपए 200/-

टैक्स प्लानिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, अमरेश बागची एवं निकोलस स्ट्रन (सम्पादन) (1994) (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) भा. रूपए 435/-

रिफार्मस ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड टैक्सिज इन इंडिया: इश्यूज एंड आप्शन स्टडी टीम (1994) भा. रूपए 250/-

प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर : जनरेशन एंड रिजनरेशन ऑफ वैल्थ्स उमा दत्ता राय चौधरी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1996) भा. रूपए 395/-

कंट्रोलिंग पोल्युशन: इंसेटिव्स एंड रेग्यूलेशंस शेखर मेहता, सुदिप्तो मंडलएवंयू शंकर (सेग पब्लिकेशंस) (1997) भा. रूपए 250/-

इंडिया : टैक्स पालिसी फार द नाइन्थ फाइव ईयर प्लान (1997-98 से 2001-02)# (वित्तीय संसाधनों के संचालन समूह की कर नीति पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट – अध्यक्ष पार्थसारथी शोम) (सेंटेक्स पब्लिकेशंस प्रालि)

(1997) भा. रूपए 350/-

वैल्यु एडिड टैक्स इन इंडिया:ए प्रोग्रेस रिपोर्ट पार्थसारथी शोम (सम्पादित) (सेंटेक्स पब्लिकेशंस प्रालि) (1997) भा. रूपए 250/-

फिस्कल पालिसी पब्लिक पालिसी एंड गर्वनेंस पार्थसारथी शोम (सम्पादित) (सेंटेक्स पब्लिकेशंस प्रालि) (1997) भा. रूपए 400/-

गर्वनमेंट सब्सिडिज इन इंडिया डीकेश्रीवास्तवएवंतपस के सेन (1997) भा. रूपए 285

इकॉनोमी इंस्ट्रूमेंट्स फार एनवार्यनमेंट सस्टेनिबिल्टि यूशंकरएवंओम प्रकाश माथुर (1998) भा. रूपए 150/-

इंडिया: द चैलेंज ऑफ अर्बन गर्वनेंस ** ओम प्रकाश माथुर (सम्पादित) (1999) भा. रूपए 400/-

स्टेट फिस्कल स्टडीज-असम डीकेश्रीवास्तव,सौमन चट्टोपाध्यायएवंटीएसरंगामनार (1999) भा. रूपए 200/-

स्टेट फिस्कल स्टडीज-पंजाब इंदिरा राजारमण,एचमुखोपाध्यायएवंएचकेअमरनाथ (1999) भा. रूपए 200/-

स्टेट फिस्कल स्टडीज-केरलडीकेश्रीवास्तव, सौमन चट्टोपध्यायएवंप्रताप रंजन जेना (1999) भा. रूपए 200/-

दिल्ली फिस्कल स्टडीओम प्रकाश माथुरएवं टीएसरंगामनार (2000) भा. रूपए 250/-

फिस्कल फेडरेलिज्म इन इंडिया कांटैम्परेरी चैलेंजिस बिफोर द इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन डीकेश्रीवास्तव (सम्पादित) (हरआनन्द पब्लिकेशंस प्रालि) (2000) भा. रूपए 695

स्टेट फिस्कल स्टडीज-हरियाणा तपस के सेन, आरकविता राव (2000) भा. रूपए 200/-

कंट्रोल ऑफ पब्लिक मनी : द फिस्कल मशीनरी इन डेवलपिंग कंट्रीज * ए प्रेमचन्द (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) (2000) भा. रूपए 745

प्राइमर आन वैल्यु एडिड टैक्स # आर.जे. चेल्लिया , पवन के अग्रवाल, महेश सी पुरोहितएवंआरकविता राव (हर आनन्द पब्लिकेशंस प्रालि) (2001) भा. रूपए 195/-

सेन्ट्रल बजटरी स्टडीज इन इंडिया डीकेश्रीवास्तवएवंएचके अमर नाथ (2001) भा. रूपए 170/-

एप्रोच टू स्टेट म्यूनिसीपल फिसकल रिलेशंस : आप्शंस ऑन पर्सपेक्टिव्स ओम प्रकाश माथुर (2001) भा. रूपए 200/-

ट्रेड एंड इंडस्ट्री: एस्से बॉई एनआईपीएफपी फोर्ड फाउंडेशन फ़ैलो एके गुहा, केएलकृष्णानंद, अशोक के लाहिरी (सम्पादित) (विकास पब्लिशिंग हाउसप्रालि) (2001) भा. रूपए 450/-

ट्रांसफर प्राइसिंग एंड रेग्यूलेशंस फार इंडिया: एप्रुवल एंड आल्टरनेटिव्स आरकेबजाज के सहयोग से एसपीसिंह एवंअमरेश बागची (यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रालि) (2002) भा. रूपए 395/-

डिस्क्रिमनेट्री टैक्स ट्रिटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायज-ए-वाएज फोरेन प्रोडक्ट्स: एन एस्सेसमेंट पवन के अग्रवालतथावीसेल्वाराजु (2002) भा. रूपए 200/-

द प्रेक्टिस एंड पालिटिक्स चह रेग्युलेशन: रेग्युलेटरी गर्वनेंस इन इंडिया इलैक्ट्रिसिटी – नवरोज के दोबाश एवं डी नरसिम्हा राव भा. रूपए 290/- (भंडार में उपलब्ध: 32)

***टैक्लिंग पावर्टी कंसट्रेंट्स आन ह्यूमन डेवलपमेंट: फाइनेसिंग स्ट्रैटरजिस इन मध्य प्रदेश (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट) मोनोग्राफ सीरिज*)** – तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीतथाअनित मुखर्जी (2007) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 56)

फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन तमिलनाडु:कंसोलिडेंग एंड बिल्डिंग अपोन एचिवमेंट (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)–

तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीतथा अनित मुखर्जी (2008) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध22)

इंटर स्टेट इक्विलाइजेशन ऑफ हैल्थ एक्सपिंडिचर इन इंडिया यूनियन –एम; गोविन्द राव तथा मीता चौधरी (2008)भा. रूपए 75/- (भंडार में उपलब्ध 94)

ट्रैप्पड इन कंफर्ट जोन ऑफ डिनायल 50 ईयर्स ऑफ एक्सपिंडिचर मैनेजमेंट इन इंडिया– ए प्रेमचन्द (2008) भा. रूपए
150/- (भंडार में उपलब्ध 86)

फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन एंड जैंडर बजटिंग – एम गोविन्द राव**,** लेखाचक्रबर्ती, अमरेश बागची (2008) भा. रूपए 250/- (भंडार में उपलब्ध 96)

फिस्कल रिफार्मस, पर्सिस्टेंट पावर्टी एवं ह्यून डेवलपमेंट: द केस ऑफ ओडिश (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीएवंप्रोतिवा कुण्डु (2008) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 98)

डिलिंग विद फिस्कल कंस्ट्रेंस आन पब्लिक फाइनेंसिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन वैस्ट बंगाल (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीएवंप्रोतिवा कुण्डु(2009)भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध148)

प्रोस्पैक्ट्स एंड पालिसिज फार लो कार्बन इकॉनामिक ग्रोथ ऑफ इंडिया – रामप्रसाद सेनगुप्ता (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध: 114)

पालिसी इंस्ट्रूमेंट फार एचिविंग लो कार्बन एंड हाई ग्रोथ इन इंडिया– यूशंकर (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 120)

राजस्थान – फोरकास्टिंग इकॉनोमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कंकरेंटली (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीएवं सुरजीत दास(2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध147)

इंडिया – पब्लिक एक्सपिंडिचर एंड फाइनेंसियल एकाउंटेबिल्टी – पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट पर्फार्मेंस एस्सेसमेंट रिपोर्ट - प्रताप रंजन जेना (2010)भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध: 29)

रिर्सोसेज फार सस्टेनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीएवं सुरजीत दास (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध142)

रेपिड ट्रांसिशन ऑफ ए यंग स्टेट टू मैच्युरिटी: रिर्सोसेज फार ह्यूमन डेवलपमेंट इन (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन,एचकेअमरनाथ,मीता चौधरी एवं सुरजीत दास (2010)भा. रूपए
150/- (भंडार में उपलब्ध 151)

फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन केरल : इश्यूज एंड चैलेंजिस (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज) – पिनाकी चक्रबर्ती, लेखा चक्रबर्ती, एचके अमर नाथ, एवं सोना मित्रा (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 153)

मार्चिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एक्रास महाराष्ट्र विद इट्स इकॉनमिक डेवलपमेंट (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमरनाथ, मीता चौधरीएवं सुरजीत दास (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 157)

अनस्पैंट बैलेंसेज एंड फंड फ्लो मैकेनिज्म अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) – एनआरभानुमूर्ति, एचके अमर नाथ, अखिलेश वर्मा तथा आदर्श गुप्ता (2014)भा. रूपए 200/-
(भंडार में उपलब्ध 98)

मध्य प्रदेश स्टेट एमडीजी रिपोर्ट 2014-15 –
एनआरभानुमूर्ति, एचकेअमरनाथ, सुकन्या बोस, परम चक्रवर्ती, एवं अकराज्योति जेना (2015) (भंडार में उपलब्ध 98)

डायर्वजेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स इन मध्य प्रदेश : द रोल ऑफ फिस्कल पालिसी एंड

गर्वनेंस – एनआरभानुमूर्ति, एचकेअमरनाथ, मनीष प्रसाद, शाइनी चक्रबर्ती, एवंऋचा जैन (2017) (भंडार में उपलब्ध 37)

एमर्जिंग इश्यूज इन स्टेट फाइनेंसेज पोस्ट फोर्टिन्थ फाइनेंस कमीशन: एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स 2016-17 - मनीष गुप्ता, लेखा चक्रबर्तीएवंपिनाकी चक्रबर्ती (2018) (भंडार में उपलब्ध165)

एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स 2017-18: एमर्जिंग इश्यूज (इम्पेक्ट ऑफ पावर सेक्टर डेब्ट-उदय ऑन स्टेट फाइनेंस)पिनाकी चक्रबर्ती, मनीष गुप्ता, लेखा चक्रबर्ती, अमनदीप कौर (2018) भा. रूपए 200/-

---

सह-प्रकाशन / संबंधित प्रकाशक के पास उपलब्ध

सह-प्रकाशन / एनआईपीएफपी के पास उपलब्ध
**केवल फोटोकापी पुस्तक उपलबध
ड्राफ्ट/धनादेश की प्राप्ति पर प्रकाशन प्रेषण डाक शुल्क भा. रूपए 30/- प्रति प्रति

नोट : क्रम संख्या 1 से 38, 40,41,54 तथा 61 पर दर्शाए गए प्रकाशन बिक्री के लिए अब उपलब्ध नहीं हैं।

अनुलग्नक VI

एनआईपीएफपी संकाय की प्रकाशित सामग्री

एच के , अमरनाथ

(सह-लेखन:एनआरभानुमूर्ति), 2018 पीएमएवाई – ग्रामीण: इम्पेक्ट आन एम्पलायमेंट, कुरूक्षेत्र 66(10):30/-34 (अगस्त)

(सह-लेखन:अलका सिंह), 2019 "इम्पेक्ट ऑफ चेंजिज इन फिस्कल फेडरलिज्म एंड फोर्टिन्थ फाइनेंस कमीशन रिकामेंनडेशंस : सिनेरियो आन स्टेट्स आटोनॉमी एंड सोशल सेक्टर प्रायटिज" एनआईपीएफपीडब्ल्यूपी 257

एनआर, भानुमूर्ति

(सह-सम्पादन), 2018 "एडवांसेस इन फाइनेंस एंड एप्लायड इकॉनोमिक्स", स्प्रिंगर

(सह-लेखन:एचकेअमरनाथ, कृष्णा शर्मा ,कणिका गुप्ता, तानवी ब्रम्हे), 2018 "रिफार्मस इन प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण एंड इट्स इम्पैक्ट : ए सैकेंडरी डेटा एनालिसिस "

2019 "एस्सेसिंग एम्प्लायमेंट जनरेशन अंडर प्रधान मंत्री आवास योजना-अर्बन", रिपोर्ट प्रकाशक : आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, फरवरी

(सह-लेखन:बिस्वाजित मोहंती), 2018 "रिजनल ग्रोथ पालिसी एक्सपीरियंस इन इंडिया : द स्पैटियल डायामेंशन", एशिया पैसेफिक जरनल ऑफ रिजनल सांइस में, 2: 479-505, (जून)

(सह-लेखन:मनीष प्रसाद एवंऋचा जैन),2018 "पब्लिक एक्सपिंडिचर, गर्वनेंस एंड ह्यूमन डेवलमेंट : ए केस ऑफ मध्य प्रदेश", इकॉनोमिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली *(*विशेष लेख*),* 53: 14, 36-43, (अप्रैल)

(सह-लेखन:लोकेन्द्र कुमावत), 2018"रिजिम शिफ्टस इन मोनेट्री पालिसी रिएक्शन फंक्शन इन इंडिया", *इंडिया इकॉनोमिक रिव्यु*,53: 1-2; 167-182, (दिसम्बर)

(सह-लेखन:एचके अमरनाथ), 2018 "पीएमएवाई-ग्रामीण: इम्पैक्ट आन एम्पलायमेंट", कुरूक्षेत्र, 66: 10, 30-34, (अगस्त)

(सह-लेखन:सुकन्या बोसएवंपरम चक्रवर्ती), 2018 "टार्गेटिंग डेब्ट एंड डेफिसिट्स इन इंडिया: ए स्ट्रक्चरल मैक्रोइकॉनोमैट्रिक एप्रोच" जरनल ऑफ क्वानटिटिव इकॉनोमिक्स*,* 16: सप्लीमेंट 1, 87-119, (दिसम्बर 2018, स्प्रिंगर)

(सह-लेखन:वसीम अहमदएवंभास्कर पाठक), 2019 "अंडरस्टेंडिंग द सिस्टेमिक सिम्पट्म्स ऑफ एनबीएफसी$_{एस}$", इकॉनोमिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली*, (*मनीएवंफाइनेंस*,* विशेष अंक*),* 54: 13, 59-67, (मार्च)

(सह-लेखन:लोकेन्द्र कुमावत), 2018 "फाइनेंशियरल ग्लोबलाइजेशन एंड इकॉनोमिकग्रोथइन साउथ एशिया", एनआईपीएफपीडब्ल्यूपी 233

(सह-लेखन:रंजन कुमार मोहंती), 2018 "एनालाइजिंगद डायनामिक रिलेशनशिप बिटविन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलमेंट एंड इकॉनोमिकग्रोथइन इंडिया", एनआईपीएफपीडब्ल्यूपी 245

रूद्राणी भट्टाचार्य

भट्टाचार्य, रूद्राणी, ऋचा जैन, तथा अभिषेक सिंह, (2019), " मिजरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्कअप शॉक इन फूड इनफलेशन इन इंडिया", आईआईबी मैनेजमेंट रिव्यू(लिंक: https://doiorg/101016/jiimb201903015)

बैनर्जी, शेषाद्री एवंभट्टाचार्य, रूद्राणी, "माइक्रो लेवल प्राइस सैटिंग बिहेवियर इन इंडिया : इवीडेंस फ्राम ग्रुप एंड सब-ग्रुप लेवल सीपीआईआईडब्ल्यू डेटा", इकॉनोमिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली, (आगामी)

सुकन्या बोस

(सह-लेखन:अरविंद सरदाना, एवंप्रियंता घोष) 2018 "यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एज्युकेशन यूजिंग द पब्लिक स्कूल सिस्टम इस फिजिबल", इकॉनोमिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली, 53(44): नवम्बर 03 https://wwwepwin/node/152993/pdf

(सह-लेखन:प्रियंता घोष, एवंअरविंद सरदाना) "इंकलुजन एंड द क्वशन ऑफ रिर्सोसेज", पाठशाला, 1(2), फरवरी (2019)

(सह-लेखन:प्रियंता घोष, एवंअरविंद सरदाना) 2019 अनुसंधान रिपोर्ट , "रिर्सोसेज रिक्वार्यनमेंट फार आरटीई: द वे फारवर्ड" एनआईपीएफपी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बंगलौर द्वारा प्रस्तुत, मार्च 2019

(सह-लेखन:एनआरभानुमूर्तिएवंपरम चक्रवर्ती), 2018 "टार्गेटिंग डेब्ट एंड डेपिफसिट्स इन इंडिया: ए स्ट्रक्चरल मैक्रोइकॉनोमैट्रिक एप्रोच" जरनल ऑफ क्वानटिटिव इकॉनोमिक्स, 16: सप्लीमेंट 1, 87-119, (दिसम्बर 2018, स्प्रिंगर)

लेखा चक्रबर्ती

(सह-लेखन:मनीष गुप्ता एवं पिनाकी चक्रबर्ती), 2018 एमर्जिंग इश्यूज इन स्टेट फाइनेंस पोस्ट पोस्ट फोर्टनिंथ फाइनेंस कमीशन: एनालिजिज ऑफ स्टेट बजट्स2016-17, एनआईपीएफपीप्रकाशन

(सह-लेखन:ऋषिकेश विनोद एवंहनी करूण), 2018 एनकर्जिंग प्रावेट इनवेस्टमेंट इन इंडिया : इवीडेंस फ्राम मेबूत, (सम्पादित)ऋषिकेश विनोद एवं सी आर राव, हैंडबुक ऑफ इकॉनोमैट्रिक्स: यूसेज ऑफ''आर'' एलजेविर पब्लिकेशंस, यूएसए

(सह-लेखन:पिनाकी चक्रबर्ती, मनीष गुप्ता, एवंअमनदीप कौर), 2018 एनालाइजिंगऑफ स्टेट बजट्स 2017-18: एमर्जिंग इश्यूज, एनआईपीएफपीपब्लिकेशंस

(सह-लेखन:पिनाकी चक्रबर्ती), 2018 "बजट 2018-19: न्यू एफआरबीएम फ्रेमवर्क", इकॉनोमिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली, 53(9):30-34

_____, 2018 "फेडरलिज्म, फिस्कल एस्सिमैट्रिक्स एंड इकॉनोमिककंवर्जेंस : इवीडेंस फ्राम इंडियन स्टेट्स ", एशिया पैसेफिक जरनल ऑफ रिजनल साइंस *(स्प्रिंगर)* के इकॉनोमिकएनालिजिज ऑफ लॉ, पॉलिटिक्स एंड रिजन्स का विशेष अंक "

(सह-लेखन:दृश्य सिन्हा), 2018 "हैज फिस्कल रूल्स चेंज्ड द फिस्कल बिहेवियर ऑफ यूनियन गर्वनमेंट ऑफ इंडिया? एनाटोमी ऑफ बजटरी फोरकास्ट एरर्स इन इंडिया",*इंटरनेशनल जरनल ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च*9(3): 75-85(जून)

(सह-लेखन:कुशाग्र ओम शर्मा), "फिस्कल रिफोर्मस, डेफिसिट एंड इंफलेशन: एम्पीरिकल एविडेंस फ्राम इंडिया", प्रांजण, जरनल ऑफ सोशल एंड मैनेजमेंट साइंस, XLVI (4) में प्रकाशन

चक्रबर्तीलेखा ,"मोनेट्री सिग्नोरेज इन एन एमर्जिंग इकॉनामी: इंटरनेशनल जरनल ऑफइकॉनोमिक्स एंड फाइनेंस , 10(5): 135-144

(सह-लेखन: समीक्षा अग्रवाल), 2018 डिजिटल इनोवेशंस इन पब्लिक फाइनेंस: एन एफिसिएंट यूज ऑफ रिर्सोसेज, योजना, भारत सरकार का जनरल

(सह-लेखन:पिनाकी चक्रबर्तीएवंमनीष गुप्ता), 2018 "वुड उदय ब्रिटन अप राजस्थान फाइनेंसिस"? इकॉनोमिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली, LIII (31):31-35

(सह-लेखन: जे स्टोट्स्की एवं पी गांधी), 2019, "इंटरगर्वनमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स एंड जेन्डर इक्विलिटी : इम्पीरिकल एविडेंस फ्राम इंडिया, वर्किंग नोट आईडीआरसीजीआरओडब्ल्यू सीरिज मैक ग्रिल यूनिवर्सिटी, मॉन्ट्रियाल, कनाडा

चक्रबर्ती, लेखा , 2019 मैक्रोइकॉनोमिकपालिसी इफैक्टिवनेस एंड इनइक्वेलिटी : एफीकेसी ऑफ जेन्डर बजटिंग इन एशिया पैसेफिक (जनवरी 18, 2019) (मारियन इन्ग्राम्स तथा यादवेन्द्र सिंह के साथ) लेवीइकॉनोमिक्स इंस्टीट्यूट, वर्किंग पेपर्स सीरिज 920 (2019)

(सह-लेखन:समीक्षा अग्रवाल), 2018 व्हु बियर्स द कारपोरेट टैक्स इंसीडेंस? एम्पीरिकल इवीडेंस फ्राम इंडिया, टैक्स एंड ट्रांसफर पालिसी इंस्टीट्यूट (क्रावफोर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पालिसी), आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, वर्किंग पेपर 5/2018

_____, 2018 डिजीटल इनोवेशंस इन पब्लिक फाइनेंस: एन एफीसिएंट यूज ऑफ रिसोर्सिज, एमआरआरए पेपर संख्या 85219, म्यूनिच यूनिवर्सिटी

चक्रबर्ती, लेखा , 2018 जेन्डर बेस्ड एनालिजिज (जीबीए) इन कनाडा: वट कैन सेक्टरल मिनिस्ट्रीज डू इन इंडिया ? एमआरआरए पेपर नम्बर 86748, म्यूनिच यूनिवर्सिटी (मई)

(सह-लेखन:मेरियन इंग्राम्स एवं यादवेन्द्र सिंह), मैक्रोइकॉनोमिकपालिसी इफैक्टिवनेस एंड इनइक्विलिटी: एफीकेसी ऑफ जेन्डश्र बजटिंग इन एशिया पैसेफिक, वर्किंग पेपर 62, लेवी इकॉनोमिक इंस्टीट्यूट, न्यूयार्क

चक्रबर्ती, लेखा , जेन्डर बजटिंग एस एकाउंटेबिल्टी इनिशिटेवि, आस्ट्रेलिया टैक्स पालिसी इंस्टीट्यूट, कैनबरा

(सह-लेखन:पिनाकी चक्रबर्ती), 2018 फेडरेशन, फिस्कल एसीमैट्रिस एंड इकॉनोमिककंर्वजेंस: इवीडेंस फ्राम इंडियन स्टेट्स, एनआईपीएफपीडब्ल्यूपी 232

(सह-लेखन:दृश्य सिन्हा), 2018 हैस फिस्कल चेन्जड द फिस्कल मार्कसमैनशिप ऑफ यूनियन गर्वनमेंट : एनाटोमी ऑफ बजटरी फोरकास्ट एरर्स इन इंडिया, एनआईपीएफपीडब्ल्यूपी 234

(सह-लेखन:स्टोस्कन, जेनेट जी, पियुष गांधी), 2018 इम्पैक्ट ऑफ इंटरगर्वनमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स आन जेन्डर इक्विलिटी इन इंडिया : एन एम्पीरिकल एनालिजिज, एनआईपीएफपीडब्ल्यूपी 240

(सह-लेखन:अमनदीप कौर), 2018 उदय पावर डेब्ट इन रेट्रोस्पैक्ट एंड प्रोस्पैक्टस: एनालाइजिंगद एफिशियेंसी पैरामीटर्स, एनआईपीएफपीडब्ल्यूपी 244

(सह-लेखन:वीणा नय्यर एवंकोमल जैन), 2019 द पोल्टिक्ल इकानोमी ऑफ जेन्डर बजटिंग : एम्पीरिकल इवीडेंस फ्राम इंडिया, एनआईपीएफपीडब्ल्यूपी 256

पिनाकी चक्रबर्ती

(सह-लेखन: मनीष गुप्ता, लेखा चक्रबर्ती, अमनदीप कौर), 2018 एनालिजिजऑफ स्टेट बजट्स 2017-18: एमजिर्हंग इश्यूज (इम्पेक्ट ऑफ पावर सेक्टर डेब्ट – उदय आन स्टेट फाइनेंस) दिसम्बर 2018, विनय, नई दिल्ली

चक्रबर्ती पिनाकी, 2018 कैन द ब्रिक्स पार्टनरशिप चेंज सबनेशनल फिस्कल बिहेवियर? एन इंडियन फेडरलिज्म पर्सपेक्टि, इन स्टेटल्र निको (सम्पादित), द ब्रिक्स पार्टनरशिप चैलेंजिस एंड प्रोस्पैक्ट्स फार मल्टीलेवल गर्वनमेंट, जेयूटीए, साउथ अफ्रीका

_____, 2018 टैक्स पालिसी डिजायन एंड डेवलमेंट: द इंडियन स्टोरी, विनोद राय एवं अमितेन्दु पालित (सम्पादित), सैवन डकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पेंगुइन रेंडम हाउस, भारत

(सह-लेखन: शताक्षी गर्ग), 2018 फिस्कल प्रेशर ऑफ माइग्रेशन एंड होरिजोन्टल फिस्कल इनइक्वेलिटी: एविडेंस फ्राम इंडियन एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल माइग्रेशन/ onlinelibrarywileycom/doi/abs/101111/imig12536

(सह-लेखन: लेखा चक्रबर्ती), 2018 "फैडरल फिस्कल एसिमैट्रिक्स एंड इकॉनोमिक कंवर्जेस / इंविडेंस फ्राम इंडियन स्टेट्स'', एशिया पैसेफिक जरनल ऑफ रिजनल साइसेंस, स्प्रिंगर, , 2: 83-113

(सह-लेखन: लेखा चक्रबर्ती), 2018 फेडरलिज्म, फिस्कल एसिमैट्रिक्स एंड इकॉनोमिक कंवर्जेस / इंविडेंस फ्राम इंडियन स्टेट्स'', पिनाकी चक्रबर्ती तथा लेखा चक्रबर्ती), मई 2018 एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 232; तथा ''इकॉनोमिक एनालिजिज ऑफ लॉ, पोलिटिक्स एंड रिजन्स'' का विशेष अंक, एशिया पैसेफिक जरनल ऑफ रिजनल साइसेंस, स्प्रिंगर

मीता चौधरी

(सह-लेखन: जय देव दुबे), 2019 "एस्टीमेटिंग पब्लिक स्पैंडिंग आन हैल्थ :यूजिंग इनफारमेशन आन विड्रावल्स" *इकॉनोमिक एंड पोल्टिकल वीकली,* 54 (5): (फरवरी)

(सह-लेखन: रंजन कुमार मोहंती), 2019 "यूटिलाइजेशन, फंड फ्लो एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर द नेशनल हैल्थ मिशन", *इकॉनोमिक एंड पोल्टिकल वीकली,* 54(8): (फरवरी)

(सह-लेखन: जय देव दुबे एवंबिदिशा मंडल), 2019 "भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के 71वें दौर के अनुसार स्वास्थ्य पर घरेलू व्यय का विश्लेषण", अनुसंधान रिपोर्ट

(सह-लेखन: प्रीतम दत्ता), 2019 "प्राइवेट होस्पिटल्स इन हैल्थ इंश्योरेंस नेटवर्क इन इंडिया : ए रिफलेक्शन फार इम्पलीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत ", एनआईपीएफपी डब्ल्यू पी संख्या 254

भारती भूषण दास

(सह-लेखन: जे स्टिफन फेरिस), "एक्सपींडिचर विजिबिल्टी एंड वोटर मेमोरीए कम्पोज :िशनल एप्रोच टू द पोल्टिकल बजट साइकल इन इंडियन स्टेट्स, 1959–2012", *इकॉनोमिक्स ऑफ गवर्नेंस, आगामी*

(सह-लेखन: जे स्टिफन फेरिस, एवंस्टेनले एल विनर), 2018 "मिजरिंग इलैक्ट्रोल कम्पीटिटिवनेस विद एप्पलीकेशन टू द : इंडियन स्टेट्स", सीई सिफो वर्किंग पेपर सीरिज 7216, 2018 (कार्लटन इकोनोमिक पेपर नं10-18 ., कार्लटन यूनिवर्सिटी, जुलाई (में भी प्रकाशित 2018
(सह-लेखन: जे स्टिफन फेरिस), 2018 "इकॉनोमिक पर्फामेंस एंड इलैक्ट्राल वोलेटिल्टी टैस्टिंग द इॅकोनोमिक वोटिंग : हाइपोथेसिस आन इंडियनस्टेट्स, 1957–2013", कार्लटन इकोनोमिक पेपर नं07-18 ., कार्लटन यूनिवर्सिटी, जून, 2018

मनीष गुप्ता

(सह-लेखन: पिनाकी चक्रबर्ती, लेखा चक्रबर्ती एवंअमनदीप कौर), 2018 मोनोग्राफ: एमर्जिंग इश्युज इन स्टेट फाइनेंसिस: एनालिजिज ऑफ स्टेट बजट्स 2017-18, विनय, नई दिल्ली।

(सह-लेखन: पिनाकी चक्रबर्ती एवंलेखा चक्रबर्ती), 2018 वुड उदय ब्रिट्न अप राजस्थान फाइनेंसिस?, *इकॉनोमिक एंड पोल्टिकल वीकली,* 53(31): 31-35

(सह-लेखन: पिनाकी चक्रबर्ती), 2019 स्टेट फाइनेंस कमीशंस : हाउ सक्सफुल रैव दे बीन इन एम्पावरिंग लोकल गर्वनमेंट्स ? एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 263

भाबेश हजारिका

2019 "जेन्डर इंकम गैप इन रूरल इनफार्मल माइक्रो-एन्टरप्राइजेस : एन अनकंडीशनल क्वांटायल डिकम्पोजिशन एप्रोच इन द हैंडलुम इंडस्ट्री" *यूरेशियन इकॉनोमिक रिव्यु* , 9(4), 386-402

2019 "एन्टरप्रेनुरियल मोटिवेशंस ऑफ सोशल-कल्चरल रैलवेंस: एन एक्प्लोरेटरी एनालिजिज इन द हैंड इंडस्ट्री इन असम" *एशियन जरनल ऑफ वोमैन स्टडीज,* 25(3), 317-351

(सह-लेखन: एनआरभानुमूर्ति), 2019 "चेंजिंग लैंडस्कैप ऑफ रूरल इकॉनोमी" *कुरूक्षेत्र,* 67(10), 23-28 (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

2018 "डेवलपमेंट ऑफ वोमैन माइक्रो-एन्टरप्रेनरशिप इन द हैंडलुम इंडस्ट्री: एन इमपीरिकल एनालिजिज एमंग ट्रायबल कम्युनिटिज इन असम" इंटरनेशनल जरनल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, 14(1), 22-38

2018 वाई वोमैन हैंडलुम माइक्रो एन्टरप्रेनरर्स अर्न लैस दैन देयर मेल काउंटरपार्ट्स? ए ब्लांइडर-ओक्साका डिकम्पोजिशन एप्रोच, इन डे यू, एंड घोष, बी एन(सम्पादित), डेप्रीवेशन, डेवलपमेंट एंड एम्पावरनमेंट ऑफ वोमैन इन इंडिया: नार्थ-ईस्ट पर्सपेक्टिव्य (पीपी 1-38), नई दिल्ली: बुकवेल पब्लिकेशन।

प्रताप रंजन जेना

2018 "एडाप्टिंग एमटीईएफ थ्रु फिस्कल रूलस: एक्सपीरियंस ऑफ मल्टी ईयर बजट प्लानिंग इन इंडिया'' एडोप्टिंग एमटीईएफ थ्रु फिस्कल रूल्स: एक्सपीयेरिंसिस ऑफ मल्टी ईयर बजट प्लानिंग इन इंडिया", *इंटरनेशनल जरनल ऑफ गर्वनमेंट फाइनेंशियल मेनेजमेंट,* 18(2)

विजय केलकर

2019, "टुवार्ड्स इंडियाज न्यू फिस्कल फेडरलिज्म", जरनल ऑफ क्वांटिटेटिव इकॉनोमिक्स, 17(1): 237-248

रंजन कुमार मोहंती

(सह-लेखन: मीता चौधरी), 2019 "यूटिलाइजेशन, फंड फ्लो एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर द नेशनल हैल्थ मिशन," *इकॉनोमिक एंड पोल्टिकल वीकली,* 54(8): 49-57, फरवरी 23

(सह-लेखन: सिद्धेश्वर पांडा), 2019 "हाउ डज पब्लिक डेब्ट इफेक्ट द इंडिया मैक्रो-इकॉनोमी? ए स्ट्रक्चरल वीएआर एप्रोच " एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 250

(सह-लेखन: एनआरभानुमूर्ति), 2018"एनालाइजिंग द डायानामिक रिलेशनशिप बिटविन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियन डेवलमेंट एंड इकॉनोमिक ग्रोथ इन इंडिया", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 245

(सह-लेखन: मीता चौधरी), "यूटिलाइजेशन, फंड फ्लो एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर द नेशनल हैल्थ मिशन", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 227

सच्चिदानंद मुखर्जी

एसमुखर्जी (2019), "वैल्यु एडिड टैक्स एफिशियंसी एक्रास इंडियन स्टेट्स: पैनल स्टोचैस्टिक फ्रंटियर एनालिजिज", *इकॉनोमिक एंड पोल्टिकल वीकली,* 54(22):40-50

एसमुखर्जी (2019), "एक्सपलोरिंग लो-काब्रन एनर्जी सिक्योरिटी पैथ फार इंडिया: रोल ऑफ एशिया-पैसेफिक एनर्जी कोओपरेशन ", कार्यशील पेपर संख्या 259, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली

(सह-लेखन: आरकविता राव), 2019 "इवोल्युशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) इन इंडिया ", कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली
(सह-लेखन: आरकविता राव), 2019 "वैल्यु एडिड टैक्स एंड इनफोर्मिल्टी: :डेटरमिनेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन्टरप्राजेज अंडर स्टेट वीएटी इन इंडिया", *मार्जिन—द जरनल ऑफ एप्लाइड इॅकोनोमिक रिसर्च,* 13(1): 21–48

_____, 2018 "एस्टीमेशन ऑफ अनएकाउंटिड इंकम ऑफ इंडिया: यूजिंग ट्रांसपोर्ट एस ए यूनिवर्सल इनपुट", आररामाकुमार (सम्पादित) *नोट-बंदी: डिमोनेटाइजेशन एंड इंडियाज एल्युसिव चेस फार ब्लैक मनी, अध्याय 6 में:* 167-187, (आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली)

(सह-लेखन: चक्रबर्ती, D), 2018 "एनवार्यनमेंटल चैलेंजिस इन एशिया", सारा हसु (सम्पादित) में, राउटेड्ज हैंडबुक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एशिया, अध्याय: 66-90, (राउटकलेज:यूके एंड यूएसए 4 जून 2018)

एसमुखर्जी 2019 "इंटर-गर्वनमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेवन्यू अनसर्टिनिटी : द केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) इन इंडिया", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 255

दिनेश कुमार नायक

2019 "एस्सेसिंग एम्पलायमेंट जनरेश अंडर प्रधान मंत्री आवास योजना (अर्बन)'' की रिपोर्ट, प्रकाशन : आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

हरी नायुडु

2019 " टैक्स रेवन्यू एफिशियेंसी इन इंडिया स्ट्रेटस: द केस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस'' एनआईपीएफपी, डब्ल्यूपी 278

राधिका पांडे

(सह-लेखन:अमेय सप्रेएवंप्रमोद सिन्हा), 2018 वट डस द न्यू 2011-12 आईआईपी सिरिज टैल एबाउट द इंडियन मेनुफैक्चिरिंग सेक्टर? इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यु 11(2): 90-106

2019 बिजनेस साइकल मिजरमेंट इन इंडिया : राधिका पांडे, इला पटनायकएवंअजय शाहद्वारा स्मिरनोव एस, ओजीयड्रिम ए, पिकहेट्टी पी (सम्पादित) में बिजनेस साइकल इन ब्रिक्स। सोसायटिज एंड पोलिटिक्ल आर्डर्स इन ट्रांजिशन, चैम।

इला पटनायक

(सह-लेखन: राधिका पांडे एवंअजय शाह), 2019 "बिजनेस साइकल मिजरमेंट्स इन इंडिया" स्मिरनोव एस, ओजीयड्रिम ए, पिकहेट्टी पी (सम्पादित) में बिजनेस साइकल इन ब्रिक्स। सोसायटिज एंड पोलिटिक्ल आर्डर्स इन ट्रांजिशन, चैम।

(सह-लेखन: अपूर्वा गुप्ता तथाअजय शाह), 2018 "एक्सपोर्टिंग एंड फर्म पर्फामेंस : एविडेंस फ्राम इंडिया ", *इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यु*

(सह-लेखन: शैफाली मलहौत्रा, शुभो राय एवंअजय शाह), 2018 "फेयर प्ले इन इडियन हैल्थ इश्योरेंस ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 228

(सह-लेखन: संहिता सपतनेकर एवंकमल किशोर), 2018 "रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया'', एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 230

(सह-लेखन: शुभो राय एवंअजय शाह), 2018 "द राइज ऑफ गर्वनमेंट फंडिड हैल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 231

(सह-लेखन: अनिरूद्ध बर्मन, शुभो राय एवंअजय शाह), 2018 "डायग्लोजिंग एंड ओवरकमिंग सस्टेन्ड फुड प्राइज वोलेटिलिटी :इनेबलिंग ए नेशनल मार्केट फार फुड ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 236

(सह-लेखन: सुप्रिया कृष्णन), 2018 "हैल्थ एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 241

(सह-लेखन: अपूर्वा गुप्ता एवं अजय शाह), 2018 "एक्सपोर्टिंग एंड फर्म पर्फामेंस : एविडेंस फ्राम इंडिया ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 243

(सह-लेखन: शालिनी मित्तल एवंराधिका पांडे), 2018 "एक्जामिनिंग द ट्रेड-ऑफ बिटविन प्राइस एंड फाइनेंशियन स्टेबिलिटी इन इंडिया", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 248

(सह-लेखन: प्रतीक दत्ता, मेहताब हंस, मयंक मिश्रा, प्रशांत रेगी, शुभो राय, संहिता सपतनेकर, अजय शाह, अशोक पाल सिंह एवं सोमाशंकर सुन्दरेसन", 2019 "हाउ टू मोर्डनाइज द वर्किंग ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 258

आर, कविता राव

(सह-लेखन: सच्चिदानंद मुखर्जी), 2019 "इवोल्युशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) इन इंडिया ", कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली

_____, 2019 "वैल्यु एडिड टैक्स एंड इनफोर्मिल्टी: :डेटरमिनेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन्टरप्राजेज अंडर स्टेट वीएटी इन इंडिया", *मार्जिन—द जरनल ऑफ एप्लाइड इॅकोनोमिक रिसर्च,* 13(1): पीपी 21–48

_____, 2018 "एस्टीमेशन ऑफ अनएकाउंटिड इंकम ऑफ इंडिया: यूजिंग ट्रासपोर्ट ए यूनिवर्सल इनपुट, आर रामाकुमार (सम्पादित) नोट-बंदी: मिमोनेटाइेशन एंड इंडियाज एलयूजिव चेस फार ब्लैक मनी, अध्याय 6 में: पीपी 167-187, (आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली)

रथिन राय

2019 "चेंजिंग फिस्कल डायानामिक्स", सेमिनार, जनरल, नई दिल्ली में, 30th अप्रैल 2019

अजय शाह

(सह-लेखन: राधिका पांडे एवंइला पटनायक), 2019 स्मिरनोव एव, क्वाजिल्दिरिम ए, पिच्चेट्टी पी (सम्पादित) "बिजनेस साइकल मिजरमेंट्स इन इंडिया" सोसायटिज एंड पोल्टिकल आर्डर्स इन ट्रांजिशन, स्प्रिंगर, चैम में,

(सह-लेखन: अपूर्वा गुप्ता एवं इला पटनायक), 2018 "एक्सपोर्टिंग एंड फर्म पर्फामेंस : एविडेंस फ्राम इंडिया_", *इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यु*

(सह-लेखन: शैफाली मलहौत्रा, इला पटनायक एवंशुभो राय), 2018 "फेयर प्ले इन इडियन हैल्थ इश्योरेंस ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी No 228

(सह-लेखन: इला पटनायक एवंशुभो राय), 2018 "द राइज ऑफ गर्वनमेंट फंडिड हैल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी No 231

(सह-लेखन: अनिरूद्ध बर्मन, इला पटनायक एवंशुभो राय), 2018 "डायग्लोजिंग एंड ओवरकमिंग सस्टेन्ड फुड प्राइज वोलेटिलिटी :इनेबलिंग ए नेशनल मार्केट फार फुड ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी No 236

(सह-लेखन: शुभो राय, बीएन श्रीकृष्णा एवं सोमाशेखर सुन्दरेसन) "बिल्डिंग स्टेट केपेसिओ फार रेगुलेशन इन इंडिया'', एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी No 237

(सह-लेखन: अपूर्वा गुप्ता एवंइला पटनायक), 2018 "एक्सपोर्टिंग एंड फर्म पर्फामेंस : एविडेंस फ्राम इंडिया ", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी No 243

(सह-लेखन: प्रतीक दत्ता, मेहताब हंस, मयंक मिश्रा, इला पटनायक, प्रशांत रेगी, शुभो राय, संहिता सपतनेकर, अशोक पाल सिंह एवं सोमाशेखर सुन्दरेसन), 2019 "हाउ टू मोर्डनाइज द वर्किंग ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया_", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपीसं 258

रेणुका साने

(सह-लेखन: ऋषभ बेली, स्मृति परिशरा, फैजा रहमान), 2018 "डिस्कलोजर्स इन प्राइवेट पालिसिज : इज ''नोटिस एंड कांसेन्ट'' वक्र?", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 246

रेणुका साने, 2019 द वे फारवर्ड फार पर्सनल इनसोलवेंसी इन द इंडियन सोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 251

_____, 2018 "स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इन द आफ्टरमैथ ऑफ एन एकाउंटिंग स्कैंडल", एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 198

अमेय सप्रे

(सह-लेखन: आर नागराज, तथा राजेश्वरी सेनगुप्ता), 2019 फोर ईयर्स आफ्टर द बेस ईयर रिविजन : टेकिंग स्टाक ऑफ द डिबेट सराउंडिंग इंडियाज नेशनल इंकम एस्टीमेट्स, *इंडिया पालिसी फोरम,*जुलाई 8

(सह-लेखन: राधिका पांडे एवंप्रमोद सिन्हा), 2019 वट डू वी न्यू एबाउट चेंजिंग इकॉनोमिक एक्टीविटिज ऑफफर्म्स?,स्ट्डीज इन माइक्रोइकोनॉमिक्स, सेग पब्लिकेशनंस, आगामी

(सह-लेखन: प्रमोद सिन्हा), 2019"प्राइवेट फाइनेल कंजमप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन हंडिया : एस्टीमेट्स : इश्यूज एंड चैलेंजिस'', कांफ्रेस प्रोसिडिंग्स आन स्टेट लेवल एस्टीमेशन ऑफ जीडीपी, *जरनल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ पोल्टिकल इकॉनोमी,* 30(3&4), जुलाई-दिसम्बर

(सह-लेखन: राधिका पांडे एवंप्रमोद सिन्हा), 2018, "वट डज द न्यू 2011-12 आईआईपी सीरिज टैल एबाउट द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर''?*इंडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यू 11(2)*

_____, 2018 द चैलेंज ऑफ आइडेंटिफाइंग इकानोमिक एक्टीविटिज ऑफ फर्म्स, आइडिया फार इंडिया, अगस्त 23

शताद्रू सिकदर

"पब्लिक प्रोविजनिंग फार सैकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया: ए सिचुएशन एस्सेसमेंट", (प्रवीण झा के साथ), कांफ्रेस वाल्युम, सम्पादन जेबीजी तिलक (आगामी)

श्रुति त्रिपाठी

(सह-लेखन: रूद्राणी भट्टाचार्य, एवंसहाना राय चौधरी), 2019 "फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड मौनेट्री पालिसी ट्रांसमिशन: ए मेटा-एनालिजिज" एनआईपीएफपी डब्ल्यूपी 274

सुरांजली टंडन

"एस्सेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रुमेंट" फाउंडेशन फार इंटरनेशनल टैक्सेशन फ़ैलो शिप 2018 के लिए चयनित तथा टैक्समैन में प्रकाशित

अनुलग्नक VII

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार स्टाफ सदस्यों की सूची

संकाय

1. डा. विजय केलकर	अध्यक्ष
2. श्री सुमित बोस	उपाध्यक्ष
3. डा. रथिन राय	निदेशक
4. डा. सुदिप्तो मंडल	अवकाश प्राप्त प्रोफेसर (9.10.2018 को कार्यकाल समाप्त
5. डा. एम.जी.राव	अवकाश प्राप्त प्रोफेसर (9.11.2018 को कार्यकाल समाप्त)
6. डा. (सुश्री) रीता पांडे	प्रोफेसर (28.2.2019 को सेवानिवृत्त)
7. डा. (सुश्री) आर.कविता राव	प्रोफेसर
8. डा.(सुश्री) इला पटनायक	प्रोफेसर
9. डा. अजय शाह	प्रोफेसर
10. डा. पिनाकी चक्रबर्ती	प्रोफेसर
11. डा.एन.आर.भानुमूर्ति	प्रोफेसर
12. डा. प्रताप रंजन जेना	एसोसिएट प्रोफेसर
13. डा.(सुश्री) लेखा एस. चक्रबर्ती	एसोसिएट प्रोफेसर
14. डा.(सुश्री) मीता चौधरी	एसोसिएट प्रोफेसर
15. डा.सच्चिदानंद मुखर्जी	एसोसिएट प्रोफेसर
16. डा. मुकेश कुमार आनन्द	एसोसिएट प्रोफेसर
17. डा. एच.के.अमरनाथ	एसोसिएट प्रोफेसर
18. डा. रेणुका साने	एसोसिएट प्रोफेसर
19. डा. मनीष गुप्ता	सहायक प्रोफेसर
20. डा.रूद्राणी भट्टाचार्य	सहायक प्रोफेसर
21. डा. सुदर्शन कुमार	सहायक प्रोफेसर (धारणाधिकार पर)
22. डा. भारती भूषण दास	सहायक प्रोफेसर (अवकाश पर)
23. डा. सुकन्या बोस	सहायक प्रोफेसर
24. डा. सुरांजली टंडन	सहायक प्रोफेसर (16.7.2018 को कार्यभार ग्रहण)
25. डा. अमेय सप्रे	सहायक प्रोफेसर (20.7.2018 को कार्यभार ग्रहण)
26. डा. श्रुति त्रिपाठी	अर्थशास्त्री
27. डा. दिनेश कुमार नायक	अर्थशास्त्री
28. डा. ए.श्री हरी नायुडु	अर्थशास्त्री
29. डा. भाबेश हजारिका	अर्थशास्त्री
30. डा. रंजन कुमार मोहंती	अर्थशास्त्री
31. सुश्री अमनदीप कौर	अर्थशास्त्री

प्रशासनिक स्टाफ

1. सुश्री अलका माट्टा	सचिव
2. श्री अरूणोदय कुमार	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (1.12.2016 से 9.7.2018)

3. श्री अशोक कुमार खंडूरी	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (1.8.2018 को कार्यभार ग्रहण)
4. सुश्री समरीन बद्र	सम्पादक
5. श्री एस.सी.शर्मा	होस्टल प्रबंधक (31.5.2018 को सेवानिवृत्त)
6. श्री भास्कर मुखर्जी	कार्यकारी अधिकारी(प्रशासन) (31.8.2018 को सेवानिवृत्त)
7. श्री प्रवीण कुमार	निजी सचिव
8. श्री विक्रम सिंह चौहान	निजी सचिव
9. श्री परविन्द्र कपूर	निजी सचिव
10. श्री शताद्रू सिकदर	अनुसंधान एसोसिएट
11. श्री बी.एस.राव	लेखा अधिकारी
12. सुश्री प्रोमिला राजवंशी	आशुलिपिक ग्रेड.I
13. सुश्री कविता इस्सर	आशुलिपिक ग्रेड.I
14. सुश्री इन्दरा हस्सिजा	सहायक
15. श्री जे.एस.रावत	सहायक
16. सुश्री रूचि आनन्द	सहायक
17. श्री अनुरोधशर्मा	आशुलिपिक ग्रेड.II
18. श्री दर्शन सिंह पंवार	आशुलिपिक ग्रेड.II
19. सुश्री अमिता मनहास	आशुलिपिक ग्रेड.II
20. श्री कपिल कुमार आहूजा	आशुलिपिक ग्रेड.II
21. सुश्री उषा माथुर	स्टैनो-टाइपिस्ट
22. श्री आर.सुन्दरेसन	स्टैनो-टाइपिस्ट (30.4.2018 को सेवानिवृत्त)
23. श्री वसीम अहमद	स्टैनो-टाइपिस्ट
24. सुश्री दीपिका राय	लिपिक (वित्त)
25. श्री शुभम कुमार वर्मा	लिपिक (वित्त)
26. सुश्री मोनिका माथुर	स्वागत अधिकारी एवं टेलीफोन आपरेटर
27. श्री राजू	ड्राइवर
28. श्री परशु राम तिवारी	ड्राइवर
29. श्री मोहन सिंह बिष्ट	फोटोकापी आपरेटर
30. श्री के.एन. मिश्रा	होस्टल अटैंडेंट
31. श्री किशन सिंह	होस्टल अटैंडेंट
32. श्री शिव बहादुर	माली
33. श्री शिव प्रताप	माली
34. श्री रमेश कुमार	माली
35. सुश्री कमला तिवारी	मैसेंजर
36. श्री हरीश चन्द	मैसेंजर
37. श्री अजय कुमार	मैसेंजर
38. श्री मुकेश	मैसेंजर
39. श्री राजेन्द्र कुमार	मैसेंजर
40. श्री बिशम्बर पांडे	वॉचमैन
41. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	वॉचमैन

कम्प्यूटर यूनिट

1. श्री एन.के. सिंह	ईडीपी प्रबंधक
2. श्री जगदीश आर्य	अनुसंधान अधिकारी (संचार)

3. श्री रोबी थामस	अधीक्षक

पुस्तकालय स्टाफ

1. डा. मौहम्मद आसिफ मुस्तफा खान	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2. श्री शिवा चिदाम्बरम	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
(प्रतिनियुक्ति पर)	
3. सुश्री सारिका गौड़	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
4. श्री पी.सी.उपाध्याय	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
5. सुश्री मन्जू ठाकुर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
6. सुश्री आजाद कौर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
7. श्री राजन ढाका	वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक
8. श्री नदीम अली	कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक
9. श्री पूर्ण सिंह	मैसेंजर

<u>अकादमिक स्टाफ</u>
संविदारत

1. श्री डी.पी.सेनगुप्ता	फ़ैलो -I
2. श्री सुयश राय	फ़ैलो -II (9.9.2011 से 1.3.2019)
3. श्री शुभो राय	फ़ैलो -I
4. डा. राधिका पांडे	फ़ैलो -I
5. सुश्री वृंदा भंडारी	फ्रीलांस सलाहकार (22.8.2016 से 21.8.2018)
6. श्री प्रमोद सिन्हा	फ़ैलो -II
7. श्री अनिरूद्ध बर्मन	परामर्शदाता (1.8.2016 से 30.11.2018)
8. श्री फड़नीस रामाराव सुरेश	फ्रीलांस सलाहकार (10.8.2015 से 9.8.2018)
9. सुश्री सुरांजली टंडन	परामर्शदाता (3.5.2011से 15.7.2018)
10. सुश्री संहिता सपतनेकर	परामर्शदाता (5.5.2014 से 5.7.2018)
11. सुश्री रचना शर्मा	फ़ैलो -II
12. सुश्री स्मृतिशर्मा	परामर्शदाता (16.6.2014 से 5.4.2018)
13. श्री आशिष अग्रवाल	परामर्शदाता (9.3.2015 से 27.6.2018)
14. सुश्री शैफाली मलहौत्रा	अनुसंधान फ़ैलो (23.3.2015 से 16.1.2019)
15. श्री जय देव दुबे	फ़ैलो -II
16. सुश्री शिवांगी त्यागी	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 9.4.2018)
17. सुश्री स्मृति परिशरा	फ़ैलो -II
18. श्री सुमंत प्रशांत	विधिपरामर्शदाता (1.11.2015 से 5.7.2018)
19. सुश्री ऋचा जैन	परामर्शदाता (2.8.2018 से 4.9.2018) जेपीए (2.8.2016 से 1.8.2018)
20. श्री शेखर हरी कुमार	फ्रीलांस सलाहकार (8.8.2016 से 31.8.2018)
21. सुश्री नेल्सन चौधरी	अनुसंधान फ़ैलो
22. श्री दीवान चन्द	फ़ैलो -II
23. सुश्री शालिनी मित्तल	अनुसंधान फ़ैलो

24.	श्री प्रियंता घोष	परामर्शदाता (5.7.2017 से 19.12.2018)
25.	सुश्री मान्या नय्यर	परामर्शदाता (1.09.2016 से 27.04.2018)
26.	श्री देवेन्द्र डामले	अनुसंधान फ़ैलो
27.	श्री अशिम कपूर	अनुसंधान फ़ैलो
28.	सुश्री फैजा रहमान	अनुसंधान फ़ैलो
29.	सुश्री हरलीन कौर	अनुसंधान फ़ैलो
30.	श्री प्रतीक दत्ता	फ़ैलो -II (कार्यभार ग्रहण: 1.8.2018)
31.	श्री मयंक मिश्रा	अनुसंधान फ़ैलो
32.	सुश्री महिमा गुप्ता	अनुसंधान फ़ैलो (3.7.2017 से 25.1.2019)
33.	श्री विशाल त्रेहान	अनुसंधान फ़ैलो
34.	श्री सुदिप्तो बैनर्जी	अनुसंधान फ़ैलो
35.	श्री समीर पेठे	अनुसंधान फ़ैलो (10.8.2017 से 11.1.2019)
36.	सुश्री बिदिशा मंडल	अनुसंधान फ़ैलो
37.	डा. अमेय सप्रे	परामर्शदाता (4.9.2017 से 18.7.2018)
38.	सुश्री अर्पिताचक्रबर्ती	परामर्शदाता (11.09.2017 से 30.04.2018)
39.	सुश्री भाव्याशर्मा	अनुसंधान फ़ैलो
40.	श्रीमयंक महावर	परामर्शदाता (9.10.2017 से 8.10.2018)
41.	सुश्री जय विप्रा	परामर्शदाता (9.10.2017 से 22.11.2018)
42.	सुश्री सुप्रिया कृष्णन	परामर्शदाता (4.10.2017 से 3.10.2018)
43.	श्री मनप्रीत सिंह	परामर्शदाता (13.11.2017 से 17.8.2018)
44.	सुश्री त्रिशि गोयल	फ्रीलांस सलाहकार
45.	श्री कृष्णा शर्मा	परामर्शदाता (15.12.2017 से 17.8.2018)
46.	सुश्री तानवी ब्राह्मे	अनुसंधान फ़ैलो
47.	सुश्री कणिका गुप्ता	अनुसंधान फ़ैलो
48.	श्री प्रीतम दत्ता	फ़ैलो -II
49.	सुश्री प्रिया	अनुसंधान फ़ैलो
50.	श्री सुमित अग्रवाल	परामर्शदाता (7.03.2018 से 26.11.2018)
51.	श्री राकेश कुमार सिंह	अनुसंधान फ़ैलो
52.	श्री अशोक भाक्कर	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 1.11.2018)
53.	सुश्री प्रिया केशरी	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 1.11.2018)
54.	सुश्री साक्षी सतीजा	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 5.11.2018)
55.	सुश्री राशि मित्तल	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 4.9.2018)
56.	श्री डी.प्रियादर्शनी	फ़ैलो -II (कार्यभार ग्रहण: 14.9.2018)
57.	सुश्री अमृता पिल्लै	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 3.10.2018)
58.	श्री अनमोल राठौड़	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 20.8.2018)
59.	श्री रघुनाथ शेषाद्री	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 8.10.2018)
60.	श्री सुभामोयचक्रबर्ती	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 8.10.2018)
61.	श्री ऋषभ बेली	फ़ैलो -II (कार्यभार ग्रहण: 16.4.2018)
62.	श्री सारंग मोहारिर	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 13.8.2018)
63.	श्री राहुल चक्रबर्ती	अनुसंधान फ़ैलो
64.	सुश्री मनप्रीत कौर	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 27.8.2018)
65.	सुश्री सरविन कौर नन्दा	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 18.7.2018)
66.	श्री अभिषेक सिंह	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 3.7.2018)

67.	श्री रत्नेश	फ़ैलो -I (कार्यभार ग्रहण: 15.6.2018)
68.	सुश्री मधुर मेहता	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 12.11.2018)
69.	श्री मोहम्मद अजरूद्दीन खान	अनुसंधान फ़ैलो
70.	सुश्री शताक्षी गर्ग	परियोजना एसोसिएट (12.4.2017 से 15.10.2018)
71.	श्री सौरभ रस्तोगी	कनिष्ठपरियोजना एसोसिएट(1.08.2017से 31.7.2018)
72.	श्री रूजेल श्रेष्ठ	अनुसंधान फ़ैलो
73.	सुश्री पल्लबी गोगई	परियोजना एसोसिएट (14.09.2017 से 13.9.2018)
74.	श्री शुभम गुप्ता	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 18.6.2018)
75.	सुश्री सुनेत्रा घटक	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 10.1.2019)
76.	श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 28.1.2019)
77.	सुश्री श्रृष्टि शर्मा	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 30.1.2019)
78.	श्री रोहित दत्ता	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 1.2.2019)
79.	श्री पुनीत मिश्रा	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 1.3.2019)
80.	सुश्री मेधा राजू	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 13.3.2019)
81.	श्री कार्तिक सुरेश	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 13.3.2019)
82.	सुश्री मोमिता दास	अनुसंधान फ़ैलो (कार्यभार ग्रहण: 25.3.2019)
83.	डा. सौमित्र घोष	परामर्शदाता (5.4.2018 से 4.9.2018)
84.	सुश्री श्रेया पांडे	परामर्शदाता (25.4.2018 से 22.10.2018)
85.	श्री चिराग आनन्द	आईटी (परामर्शदाता) कार्यभार ग्रहण: 15.12.2018

<u>प्रशासनिक स्टाफ</u>
संविदारत (ठेके पर)

1.	श्री आर.मणि	परामर्शदाता (प्रशासन)
2.	सुश्री लता बालासुब्रामनियन	परामर्शदाता (कार्यक्रम सहायक)
3.	सुश्री मीना	डाटा एंट्री आपरेटर
4.	श्री कौशल पायल	परामर्शदाता (प्रशासन) कार्यभार ग्रहण: 22.5.2018
5.	श्री कुलदीप सिंह	डेटा एंट्री आपरेटर (कार्यभार ग्रहण: 15.5.2018)
6.	सुश्री दीपिका गुप्ता	परामर्शदाता (लेखा) कार्यभार ग्रहण 18.6.2018

अनुलग्नक VIII

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार प्रायोजकों, कारपोरेट, स्थाई एवं साधारण सदस्यों की सूची

क. प्रायोजक सदस्य

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. कर्नाटक
5. केरल
6. महाराष्ट्र
7. उड़ीसा
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल

अन्य

1. एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
2. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स Federation ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
3. इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ख. स्थाई सदस्य – राज्य / संघ शासित प्रदेश

1. अरूणाचल प्रदेश
2. गोवा, दमन एवं दीव
3. हिमाचल प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. मेघालय
6. मणिपुर
7. नागालैंड

ग. साधारण सदस्य – राज्य / संघ शासित प्रदेश

1. हरियाणा
2. त्रिपुरा सरकार

अन्य

1. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
2. मैसर्स 20 सेंचुरी फाइनेंस कारपोरेशन
3. मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड
4. मैसर्स आईसीआर ए लिमिटेड

अनुलग्नक IX

वित्त एवं लेखा

संस्थान के लेखापरीक्षक मैसर्स सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित संस्थान के वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित लेखा विवरण

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
8 , दिव्तीय तल , कृष्णा मार्किट
कालकाजी , नयी दिल्ली 110019
दूरभाष : 011-40590344
ईमेल : skacamail@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
जनरल बॉडी के सभी सदस्य,

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

मत

हमारे द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (इकाई) के अंतर्गत पंजीकृत विनय के वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार संक्षेप सहित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां शामिल हैं।

हमारे मतानुसार, प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2019 की यथास्थिति को इकाई की वित्तीय स्थिति एवं वर्ष के दौरान इसके वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति होती है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

मत का आधार

हमारे द्वारा किया गया लेखापरीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसरण में किया गया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत उल्लेख हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में प्रस्तुत लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में वर्णित है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसरण में हम इकाई से स्वतंत्र हैं तथा हमारे द्वारा अपने अन्य आचार उत्तरदायित्वों का निर्वाह आचार संहिता के अनुरूप किया गया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षण प्रमाण हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन एवं शासी प्रभारियों के उत्तरदायित्व

भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई के इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने के प्रति प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सत्य एवं स्वच्छ स्वरूप में एवं किसी भी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्याकथन, किसी जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनकी प्रस्तुति करने से संबद्ध डिजाइन, आंतरिक नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण किया जाना शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान प्रबंधन सोसायटी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने,गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से संबंद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा इकाईको बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी रखना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं-:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्य परक हों । पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठगांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं ।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना ।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए इकाई की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसीप्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखा परीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परिक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम इकाईकी प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित इंडएएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंडएएस वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को हमने उन मामलों का विवरण भी दिया है जिनका समेकन हमारे द्वारा स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया गया था तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

अन्य अपेक्षाओं की रिपोर्ट

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने, वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

(ii) हमारे मतानुसार, इकाई द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण विधि अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है तथा ऐसा इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है; तथा

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्रतथा आय एवं व्यय लेखा विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 008714सी

हस्ता./-
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
सदस्यता संख्या 077494

यूडीआईएन:19077494एएएएबीएच1047
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30/10/2019

राष्टीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 **मार्च** 2019 को वित्तीय स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

धनराशि रूपए में

	अनुसूची #	31 मार्च 2019 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
कोरप्स/पूंजी निधि तथा देनदारियां			
कोरप्स/पूंजी निधि	1	124,980,947	123,114,019
आरक्षित तथा अधिशेष	2	162,810,714	155,810,714
आस्थगित आय	3	17,442,303	17,782,976
धर्मादा/विनिश्चित निधियां	4	306,795,449	286,685,601
वर्तमान देनदारियां तथा प्रावधान	5	148,817,557	191,851,027
जोड़		**760,846,970**	**775,244,337**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	6	62,226,986	63,128,546
निवेश–धर्मादा/विनिश्चित निधियां	7	340,050,187	384,284,869
निवेश–अन्य	8	161,988,748	209,753,574
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	9	196,581,049	118,077,348
जोड़		**760,846,970**	**775,244,337**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखों के संबंध में टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग हैं ।

राष्टीय लोक वित्त नीति संस्थान की ओर से

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
बी.एस. रावत	अल्का मट्टा	डा. रथिन राय	डा. विजय केलकर
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
सिंह कृष्णा एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 008714–सी
हस्ता./-
कृष्ण कुमार सिंह
भागीदार
एम. नं. 077494
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30/10/2019

यूडीआईएन:19077494AAAABH1047

राष्टीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 **मार्च** 2019 को वित्तीय स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

धनराशि रूपए में

	अनुसूची #	31 मार्च 2019 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
आय			
केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान	10	88,645,450	101,731,390
अकादमिक कार्यकलापों से आय	11	121,679,514	94,473,372
अर्जित ब्याज	12	15,202,870	15,502,982
अन्य आय	13	18,146,342	14,751,291
जोड़		**243,674,176**	**226,459,035**
व्यय			
स्थापना व्यय	14	68,727,375	83,234,026
अकादमिक कार्यकलापों पर व्यय	15	120,371,499	84,472,977
प्रशासनिक व्यय	16	41,323,647	34,407,586
प्रकाशन स्टाक में कमी		53,504	14,255
मूल्यह्रास	6	3,111,531	3,524,178
जोड़		**233,587,556**	**205,653,022**
शेष वर्ष के संबंध में व्यय की तुलना में आय की अधिकता के नाते शेष		10,086,620	20,806,013
घटा : पिछली अवधि की मदें		9,942	70,601
'अपवाद मद – वेतन बकाया		1,209,750	-
कोर्ट केस सेटलमेंट में दी गई राशि (अनुसूची 18 के नोट सं. 3 का संदर्भ देखें)			
व्यय की तुलना में आय की अधिकता		**8,866,928**	**20,735,412**
घटा : अतिरिक्त देनदारी के लिए अंतरित राशि		4,000,000	10,000,000
घटा : साधारण रिजर्व के लिए अंतरित राशि		3,000,000	9,000,000
कोरप्स/पूंजी निधि में ले जाया गया अधिशेष के नाते शेष		**1,866,928**	**1,735,412**
महत्वपूर्ण रेखांकन नीतियां			
लेखों के संबंध में टिप्पणियां	17		
	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग हैं ।
राष्टीय लोक वित्त नीति संस्थान की ओर से

हस्ता./-	**हस्ता./-**	**हस्ता./-**	**हस्ता./-**
बी.एस. रावत	अल्का मट्टा	डा. रथिन राय	डा. विजय केलकर
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
सिंह कृष्णा एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 008714–सी

हस्ता./-
कृष्ण कुमार सिंह
भागीदार
एम. नं. 077494 **यूडीआईएन:**19077494AAAABH1047
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30/10/2019

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

धनराशि रूपए में

		31 मार्च 2019 की स्थिति		31 मार्च 2018 की स्थिति
अनुसूची 1 . कोरप्स/पूंजी निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	123,114,019		121,378,607	
जमा : आय और व्यय खाते से अंतरित अधिशेष	1,866,928		1,735,412	
		124,980,947		123,114,019
जोड़		**124,980,947**		**123,114,019**
अनुसूची-2 : रिजर्व और अधिशेष				
क. अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	58,189,863		48,189,863	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	4,000,000		10,000,000	
		62,189,863		58,189,863
ख. सामान्य रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	97,120,851		88,120,851	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	3,000,000		9,000,000	
		100,120,851		97,120,851
ग. : मृत कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायतार्थ रिजर्व के लिए अंतरित राशि				
पिछले खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि		500,000		500,000
जोड़		**162,810,714**		**155,810,714**
अनुसूची-3 : आस्थगित आय				
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए इमारत के				
निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार से अनुदान				
पिछले खाते के अनुसार	17,127,099		17,386,174	
घटा : ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के समकक्ष राशि				
आय और व्यय खाते को अंतरित	368,683		259,075	
		16,758,416		17,127,099
पूंजी परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रायोजकों से अनुदान				
पिछले खाते के अनुसार	655,877		1,072,381	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	496,034		217,999	
घटा : आय और व्यय खाते को अंतरित ऐसी परिसंपत्तियों पर				
मूल्यह्रास के समकख राशि	468,024		634,503	
		683,887		655,877
जोड़		**17,442,303**		**17,782,976**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र् का भाग है

अनुसूची-4 : विनिश्चित/धर्मादा निधियां

धनराशि रूपयों में

विवरण	फोर्ड फाउंडेशन अक्षय निधि	सरकारी अक्षय निधि	भारतीय रिजर्व बैंक अक्षय निधि	वैज्ञानिक अनुसंधान निधि	आजीवन सदस्यता निधि	बिमल बागची अवार्ड निधि	जोखन मौर्य निधि	सरकारी कोरप्स निधि	राजा चेलैय्या वार्षिक व्याख्यान माला और भ्रमणकारी प्रोफेसरशिप निधि	जोड़
प्रारंभिक निधि	**6,177,924**	**10,000,000**	**40,000,000**	**727,406**	**420,000**	**50,000**	**29,300**	**120,000,000**	**20,000,000**	
क- निधियों का प्रारंभ	15,064,577	10,000,000	57,792,162	2,244,110	1,291,902	96,387	62,566	169,996,822	30,137,075	286,685,601
ख-निधि में अभिवृद्धियां										
|-निधि में अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
||-निवेशों से आय	1,174,631	814,439	4,544,097	162,962	93,578	7,334	4,241	13,012,384	2,239,382	22,053,048
जोड. -क+ख	**16,239,208**	**10,814,439**	**62,336,259**	**2,407,072**	**1,385,480**	**103,721**	**66,807**	**183,009,206**	**32,376,457**	**308,738,649**
ग-निधि के उद्रदेश्य हेतु उपयोग/व्यय	467,232	814,439	154,617	-	-	-	-	506,912	-	1,943,200
जोड. - ग	**467,232**	**814,439**	**154,617**	**-**	**-**	**-**	**-**	**506,912**	**-**	**1,943,200**
वर्ष के अंत में निवल शेष वर्ष का - क+ख+ग	**15,771,976**	**10,000,000**	**62,181,642**	**2,407,072**	**1,385,480**	**103,721**	**66,807**	**182,502,294**	**32,376,457**	**306,795,449**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र का भाग है

धनराशि रूपयों में

#	विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
	अनुसूची-5 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
	क. वर्तमान देयताएं		
1	वस्तुओं और सेवाओं के लिए विविध लेनदार	4,931,724	6,299,089
2	बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	3,216,978	2,530,163
3	परियोजना अनुदान-(देखें अनुसूची-5 - क)	82,708,900	115,405,105
4	केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान (देखें अनुसूची-5-ख)	-	15,068,610
5	सांविधिक देय	5,678,270	5,009,919
6	अन्य वर्तमान देयताएं	15,147,505	15,610,555
	जोड़	**111,683,377**	**159,923,441**
	ख. प्रावधान		
1	छुट्टी नकदीकरण	37,134,180	31,927,586
	जोड़	**37,134,180**	**31,927,586**
	कुल जोड़	**148,817,557**	**191,851,027**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची-5 -क-परियोजना अनुदान

(धनराशि रूपयों में)

	विवरण	1 अप्रैल, 2018 को अप्रयुक्त निधि	1 अप्रैल 2018 को वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति	जोड़	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आय और व्यय/खाते में प्रभारित	प्रयुक्त और आस्थगित आय में प्रभारित	जोड़	31 मार्च, 2019 को वसूली योग्य	31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त
1	एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम- आर्थिक कार्य विभाग-वित्त मंत्रलय, भारत सरकारए 2017-18	-	6,537,090	6,450,211	(86,879)		-	-	86,879	--
2	आर्थिक वैश्वीकरण एवं आर्थिक विकास -आईसीएसएसआर	592,395	-	-	592,395	414,962	-	414,962	-	177,433
3	स्वास्थ्य एवं इसके वित्तीयन के अनुसंधान एवं नीतियों में सुधार – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	34,446,626	-	-	34,446,626	12,606,661	-	12,606,661	-	21,839,965
4	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- स्वास्थ्य एवं इसके वित्तीयन के अनुसंधान एवं नीतियों में सुधार – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	1,375,802	-	1,838,816	3,214,618	-	-	-	-	3,214,618
5	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण – यूएनडीपी	512,553	-	-	512,553	-	-	-	-	512,553
6	डिजीटल लैंड के प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन – एनसीईएआर उप-अनुदान	927,993	-	-	927,993	-	-	-	-	927,993
7	एनआईपीएफपी – ट्राई सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम	42,521	-	-	42,521	-	-	-	-	42,521
8	क्या मौद्रिक नीति से भारत में वित्तीय स्थिरता संभव है- आईसीएसएसआर	253,362	-	320,000	573,362	411,446	-	411,446	-	161,916
9	एनआईपीएफपी – ट्राई सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम II	-	453,878	2,342,996	1,889,118	1,889,118	-	1,889,118	-	-
10	भारत में स्वास्थ्य पर लोक वित्तीयन की पद्धति : आगे की दिशा - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	5,745,284	-	23,832,269	29,577,553	18,998,697	333,784	19,332,481	-	10,245,072
11	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- भारत में स्वास्थ्य पर लोक वित्तीयन की पद्धति : आगे की दिशा - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	499,382	-	821,738	1,321,120	-	-	-	-	1,321,120
12	लोक वित्तीयन पर नवोपायों के परिणाम - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	70,009,267	-	-	70,009,267	38,909,131	162,250	39,071,381	-	30,937,886
13	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- लोक वित्तीयन पर नवोपायों के परिणाम - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	999,920	-	2,739,408	3,739,328	-	-	-	-	3,739,328
14	डेटा रक्षण के लिए सहमति फ्रेमवर्क में सुधार -ओमिदयार नेटवर्क	-	138,787	966,314	827,527	578,592	-	578,592		248,935
15	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण – यूएनडीपी II	-	292,610	3,205,125	2,912,515	2,724,805	-	2,724,805	-	187,710
16	भारत में डिजीटल परिवर्तन के महत्वपूर्ण एवं नव प्रवाहों पर चर्चा के लिए प्लेटफार्म – फ्रिडरिच नौमान्न स्टिफ्टंग	-	-	702,370	702,370	702,370	-	702,370	-	-

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची-5 -क-परियोजना अनुदान

(धनराशि रूपयों में)

	विवरण	1 अप्रैल, 2018 को अप्रयुक्त निधि	1 अप्रैल 2018 को वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति	जोड़	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आय और व्यय/खाते में प्रभारित	प्रयुक्त और आस्थगित आय में प्रभारित	जोड़	31 मार्च, 2019 को वसूली योग्य	31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त
17	प्रभावशाली राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना के संगठनात्मक डिजाइन एवं आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसंधान अध्ययन में सहयोग-ओमिदयार नेटवर्क	-	-	1,515,782	1,515,782	243,415	-	243,415	-	1,272,367
	कुल आगे ले जाया गया	**115,405,105**	**7,422,365**	**44,735,029**	**152,717,769**	**77,479,197**	**496,034**	**77,975,231**	**86,879**	**74,829,417**
18	हिमालय संरक्षण के लिए सहायता सेवा, हिमाचल प्रदेश – यूएनडीपी	-	-	2,561,625	2,561,625	121,289	-	121,289	-	2,440,336
19	हिमालय संरक्षण के लिए सहायता सेवा, सिक्किम– यूएनडीपी	-	-	2,561,625	2,561,625	148,665	-	148,665	-	2,412,960
20	विशेष क्षेत्र अनुसंधान के विशिष्ट मुद्दों पर गृह मंत्रालय के साथ सहयोग कार्यक्रम के संबंध में डिजीटल लाइब्रेरी/दस्तावेज केन्द्र का निर्माण एवं अनुरक्षण – आईसीएसएसआर	-	-	2,000,000	2,000,000	504,457	-	504,457	-	1,495,543
21	एनआईपीएफपी – कारपोरेट कार्य मंत्रालय अनुसंधान कार्यक्रम – कारपोरेट कार्य मंत्रालय			2,500,000	2,500,000	969,356		969,356		1,530,644
22	एनआईपीएफपी-आर्थिक कार्य विभाग अनुसंधान कार्यक्रम आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय,भारत सरकार 2018-19			4,982,361	4,982,361	17,258,238		17,258,238	12,275,877	-
23	एनआईपीएफपी – ट्राई सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम III			8,228,978	8,228,978	9,045,748		9,045,748	816,770	-
24	भारत में स्वास्थ्य पर हाउसहोल्ड व्यय भारतीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)के 71वें राउंड के प्राइमरी डेटा का विश्लेषण-विश्व स्वास्थ्य संगठन	-	-	554,070	554,070	1,036,512	-	1,036,512	482,442	-
	जोड़	**230,810,210**	**14,844,730**	**112,858,717**	**328,824,197**	**184,042,659**	**992,068**	**185,034,727**	**13,748,847**	**157,538,317**

अनुसूची 5–ख–केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान

	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अप्रयुक्त अनुदान का अथशेष	15,068,610	23,912,798
जमा : वर्ष के दौरान वेतन एवं भत्तों के लिए प्राप्त अनुदान	-	71,987,202
वर्ष के दौरान आवर्ती व्यय के लिए प्राप्त अनुदान	-	19,200,000
	15,068,610	**115,100,000**
घटा : वेतन और भत्तों के लिए प्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखे आय के रुप में प्रभारित)	80,945,450	80,831,390
आवर्ती व्ययों का अप्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखे आय के रुप में प्रभारित)	6,000,000	19,200,000
योग . अप्रयुक्त अनुदान ;प्राप्ति योग्यद्ध अनुदान	**(71,876,840)**	**15,068,610**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र् का भाग है

अनुसूची 6 - अचल परिसंपत्तियां

धनराशि रूपयों में

#	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 18 को	अभिवृद्धियां	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 19 को	1 अप्रैल, 18 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 19 तक	31 मार्च 19 को	31 मार्च 18 को
	स्वयं की निधियों में से खरीदी गई अचल परिसंपत्तियां										
1	लीजहोल्ड भूमि	18,809,202	-	-	18,809,202	-	-	-	-	18,809,202	18,809,202
2	भवन	33,233,766	61,950	-	33,295,716	11,394,565	808,404	-	12,202,969	21,092,747	21,839,201
3	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	27,724,246	589,895	1,124,814	27,189,327	25,838,821	1,021,625	1,124,814	25,735,632	1,453,695	1,885,425
4	कार्यालय उपस्कर	9,521,493	728,306	567,722	9,682,077	8,836,650	194,778	567,722	8,463,706	1,218,371	684,843
5	फर्नीचर और सज्जा	11,590,935	100,451	116,334	11,575,052	10,783,817	95,572	116,334	10,763,055	811,997	807,118
6	होस्टल, पुस्तकालय, कंप्यूटर तथा सेमिनार कक्ष, फर्नीचर	3,641,172	-	-	3,641,172	3,637,756	406	-	3,638,162	3,010	3,416
7	एयर कंडीशनर और वाटर कूलर	6,411,917	168,293	27,985	6,552,225	5,723,954	82,256	27,985	5,778,225	774,000	687,963
8	विद्युत संस्थापन	6,847,114	65,042	141,662	6,770,494	6,218,714	71,783	141,662	6,148,835	621,659	628,400
9	वाहन	1,205,374	-	-	1,205,374	1,205,372	-	-	1,205,372	2	2
10	बागवानी उपस्कार	109,780	-	-	109,780	109,780	-	-	109,780	-	-
	जोड़	**119,094,999**	**1,713,937**	**1,978,517**	**118,830,419**	**73,749,429**	**2,274,824**	**1,978,517**	**74,045,736**	**44,784,683**	**45,345,570**
	केंद्रीय सरकार से अनुदान में से अधिप्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1	इमारत-अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	21,289,579	-	-	21,289,579	4,162,480	368,683	-	4,531,163	16,758,416	17,127,099
2	विद्युतीय, अग्नि-शमन और एचवीएसी कार्य-अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	7,298,350	-		7,298,350	7,298,350	-	-	7,298,350	-	-
		28,587,929	**-**	**-**	**28,587,929**	**11,460,830**	**368,683**	**-**	**11,829,513**	**16,758,416**	**17,127,099**
	विभिन्न प्रायोजको से सरकार से अनुदान में से अधिप्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	4,156,385	-	-	4,156,385	3,801,451	222,917	-	4,024,368	132,017	354,934
2	कार्यालय उपस्कर	216,380	-	-	216,380	161,236	18,919	-	180,155	36,225	55,144
3	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-आईसीएसएसआर	51,500	-	-	51,500	6,657	16,308	-	22,965	28,535	44,843
		4,424,265	**-**	**-**	**4,424,265**	**3,969,344**	**258,144**	**-**	**4,227,488**	**196,777**	**454,921**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र् का भाग है

अनुसूची 6 - अचल परिसंपतियां

धनराशि रूपयों में

#	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 18 को	अभिवृद्धियां	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 19 को	1 अप्रैल, 18 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 19 तक	31 मार्च 19 को	31 मार्च 18 को
	विदेशी अंशदान निधियों में से प्राप्त अचल परिसंपतियां										
1	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	9,880	-	-	9,880	9,880	-	-	9,880	-	9,880
2	फर्नीचर और सज्जा	1,523,860	-	-	1,523,860	1,523,860	-	-	1,523,860	-	1,523,860
3	बागवानी उपस्कर	624,980	-	-	624,980	624,980	-	-	624,980	-	624,980
	जोड़	**2,158,720**	**-**	**-**	**2,158,720**	**2,158,720**	**-**	**-**	**2,158,720**	**-**	**-**
	विदेशी अंशदान निधियों में से प्राप्त अचल परिसंपतियां										
1	आंकडा प्रसंस्करण उपस्कर-आईडीआरसी	154,571	-	-	154,571	99,183	47,659	-	146,842	7,729	55,388
2	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-बीएमजीएफ-‖	144,499	333,784	-	478,283	16,854	119,894	-	136,748	341,535	127,645
3	कार्यालय उपस्कर-एनसीईएआर-उप ग्राण्ट-‖‖	22,000	-	-	22,000	4,077	4,180	-	8,257	13,743	17,923
4	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-बीएमजीएफ-‖‖	-	162,250	-	162,250	-	38,147	-	38,147	124,103	-
	जोड़	**321,070**	**496,034**	**-**	**817,104**	**120,114**	**209,880**	**-**	**329,994**	**487,110**	**200,956**
	कुल जोड़	**154,586,983**	**2,209,971**	**1,978,517**	**154,818,437**	**91,458,437**	**3,111,531**	**1,978,517**	**92,591,451**	**62,226,986**	**63,128,546**
	पिछला वर्ष	**151,465,819**	**4,019,728**	**898,564**	**154,586,983**	**88,758,851**	**3,524,178**	**824,592**	**91,458,437**	**63,128,546**	**-**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन–पत्र का भाग है

धनराशि रूपयों में

#	विवरण	31 मार्च 19 को		31 मार्च 18 को	
	अनुसूची-7 : निवेश-धर्मादा/विनिश्चित निधियां				
	दीर्धावधि निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियों में	88,513,079		85,413,079	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	181,766,168		160,710,723	
	वर्तमान निवेश				
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	69,770,940		138,161,067	
	जोड़	**340,050,187**		**384,284,869**	
	अनुसूची-8 : निवेश - अन्य				
	दीर्धावधि निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियों में	65,010,000		106,830,963	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	92,400,963		52,537,268	
	वर्तमान निवेश				
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,504,363		50,316,500	
	प्रतिभूति जमा के विरूद्घ अनुसूचित बैंक के पास सावधि जमा	73,422		68,843	
	जोड़	**161,988,748**		**209,753,574**	
	अनुसूची-9 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
क.	**वर्तमान संपत्ति**				
	1. इनवेंटरीज				
	प्रकाशनों का भंडार		90,937		144,441
	2. विविध देनदार		270,988		94,538
	3. हाथ में नकद शेष -चेक/अप्रदाय सहित		40,054		23,897
	4. बैंक शेष				
	अनुसूचित बैंकों के पास - बचत खाता				
	केनरा बैंक, जीत सिंह मार्ग, खाता संख्या 1484101001555	17,561,482		37,822,475	
	केनरा बैंक, जीत सिंह मार्ग, खाता संख्या 1484106026094	4,966		4,966	
	स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू खाता सं. 10596549875	17,106		16,520	
	अनुसूचित बैंकों के पास-चालू खाता				
	स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू, एफसी खाता सं. 10596547368	19,153,495		7,912,417	
	स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू चालू खाता सं. 10596547335	43,956		44,605	
			36,781,005		45,800,983
ख	**ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां,**				
	1. अग्रिम व अन्य राशि-नकद अथवा समान अथवा				
ख.	**प्राप्त होने वाली कीमत के रूप में वसूली योग्य:**				
	क. स्टाफ को उत्सव अग्रिम	22,900		28,300	
	ख. पूर्वप्रदत्त व्यय	9,364,173		8,242,854	
	ग. व्यय के लिए स्टाफ को अग्रिम	555,364		299,490	
	घ. अन्य अग्रिम	2,126,145		464,854	
	ड.. प्रतिभूति जमा	772,788		772,788	
	च. इनपुट कर क्रेडिट (आस्थगित)	-		421,373	
	छ. इनपुट कर क्रेडिट	44,980		22,561	
			12,886,350		10,252,220

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन–पत्र का भाग है

धनराशि रूपयों में

#	विवरण		31 मार्च 19 को		31 मार्च 18 को
	2. उपार्जित आय				
	क. विनिश्चित/धर्मादा निधियों में निवेशों पर आय	2,868,603		4,657,699	
	ख. निवेशों पर - अन्य	1,522,175		3,302,972	
	ग. राज्य सरकार अनुदान	500,000		-	
	घ. पाठ्यक्रम कार्यक्रम और परियोजना आय	11,880,645		8,916,681	
	ड. परियोजना अनुदान (अनुसूची 5 (क) देखें)	13,661,968		7,422,365	
	च. केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान (अनुसूची 5 (ख) देखें)	**71,876,840**		-	
		-	102,310,231	-	24,299,717
	3. प्राप्ति योग्य दावे			-	-
क	आय कर वसूली योग्य		44,201,484		37,461,552
	जोड़		**196,581,049**		**118,077,348**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो आय और व्यय खाते का भाग हैं

धनराशि रूपयों में

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति	31 मार्च, 2018 की स्थिति
अनुसूची-10 : केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान		
क. केंद्रीय सरकार से अनुदान		
वेतन अनुदान - देखें अनुसूची 5-ख	80,945,450	80,831,390
आवर्ती अनुदान-देखें अनुसूची 5-ख	6,000,000	19,200,000
जोड़-क	**86,945,450**	**100,031,390**
ख. राज्य सरकारों से अनुदान		
सामान्य सहायता अनुदान		
उड़ीसा सरकार	500,000	500,000
महाराष्ट्र सरकार	100,000	100,000
तमिलनाडु सरकार	100,000	100,000
नागालैंड सरकार	500,000	500,000
गुजरात सरकार	500,000	500,000
जोड़-ख	**1,700,000**	**1,700,000**
कुल जोड़-क+ख	**88,645,450**	**101,731,390**
अनुसूची-11 : अकादमिक कार्यकलापों से आय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय	15,116,052	19,012,981
प्रयुक्त सीमा तक परियोजना अनुदान - सदंर्भ अनुसूची 5-क	106,563,462	75,460,391
जोड	**121,679,514**	**94,473,372**
अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज		
बैंको/वित्तीय संस्थाओं से अर्जित ब्याज		
अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा पर	1,992,188	7,582,225
अनुसूचित बैंकों के पास बचत खातों पर	483,922	347,440
सरकारी व अन्य प्रतिभूतियों पर	12,648,977	7,408,130
आयकर वापसी पर ब्याज	-	125,625
अन्य ब्याज	77,783	39,562
जोड	**15,202,870**	**15,502,982**
अनुसूची-13 : अन्य आय		
प्रकाशनों की बिक्री	-	583
वसूलियां	16,734,897	11,299,028
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ	71,319	-
विविध आय	115,824	377,519
मकान किराया वसूलियां	175,837	143,019
रा.जो.वि.नी.सं. स्टाफ से प्राप्त परामर्श फीस	66,630	126,883
देनदारियां बट्टे खाते डाली गई	83,717	1,910,574
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	61,411	107
आस्थगित आय से अंतरित राशि (अनुसूची 3 देखें)	836,707	893,578
जोड	**18,146,342**	**14,751,291**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो आय और व्यय खाते का भाग हैं

धनराशि रूपयों में

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
अनुसूची-14 : स्थापना व्यय		
वेतन और भत्ते	73,618,153.00	72,976,883
बोनस	276,320.00	279,198
पीएफ व पेंशन निधि के लिए अंशदान	7,543,158.00	7,436,203
उपदान	5,087,313.00	7,465,380
छुट्टी वेतन	7,679,191.00	3,240,287
स्टाफ लाभ तथा कल्याण	4,601,304.00	4,169,064
ईडीएलआई तथा प्रशासनिक प्रभार	179,490.00	180,842
परामर्श फीस	1,339,918.00	3,935,230
	100,324,847.00	**99,683,087**
घटा : अकादमिक कार्यकलापों को प्रभारित	31,597,472.00	16,449,061
जोड़	**68,727,375.00**	**83,234,026**
अनुसूची-15 : अकादमिक कार्यकलापों पर व्यय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना खर्च	13,808,037	9,012,586
परियोजना अनुदान का उपयोग-अनुसूची 5-क देखें	106,563,462	75,460,391
जोड़	**120,371,499**	**84,472,977**
अनुसूची-16 : प्रशासनिक व्यय		
यात्रा और सवारी	1,861,234	1,138,033
दरें और कर	2,147,019	1,451,823
विद्युत प्रभार	7,701,241	6,429,445
जल प्रभार	940,124	824,632
मुद्रण और लेखन सामग्री	955,218	927,574
टेलीफोन और डाकखर्च	1,525,392	1,578,063
मरम्मत और अनुरक्षण	12,531,239	10,941,578
कार संचालन और अनुरक्षण	373,483	374,634
आडिट फीस	332,462	275,000
ऑडिट फीस-आंतरिक	142,691	120,600
आडिट फीस-पीएफ ट्रस्ट	18,000	16,500
आडिट फीस-उपदान ट्रस्ट	24,624	19,033
विविध व्यय	381,861	274,320
विधिक व्यय	494,295	483,740
विज्ञापन पर व्यय	186,733	37,445
पीएफ की परिपक्वता/उपदान न्यास निवेश पर हानि	937,167	-
ब्याज की कमी और अन्य व्यय (पीएफ निधि)	246,378	-
संपत्ति के निपटारे पर हानि	-	61,233
पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	9,370,251	6,752,008
प्रकाशनों की लागत	317,244	288,401
बैठक और सेमिनार	213,406	275,061
साधारण/शासी निकाय बैठक	118,643	194,409
बीमा व्यय	113,379	91,678
वसूली योग्य-बट्टे खाते डाला गया	958,746	2,458,738
व्यावसायिक फीस	157,256	148,620
पचीसवीं वर्षगांठ पर व्यय	90,000	60,000
	42,138,086	35,222,568
घटा : धर्मादा/विनिश्चित निधियों के लिए प्रभारित	814,439	814,982
जोड़	**41,323,647**	**34,407,586**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 17–लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों का निर्माण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक अभिसमय के अधीन उपचय आधार पर और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखाकरण मानकों, यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, के अनुसार किया जाता है। सामान्य सदस्यता शुल्क को नकद आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

2. वित्तीय विवरणिकाएं तैयार करने के लिए ऐसे प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों की अपेक्षा होती है जिनसे प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों,राजस्व और व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित होती है। यद्यपि ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी भिन्नताओं को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें परिणाम परिणत होते हैं।

3. दीर्घावधिक निवेशों को ह्रास, अस्थाई के अलावा, के समायोजन के पश्चात उनकी वहन लागत पर अग्रेनित किया जाता है। चालू निवेश लागत और उचित मूल्य में से न्यूनतर के आधार पर अग्रेनित किए जाते हैं। निवेशों की लागत में, यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रीमियम सहित सभी अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

   भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई चेयर ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए दी गई काय निधि में से प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों, जब इन्हें प्रीमियम पर अधिग्रहीत किया गया हो, का उल्लेख आरबीआई और संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार आरबीआई काय निधि से उपार्जित ब्याज आय के सापेक्ष किया गया है।

4. प्रकाशनों की मालसूची का मूल्यांकन लागत पर किया गया है। लागत का निर्धारण एफआईएफओ आधार पर किया गया है। दस वर्ष से अधिक पुराने प्रकाशन और परियोजना अनुदानों से वित्तपोषित प्रकाशनों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है।

5. अचल परिसम्पत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया गया है जिसमें अधिग्रहण से संबंधित आनुशंगिक और प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल हैं। अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया गया है।

6. प्रबंधन द्वारा पाँच प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य पर विचार के पश्चात परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर सरल रेखा पद्धति से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। परिसम्पत्तियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है:-

परिसम्पति विवरण	उपयोज्यता
भवन	60 वर्ष
डेटा संसाधन उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्निचर एवं जुड़नार	10 वर्ष
होस्टल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	8 वर्ष
एयर कंडीनर एवं वाटर कूलर	10 वर्ष
विद्युत संस्थापनाएं	10 वर्ष

वाहन	8 वर्ष
बागवानी उपकरण	5 वर्ष

7. प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से किसी परिसम्पत्ति का क्षय होने के संबंध में आकलन किए जाते हैं। ऐसे क्षय के किसी संकेत के मामले में, प्रबंधन परिसम्पत्ति द्वारा वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी वाहित राशि से कम है, तो परिसम्पत्ति की वाहित राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और अंतर को अक्षमता हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

8. पुस्तकालय के लिए खरीदी गई पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीद के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. अल्पावधिक कर्मचारी लाभों को आय एवं व्यय के लेखे में छूट न दी गई राशि के व्यय के रूप में सेवाएं प्रदान किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया गया है।

10. रोजगार के बाद के और अन्य दीर्घावधिक लाभों को उस वर्ष के आय व्यय लेखे में छूट न दी गई राशि पर हुए व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए निर्धारित देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर स्वीकृति दी गई है। रोजगार-पश्चात और अन्य दीर्घावधिक लाभों के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को सामान्यतः संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखा पुस्तिकाओं में लेखाबद्ध किया गया है।

12. चिह्नित/वृत्ति निधियों से निवेशों पर आय का उपयोग निधियों के विनिर्दिष्ट उद्देष्यों के लिए किया गया है। अप्रयुक्त राशि के शेष को, यदि कोई हो, संबंधित चिह्नित/वृत्ति निधियों में रखा गया है।

13. विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभिक तौर पर देनदारी माना गया है और वर्ष के दौरान उपयोगिता के अुनसार समायोजित किया गया है। अनुदानों को, मूल्यह्रास के योग्य परिसम्पत्तियों के लिए प्रयुक्त सीमा तक, आस्थगित आय माना गया है और इन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक आधार पर आय और व्यय लेखे में स्वीकृति दी गई है। राजस्व व्ययों के लिए प्रयुक्त सीमा तक वेतनों और परियोजना अनुदानों को वर्ष की आय माना गया है। आवर्ती व्ययों के लिए अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

14. प्रावधानों को वहां स्वीकृति दी गई है जब विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देनदारी हो तथा जिसके लिए यह संभव हो कि देनदारी के समाधान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा और विश्वसनीय प्राक्कलन संभव हो सकेगा। देनदारी के समाधान के लिए अपेक्षित प्रावधानों की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और जहां देनदारी के चालू सर्वोत्तम प्राक्कलन के लिए आवश्यक हो, समायोजित किया गया है।

15. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया गया है जब एक संभावित देनदारी या वर्तमान देनदारी हो जिसके लिए संसाधनों का वह बर्हिप्रवाह अपेक्षित हो सकता हो, जो संभावित रूप से अपेक्षित नहीं है। उस वर्तमान देनदारी के संबंध में भी प्रकटीकरण किया जाएगा जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित हो, जहां संबंधित बर्हिप्रवाह का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जाना संभव न हो।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 – लेखांकन नोट

1. आकस्मिक देयताएं / परिसम्पतियां

   संस्थान के विरूद्ध एवं संस्थान द्वारा दायर किए न्यायिक मामलों के संबंध में देयता : राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं : शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)

3. केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बैंच, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 4 मार्च, 2011 तथा 14 दिसम्बर, 2018 के क्रमश: न्यायनिर्णय एवं आदेश के अनुसरण के परिणामस्वरूप श्रीमती सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी को पूर्व प्रभाव से केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बैंच के न्यायनिर्णय एवं आदेश में उल्लिखित वेतनमान / वित्तीय उन्नयन प्रदान किए गए थे जिससे उनकी देयताओं के प्रति उन्हें 12,09,750 रूपए की राशि का भुगतान किया गया था।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संज्ञान की गई एवं एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के खंड 22 में अनुपालन में संस्थान में उपलब्ध देयताएं :

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को चुकता न की गई मूल राशि	8,41,677	5,95,206
वर्ष के दौरान ब्याज उपचय की राशि तथा वर्ष के अंत में चुकता न की गई बकाया राशि	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदात्ता को खंड 16 के उपबंधों के अनुसार भुगतान की राशि के साथ चुकता किए गए ब्याज की राशि	-	-
भुगतान किए जाने में देरी की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता किया गया है) जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना चुकता किया गया है।	-	-
वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उससे संबंधित चुकता न किया गया बकाया ब्याज	-	-
आगामी वर्षों में भुगतान न किए जाने के कारण देय बढ़त ब्याज की राशि जो वास्तविक भुगतान किए जाने की तिथि तक के लिए खंड 23 के अंतर्गत कटौती व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को चुकता की जानी है।	-	-

5. संस्थान के प्रबंधन के मतानुसार, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कारोबार के सामान्य क्रम में कम से

उस राशि के समान है जिस पर इनका उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो और सभी ज्ञात देयताओं के लए प्रावधान वित्तीय विवरणिका में किया गया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल 4,42,01,485 रूपए के वसूली योग्य आयकर में से 1,37,33,202 रूपए की राशि आयकर वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व के आकलन वर्षों से संबंधित है।

6. वृत्ति/चिह्नित निधियों के निवेशों में 5,49,49,920 रूपए के उद्धृत निवेश और 28,51,00,267 रूपए के अनुद्धृत निवेशशामिल हैं। उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य रूपए 5,75,75,094है।
अन्य निधियों में 16,19,88,748 रूपए की राशि का निवेश अनुद्धृत निवेश है।

7. वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त परिभाषित अंशदायी योजना का विवरण निम्नानुसार है:

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान रु.65,27,159(पिछले वर्ष रु.63,75,843)
पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान रु.10,15,999(पिछले वर्ष रु.10,60,360)

एक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है। देनदारी के वर्तमान मूल्य का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के रूप में स्वीकृत किया गया है और अंतिम देनदारी निर्मित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा गया है। छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी को इसी तरीके से ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत किया गया है।

तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मूल बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नानुसार हैः

क)आर्थिक अनुमान

मूल पूर्वानुमान इस प्रकार हैं (1) छूट की दर (2) वेतन वृद्धि। छूट वृद्धि लेखाकरण तिथि को सरकारी बंधपत्रों पर उपलब्ध बाजार अर्जन पर उस शर्त पर आधारित है जो देयताओं की शर्तों से मिलती हों और वेतन वृद्धि में मूल्यवृद्धि, वरिष्ठता, प्रोन्नति और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, अक्षमता के लिए कोई सुस्पष्ट भत्ते का उपयोग नहीं किया गया है।

		31-मार्च-2019	**31-मार्च-2018**
i)	छूट की दर	7.75%प्र.व.	7.75%प्र.व.
ii)	भावी वेतन वृद्धि	9.50%प्र.व.	8.50%प्र.व.
iii)	ग्रेच्युटी के लिए योजना परिसम्पतियों की प्रत्याशित प्रतिफल दर (वित्त पोषित)	7.75%प्र.व.	7.75%प्र.व.
जनसांख्यिकी अनुमान			
		31-मार्च -2019	**31-मार्च-2018**
i)	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
ii)	मृत्यु सारणी	आईएएलएम 2006-08	आईएएलएम 2006-08
		अल्टीमेट	अल्टीमेट
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	6.50%	6.50%

8. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी इन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक हो, पुनर्निर्मित, पुनप्रतिशत समूहबद्ध, पुनः व्यवस्थित और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

कृते राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(बी.एस.रावत)	(अलका माट्टा)	(डा.रथिन राय)	(डा. विजय केलकर)
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

समान तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008714सी

हस्ता./-
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं.077494

यूडीआईएन: 19077494AAAABH1047

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 30/10/2019

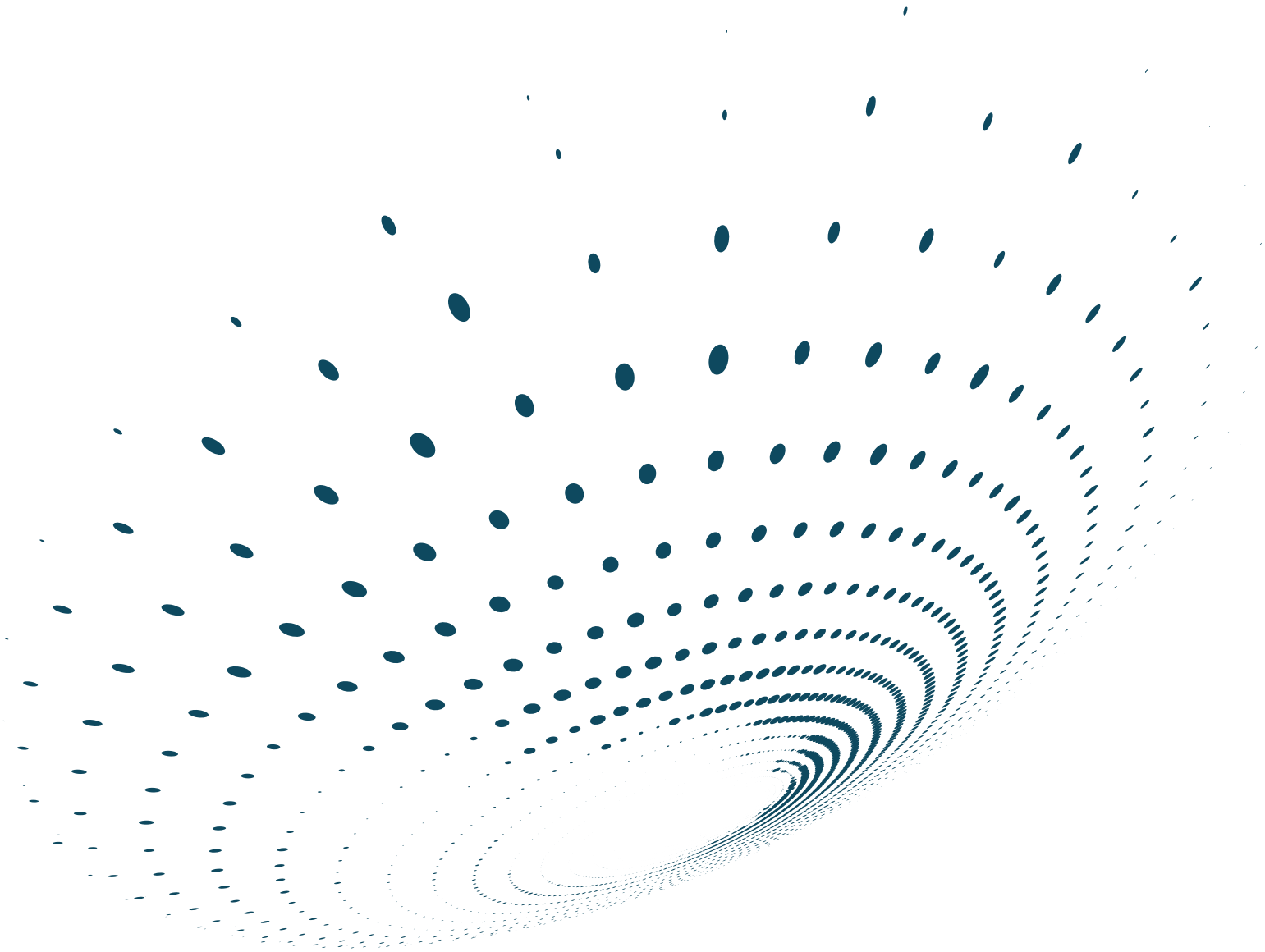

18/2, सत्संग विहार मार्ग,
स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू)
नई दिल्ली 110067
दूरभाष: 011 26569303, 26569780, 26569784
फैक्स : 91-11-26852548
ईमेल : nipfp@nipfp.org.in
वेबसाइट: www.nipfp.org.in

Tel. No. 26569303, 26569780, 26569784
Fax: 91-11-26852548
www.nipfp.org.in